केरल शिक्षा विधेयक, 1957 में।

अनुच्छेद 143 (1) के तहत संदर्भ

भारत का संविधान।

(एस. आर. दास सी. जे., भगवती, वेंकटरामा अय्यर,

बी. पी. सिन्हा, जेफर आई. एम. ए. एम., एस. के. दास और जे. एल.

कपूर जे. जे.)

राष्ट्रपति का संदर्भ-केरल शिक्षा विधेयक, 1957-संविधान की राष्ट्रीय वैधता-उच्चतम न्यायालय का सलाहकार अधिकार क्षेत्र, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का दायरा -

भारत, कला। 143 (1) , 14 , 29 , 30 और 226। यह कला के तहत एक संदर्भ था। 143 (1) संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1959] की राय प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया

996

संवैधानिक विधि से संबंधित कुछ प्रश्नों पर न्यायालय

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के कुछ प्रावधान, जो केरल विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे, लेकिन

राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष के विचार के लिए आरक्षित किया गया था

दाँत। विधेयक, जैसा कि इसके शीर्षक और प्रस्तावना से संकेत मिलता है, इसके लिए था -

कला के प्रावधान। 45 संविधान और राज्य सरकार को नियंत्रण की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त दोनों संस्थान। चार प्रश्नों में से

इस न्यायालय को संदर्भित, प्रथम और तृतीय आक्षेपित सी. एल.। 3 (5) सीएल के साथ पढ़ें। 36 और सी. एल. 15 विधेयक को कला के तहत भेदभावपूर्ण होने के रूप में। 14 , दूसरा आक्षेपित सी. एल. एस. 3 (5) , 8 (3) और सीएलएस। 9 13 तक

विधेयक को अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया है।

सरकार, सीएलएस। 9 13 ने विद्यालयों के विनियमन और प्रबंधन, शिक्षकों को वेतन के भुगतान के लिए प्रावधान किए और उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें और क्ल। (33) अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम आदेश देने से मना किया

देखें कि सी. एल. 3 (5) सी. एल. ने विधेयक के अन्य प्रावधानों को आकर्षित किया, यदि उनमें से कोई भी असंवैधानिक पाया गया। 3 (5) स्वयं निंदा से बच नहीं सके। आयोजित (दास सी. जे., भगवती, बी. पी. सिन्हा, जाफर इमाम, एस. के. दास और जे. एल. कपूर जे. जे. के अनुसार) , कि हालांकि कला। 143 (1) संविधान, जो वस्तुतः के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करता है

एस. 213 (1) भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने इस न्यायालय को विवेकाधिकार दिया, जहां वह उचित समझता है, कि वह किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति को अस्वीकार कर दे। इसे संदर्भित प्रश्नों पर राय, आपत्ति कि इस तरह

लागू किए गए कानून से संबंधित नहीं, बल्कि एक विधेयक की वैधता से संबंधित प्रश्न, जिसे अभी तक अधिनियमित नहीं किया गया था, संदर्भ को स्वीकार करने से इनकार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) का उद्देश्य था -

राष्ट्रपति की शंकाओं को दूर करना और किसी भी तरह से सहमत नहीं था

किसी भी संदेह के साथ जो एक पार्टी मनोरंजन कर सकती है और नहीं

संदर्भ इस आधार पर अधूरा या अक्षम हो सकता है कि इसमें अन्य प्रश्न शामिल नहीं थे जिन्हें शामिल किया जा सकता था।

इसमें और यह इस न्यायालय के लिए नहीं था कि वह संदर्भ से परे जाए और

उन पर चर्चा करें।

कला द्वारा प्रदत्त सलाहकार क्षेत्राधिकार। 143 (1) यह कला द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार से अलग था। 143 (2) संविधान में कि बाद वाले ने इस न्यायालय को जवाब देना अनिवार्य बना दिया

संदर्भ।

एस्टेट ड्यूटी के लेवी में, [1944] एफ. सी. आर. 317, पर भरोसा किया गया।

अटॉर्नी-ओंटारियो के लिए जनरल बनाम। हैमिल्टन स्ट्रीट रेलवे, [1903]

ए. सी. 524, अटॉर्नी-जनरल फॉर ब्रिटिश कोलंबिया बनाम। अटॉर्नी-कनाडा के लिए जीन राल, [1914] ए. सी. 153, कनाडा में वैमानिकी के विनियमन और नियंत्रण में, [1932] ए. सी. 54, के पुनः आवंटन में

भूमि और भवन, [1943] एफ. सी. आर. 20 और दिल्ली विधि अधिनियम,

1912 , [1951] एस. सी. आर. 747 पर विचार किया गया।

राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत एक को ओवरराइड नहीं कर सका

मौलिक अधिकार और इसे संरक्षित करना चाहिए, लेकिन किसी भी न्यायालय को मौलिक अधिकार के दायरे को निर्धारित करने में, एक निर्देशक सिद्धांत की पूरी तरह से अनदेखी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को अपनाकर दोनों को यथासंभव अधिक से अधिक प्रभाव देने का प्रयास करना चाहिए।

मद्रास राज्य बनाम। श्रीमती. चंपकम दोराईराजन, [1951] एस. सी. आर.

525 और मोहम्मद। हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य, [1959]

एस. सी. आर. 629, संदर्भित।

संदर्भ के तहत प्रश्नों के उत्तर देने में, गुण या

अन्यथा विधेयक को प्रायोजित करने वाली सरकार की नीति से इस न्यायालय का कोई सरोकार नहीं हो सकता था और इसका एकमात्र कर्तव्य विधेयक के ऐसे पक्षकारों की संवैधानिक वैधता पर अपनी राय व्यक्त करना था जो प्रश्नों में शामिल थे।

एक श्रृंखला द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के प्रकाश में न्याय किया गया

कला की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय के निर्णय। 14 संविधान के प्रश्न 1 और 3 के भीतर आने वाले विधेयक के खंडों को उस अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

सी. एल. द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। 3 (5) सीएल के साथ पढ़ें। 26 में से

विधेयक, जिसने अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को सरकारी या निजी स्कूल में भेजना अनिवार्य कर दिया था और इस तरह ऐसे क्षेत्र में एक नए स्कूल के लिए काम करना असंभव बना दिया था, जिसमें न तो सहायता और न ही मान्यता की मांग की गई थी, को ऐसा नहीं कहा जा सकता था

भेदभावपूर्ण क्योंकि राज्य अपने लोगों की जरूरतों को अच्छी तरह से जानता था,

और इस तरह का भेदभाव काफी अनुमेय था, जैसा कि भौगोलिक वर्गीकरण पर आधारित था।

मोहम्मद. हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य, [1959] एस. सी. आर.

629 , चिरनजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ, [1950] एस. सी. आर. 1045, रामकृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर, [1959] एस. सी. आर. 279, का उल्लेख किया गया है। .

कोई भी कानून तब तक भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि इसके प्रावधान

यह अपराध है और चूंकि विधेयक के प्रावधानों ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने सभी शैक्षणिक संस्थानों में समान रूप से लागू करके कानून के समान संरक्षण का उल्लंघन किया है, हालांकि समान रूप से स्थित नहीं है।

कंबरलैंड कोल कंपनी v. संशोधन बोर्ड, (1931) 284 यू. एस. 23;

76 एल. एड. 146 , अप्रयोज्य रखा गया।

किसी कानून की नीति और उद्देश्य का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है -

इसका लंबा शीर्षक और प्रस्तावना। विवादित विधेयक ने अपनी नीति को लंबे शीर्षक और प्रस्तावना में निर्धारित किया और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों द्वारा इसे मजबूत किया।

विभिन्न खंडों में अधिक निश्चित बयान और इसके साथ-साथ, उस नीति को लागू करने में सरकार को दिए गए विवेकाधिकार का उपयोग करना था। सी. एल. में 'मे' शब्द का उपयोग। 3 (3) इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता था, क्योंकि एक बार उद्देश्य स्थापित हो जाने और विवेकाधिकार के प्रयोग की शर्तें पूरी हो जाने के बाद, उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करना सरकार का दायित्व था। यदि यह ऐसा करने में विफल रहा, तो विफलता की निंदा की जानी चाहिए, न कि विधेयक की।

विश्वांबर सिंह बनाम। उड़ीसा राज्य, [1954] एस. सी. आर. 842

और जूलियस वी। ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड बिशप, (1880) 5 एप। कैस। 214 ,

संदर्भित किया गया।

विवेकाधीन शक्ति अनिवार्य रूप से भेदभावपूर्ण नहीं थी, और

सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। नीति निर्धारित करने के अलावा, राज्य विधानमंडल ने स्वयं सी. एल. द्वारा प्रभावी नियंत्रण का समर्थन किया। 37 और सी. एल. का परंतुक। 15 बिल से। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विधेयक ने सरकार को दिशाहीन या अनियंत्रित शक्तियां प्रदान कीं।

संविधान का अनुच्छेद 30 (1), जो आवश्यक था

कला के साथ संगत। 29 (1) और अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया, 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया, न ही इसे संविधान द्वारा कहीं और परिभाषित किया गया था, लेकिन यह सुझाव देना बेतुका था कि अल्पसंख्यक या वर्ग

कला द्वारा परिकल्पित। 30 (1) और कला। 29 (1) इसका मतलब केवल प्रति पुत्र ऐसा हो सकता है जो विशेष क्षेत्र में एक संख्यात्मक अल्पसंख्यक का गठन करता है

जहाँ शैक्षणिक संस्थान किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन स्थित था या रहता था। संविधान का अनुच्छेद 350-ए, जिसका ठीक से अर्थ लगाया गया है, इस तरह के प्रस्ताव का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। जैसा कि विवादित विधेयक पूरे राज्य में फैला हुआ है, राज्य में अल्पसंख्यकों का निर्धारण इसकी पूरी आबादी के आधार पर किया जाना चाहिए, और इस प्रकार ईसाई, मुसलमान और एंग्लो-इंडियन इसके अल्पसंख्यक समुदाय होंगे।

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है।

संविधान से पहले से मौजूद या उसके बाद स्थापित अल्पसंख्यक संस्थान और दोनों को संरक्षित करते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं थी कि एक अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यक तक ही सीमित रखा जाए। जिस समुदाय से वह संबंधित था और एक अल्पसंख्यक संस्थान, उसमें एक गैर-सदस्य को स्वीकार करके ऐसा करना बंद नहीं कर सकता था।

कला भी नहीं। 30 (1) किसी भी तरह से पढ़ाए जाने वाले विषयों को सीमित करें

एक अल्पसंख्यक संस्थान में, और उसके महत्वपूर्ण शब्द "अपनी पसंद के", स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उसके द्वारा प्राप्त अधिकारों का दायरा उन संस्थानों की प्रकृति से निर्धारित होता था जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों ने स्थापित करने के लिए चुना था और जिन तीन श्रेणियों में ऐसे संस्थानों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता था, वे थे (1) वे जो न तो सहायता चाहते थे और न ही राज्य से मान्यता, (2) वे जो सहायता चाहते थे, और (3) वे जो मान्यता चाहते थे लेकिन सहायता नहीं चाहते थे। विवादित विधेयक केवल दूसरी और तीसरी श्रेणी के संस्थानों से संबंधित था।

कला द्वारा प्रयुक्त शब्द 'सहायता'। 29 (2) और 30 (2) शामिल हैं

' कला के तहत अनुदान। 337 संविधान और उस शब्द का वही अर्थ होना चाहिए जो विधेयक में आता है। नतीजतन, मैं प्रश्न संख्या 2 में उल्लिखित विधेयक के ऐसे खंडों को उन अनुदानों के लिए पूर्ववर्ती नई और कठोर शर्तों के रूप में लागू करता हूं जिनके लिए यह कला के अधीन था। 337 और 29 (2) ने न केवल अनुच्छेद का उल्लंघन किया। 337 लेकिन सार और प्रभाव में भी, कला। 30 (1) संविधान के अधीन थे और उस हद तक अमान्य थे।

राशिद अहमद बनाम। नगरपालिका बोर्ड, कैराना, [1950] एस. सी. आर. 566, मोहम्मद। यासीन वी. नगर क्षेत्र समिति, जलालाबाद, [1952] एस. सी. आर. 572 और द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम। बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, [1955] आई. एस. सी. आर. 568 का उल्लेख किया गया है।

हालाँकि कला के तहत एंग्लो-इंडियन शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सहायता देने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। 337 संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय संस्थानों और कलाओं के लिए राज्य सहायता अपरिहार्य थी। 28 (2) , 29 (2) और 30 (2) ने स्पष्ट रूप से ऐसी सहायता और कलाओं के अनुदान का खाका तैयार किया। 41 और 46 ने आरोप लगाया शैक्षणिक संस्थानों की सहायता करना और अल्पसंख्यकों के ऐसे हितों को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य है।

लेकिन अल्पसंख्यकों का कला के तहत अपने शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अधिकार। 30 (1) , सहायता के अनुदान के लिए पूर्ववर्ती शर्तों के रूप में उचित विनियमों को लागू करके खराब प्रशासन के खिलाफ उचित सुरक्षा उपायों पर जोर देने के राज्य के अधिकार के साथ असंगत नहीं था। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं था कि राज्य विधानमंडल कला के तहत कानून बनाने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 245 और संविधान की धारा 246, अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करके मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करती है, जिसके लिए उसके पास प्रत्यक्ष रूप से करने की कोई शक्ति नहीं थी, वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती थी।

सहायता, कला का उल्लंघन किया। 30 (1) संविधान से। राज्य मान्यता प्रदान करने पर भी इसी तरह के विचार लागू होते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका।

या कला के तहत अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करें। 30 (1) राज्य की मान्यता के बिना, अन्यथा यह शिक्षा संहिता के तहत अपने विद्वानों के लिए विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाने या सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश करने के लिए खुला नहीं होगा। हालांकि यह निस्संदेह सच था कि राज्य की मान्यता का कोई मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है, मान्यता से इनकार करना ऐसी शर्तों को छोड़कर जो वस्तुतः संस्था को प्रशासित करने के अधिकार के समर्पण के बराबर है, सार और प्रभाव में कला का उल्लंघन करना चाहिए। 30 (1) संविधान से। खंड 3 (5), क्ल

के साथ पढ़ा जाता है। 20 विधेयक, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण शुल्क लेने पर प्रतिबंध लगाने में, वंचित कर दिया

सी. एल. द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे के बिना आय के एक फलदायी स्रोत के अल्पसंख्यक संस्थान। (9) सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए, और इस प्रकार राज्य की मान्यता के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती लागू की गई जो थी

127 1000

कला का उल्लंघन करने वाला प्रभाव। 30 (1) और इसलिए, उस हद तक शून्य था। अधिनियम के तहत बनाए जाने पर कोई भी नियम इस तरह की अयोग्यता को ठीक नहीं कर सकता था।

संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य की आवश्यकता नहीं थी

सरकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी

संविधान द्वारा गारंटीकृत अल्पसंख्यक अधिकारों का नुकसान,

यदि सरकार ने ऐसा चुना तो वह सरकार के माध्यम से ऐसा कर सकती है

शिक्षा और सहायता प्राप्त स्कूल, और यह न्यायालय ऐसे मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध था जैसा कि संविधान ने सोचा था अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान करने के लिए उपयुक्त।

कला द्वारा उच्च न्यायालयों को प्रदत्त व्यापक शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र। 226 संविधान का अनुच्छेद सी. एल. जैसे प्रावधान से प्रभावित नहीं हो सकता है। (33) विधेयक, जो न्यायालयों को इसके तहत किसी भी कार्यवाही को रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा या अंतरिम आदेश जारी करने से मना करता है, और इसे निम्न के अधीन पढ़ा जाना चाहिए:

कला के प्रावधानों को ओवरराइड करना। 226 संविधान से।

जे. वेंकटरामा अय्यर-यह स्पष्ट था कि कला। 30 (1) में से

संविधान में अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं दिया गया है।

राज्य मान्यता के लिए संस्थान, और न ही, उचित रूप से अर्थ लगाया गया, निहितार्थ द्वारा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के निहितार्थ, यदि उठाए जाते हैं, तो कला के व्यक्त प्रावधानों के विपरीत होगा। 45 संविधान का

यह। अनुच्छेद 30 (1) का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की रक्षा करना था -

विशुद्ध रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान किए जाने वाले अल्पसंख्यक संस्थान

और यह अभिनिर्धारित करना कि राज्य इसके तहत मान्यता देने के लिए बाध्य था

वे केवल कला प्रस्तुत करने के लिए नहीं होंगे। 45 पूरी तरह से निष्फल लेकिन संविधान की मूल अवधारणा को भी रद्द करने के लिए, अर्थात्,

इसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र,

यहाँ मौलिक अधिकार और अधिकार के बीच कोई टकराव नहीं था।

राज्य नीति का एक निर्देशात्मक सिद्धांत जो फल देना चाहिए, और

कला का सिद्धांत। 45 पूरा खेल होना चाहिए। विधेयक के खंड (20) को उस सिद्धांत और धारा को लागू करने के लिए बनाया गया था। 3 (5) इसे राज्य की मान्यता के लिए एक पूर्व शर्त बनाने में विधेयक का

कला का उल्लंघन करते हैं। 30 (1) संविधान से।

न ही कला के पीछे की नीति पर विचार किया जा सका। 30 (1)

एक अलग निष्कर्ष की ओर ले जाता है, यह मानते हुए कि

नीति को भाषा से अलग किया जा सकता है; क्योंकि

नीति इसके अलावा और कुछ नहीं थी कि बहुसंख्यक समुदाय राज्य के पास धर्म को नष्ट करने या खराब करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए।

अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक या भाषाई अधिकार।

केवल दो दायित्व, एक सकारात्मक और दूसरा ए

अल्पसंख्यक, धार्मिक या भाषाई संस्थाओं सहित, और (2) अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना को प्रतिबंधित नहीं करना। उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करना।

यह अभिनिर्धारित करना कि राज्य सरकार आगे भी अनुच्छेद के तहत बाध्य थी। 30 (1) अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देना एस. सी. आर. होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1001

अल्पसंख्यकों को अधिक पसंदीदा स्थिति में रखने के लिए

बहुसंख्यक समुदाय, जिसका संविधान कभी अपमान नहीं करता प्लेटेड।

सिटी विनीपेग बनाम। बैरेट: विनीपेग का शहर बनाम। लोगान, [1892]

ए. सी. 445, संदर्भित।

सलाहकार न्यायनिर्णय: विशेष संदर्भ संख्या 1

1958 से।

अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ

143 (1) केरल पर भारत के संविधान का

शिक्षा विधेयक, 1957।

जिन परिस्थितियों के कारण यह संदर्भ दिया गया

15 मार्च, 1958 के संदर्भ का पूरा पाठ, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

जहाँ राज्य की विधान सभा

केरल ने बेहतरी के लिए एक विधेयक पारित किया है

शैक्षणिक संस्थान का संगठन और विकास

- केरल राज्य में राज्य (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

केरल शैक्षिक विधेयक);

और जहाँ उक्त विधेयक की एक प्रति है

यहाँ संलग्न, के राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया गया है

केरल, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, मेरे लिए विचार करना;

और जहाँ खंड (3) का उपखंड 3

उक्त विधेयक केरल सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम बनाता है,

द्वारा स्थापित और अनुरक्षित किसी भी विद्यालय को मान्यता देना

प्रो के उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय

उक्त के उपखंड (2) में निर्धारित सुविधाओं का उल्लेख करना।

सामान्य शिक्षा के लिए सुविधाएँ, विशेष शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए;

और जहाँ खंड 3 का उपखंड (5)

बिल ने कहा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि कोई भी नया स्कूल

किसी भी निजी क्षेत्र में स्थापित या कोई उच्च वर्ग खोला गया

स्कूल, बिल के एक अधिनियम और अधिनियम बनने के बाद

लागू हो गया है, अन्यथा के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के साथ

उसकी धारा 36 के तहत, होने का हकदार नहीं होगा केरल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त;

और जहाँ एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या।

खंड 3 के उक्त उपखंड (5) के प्रावधान

उक्त विधेयक सरकार को एक निर्देशित सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट प्रदान करता है [1959]

1002

नए विद्यालयों की मान्यता और किसी भी निजी विद्यालय में उच्च कक्षाओं को खोलने के संबंध में शक्ति जो मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करने में सक्षम है;

और जहाँ एक संदेह और पैदा हो गया है

क्या निजी विद्यालयों में नए विद्यालयों और उच्च वर्गों को मान्यता देने की ऐसी शक्ति का उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) द्वारा गारंटीकृत अल्पसंख्यकों के शिक्षा की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को प्रभावित किया जा सके।

शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) द्वारा गारंटीकृत संबंध उनके द्वारा सारणीबद्ध; और जहाँ खंड 9 से 13 सरकार को सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन के संबंध में कुछ शक्तियाँ प्रदान करते हैं;

और जहाँ एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या

अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) द्वारा गारंटीकृत उन्हें प्रशासित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

और जहाँ उक्त विधेयक का खंड 15

केरल सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में सहायता प्राप्त स्कूलों की किसी भी श्रेणी को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार है, यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्य में सामान्य शिक्षा के मानकीकरण के लिए केरल राज्य या किसी भी क्षेत्र में साक्षरता के स्तर में सुधार के लिए या किसी भी क्षेत्र में सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए या किसी भी श्रेणी की शिक्षा को उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने के लिए एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट पर जनहित में ऐसा करना आवश्यक है।

1003

स्कूलों की संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या सुधार के लिए उस सरकार द्वारा दी गई सहायता या अनुदान की राशि को घटाने के बाद इस तरह से अपने हाथ में लिए गए स्कूलों के बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजे का भुगतान;

और जहाँ एक संदेह पैदा हुआ है कि क्या ऐसा है

शक्ति का प्रयोग किसी भी मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से करने में सक्षम नहीं है;

और जहाँ उक्त विधेयक का खंड 33 उपबंध करता है

कि, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी अदालत कोई अस्थायी मंजूरी नहीं दे सकती है।

निषेधाज्ञा या कोई अंतरिम आदेश जो किसी पर प्रतिबंध लगाता है

ऐसी कार्यवाही जो अधिनियम के तहत की जा रही है या की जाने वाली है;

और जहाँ एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या

उक्त खंड 33 के प्रावधान, जहाँ तक वे उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित हैं, संविधान के अनुच्छेद 226 का उल्लंघन करेंगे।

और जहाँ कोन की संभावना है

यहाँ विधेयक के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता

कानून की अदालतों में पूछताछ किए जाने से पहले संदर्भित, जिसमें काफी मुकदमेबाजी शामिल है;

और जहाँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए

इसके बाद निर्धारित कानून उत्पन्न हुए हैं और ऐसे हैं प्रकृति और इतना महत्व है कि यह समीचीन है

कि उस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त की जानी चाहिए;

अब, इसलिए, शक्तियों के प्रयोग में

अनुच्छेद 143 के खंड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त

संविधान, I, राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति,

एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों को सर्वोच्च न्यायालय को भेजें विचार और उस पर रिपोर्ट के लिए भारत का न्यायालय,

अर्थात्: ---

" (1) क्या केरल के खंड 3 का उपखंड (5)

शिक्षा विधेयक, जिसे उसके खंड 36 के साथ पढ़ा जाता है, या इनमें से कोई भी

उक्त उपखंड के प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। संविधान के किसी भी विवरण में या किसी भी

हद तक?

(2) खंड 3 का उपखंड (5), खंड 1004 का उपखंड (3) करें।

केरल शिक्षा विधेयक के खंड 8 और खंड 9 से 13,

या उसके कोई प्रावधान, अनुच्छेद 30 के खंड (1) का उल्लंघन करते हैं: संविधान के किसी भी विवरण में या किसी भी

हद तक?

(3) क्या केरल शिक्षा विधेयक का खंड 15 है, या

इसके किसी भी प्रावधान से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। किसी भी विवरण में या किसी भी हद तक?

(4) क्या केरल शिक्षा विधेयक का खंड 33 है, या

इसके किसी भी प्रावधान से संविधान के अनुच्छेद 226 का उल्लंघन होता है। किसी भी विवरण में या किसी भी हद तक?

1958. 29 अप्रैल, 30. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 12 मई।

एम. सी. सीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी, सी. के.

डैफ्टरी, सॉलिसिटर-भारत के जनरल, एच. एन. सान्याल,

अतिरिक्त सॉलिसिटर-भारत के महाधिवक्ता जी. एन. जोशी और भारत के राष्ट्रपति के लिए आर. एच. ढेबर। प्रेमम।

भारत के संविधान में बल दिया गया है -

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता

और व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है। देने के लिए।

इन आदर्शों को लागू करने के लिए संविधान निधि प्रदान करता है

कला में व्यक्तियों के लिए मानसिक अधिकार। 19 , 25 और

28 और कला में समूहों के लिए। 26 , 29 और 30. फंडा कला में मानसिक अधिकार। 29 और 30 निरपेक्ष हैं और नहीं

उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, हालांकि प्रतिबंध

इसे अन्य मौलिक अधिकारों पर रखा जा सकता है। ये

अधिकारों की तुलना कला के तहत अधिकारों के साथ की जा सकती है।

44 (2) आयरिश संविधान और एस। 93 अंग्रेज़ों का

26 , 29 और इस न्यायालय द्वारा 30 पर विचार किया गया था आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम।

श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी,

([1954] एस. सी. आर. 1005 1028-1029) और स्टेट ऑफ

बॉम्बे बनाम। बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, ([1955] 578,580,586 पर 1 एस. सी. आर. 568)। अनुच्छेद 30 (1) निरपेक्ष देता है।

अल्पसंख्यकों को स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान। संविधान

अल्पसंख्यकों को इन स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना। स्वयं कला के तहत काम करने के लिए। 30 (1) .

* केरल शिक्षा विधेयक का खंड 3 (5)

नए स्कूलों की स्थापना और खोलने पर जोर उच्च वर्गों की नियुक्ति एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के नियमों के अनुसार होगी।

1005

सी. एल. के तहत तैयार किया जाए। 36 उन्हें मान्यता देने के लिए

सरकार द्वारा, कार्यपालिका को दिशाहीन और अनियंत्रित शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं और कला का उल्लंघन किया जाता है। 14. विधायिका कोई नीति निर्धारित नहीं करती है, लेकिन इसे नियम बनाने की शक्तियों के तहत कार्यपालिका पर छोड़ देती है। ए. थंगल कुंजू मुसलियार बनाम। एम. वेंकिताचलम पोट्टी,

[1955] 2 एस. सी. आर. 1196 1239,1241); पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार, ([1952] एस. सी. आर. 284 345,346)। यह कहना गलत है कि केरल में ईसाई और मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं। जब संविधान अल्पसंख्यकों की बात करता है तो यह अखिल भारतीय आधार पर बोलता है। तथ्य यह है कि एक निश्चित समुदाय ने एक बहुत

किसी विशेष राज्य में जनसंख्या का उच्च प्रतिशत अल्पसंख्यक के रूप में इसकी स्थिति से विचलित नहीं हुआ। विधेयक के प्रावधान दिए गए अधिकारों को भ्रामक बनाते हैं

कला द्वारा। 30 (1) अल्पसंख्यकों के लिए। सरकारी सहायता के साधन का उपयोग करके विधेयक अल्पसंख्यक संबंधों को अपने स्वयं के स्कूलों का प्रशासन करने के उनके अधिकार से वंचित करने का प्रयास करता है। शिरूर मठ मामला, ([1954] एस. सी. आर. 1005 1028,1029)। अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों का अधिकार। 30 (1) उनके संस्थानों की स्थापना और प्रशासन एक निरपेक्ष और

निरंकुश अधिकार और सरकार से उनकी सहायता प्राप्त करने के अनुरूप है। अनुच्छेद 337 एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष दृष्टिकोण बनाता है। अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन किया गया है कि स्कूल सहायता के लिए जाते हैं या नहीं। विधेयक का खंड 8 (3) जिसके तहत सभी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों से एकत्र की जाने वाली सभी फीस आदि सरकार को सौंपनी होगी, प्रबंधन को प्रशासन के अधिकार से वंचित करता है। पियर्स वी। सोसाइटी ऑफ होली सिस्टर्स नेम्स, (69 एल. एड। 1070 1077 में); माहेर बनाम। नेब्रास्का, (67 एल. एड। 1042 1044 पर)।

विधेयक का खंड 15 सरकार को किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी श्रेणी के सहायता प्राप्त स्कूलों का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। यह खंड पूरी तरह से कला का विध्वंसक है। 30 (1) . यह कला का भी अपमान करता है। 14 चूंकि यह सरकार को अधिग्रहण के लिए उपयुक्त रूप से श्रेणी और क्षेत्र का चयन करके किसी भी स्कूल को चुनने और चुनने का अधिकार देता है, इसलिए चयन करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

विधेयक का खंड 33 सभी न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1959] से प्रतिबंधित करता है।

1006

कोई अस्थायी निषेधाज्ञा या अंतरिम आदेश देना

अधिनियम के तहत की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में। इस हद तक कि यह खंड कला का उल्लंघन करता है। 226 या कला। 32 , यह शून्य है। कला के तहत अंतरिम आदेश भी पारित किए जाते हैं। 226 और 32 मुख्य राहत के सहायक के रूप में। राज्य

राजस्थान के महाधिवक्ता कासलीवाल, आर. एच. ढेबर और टी. एम. सेन ने राजस्थान राज्य के लिए इस प्रस्ताव को अपनाया। भारत के महान्यायवादी की दलीलें।

जी. एस. पाठक, एम. आर. कृष्णा पिल्लई के साथ

केरल ईसाई शिक्षा कार्रवाई समिति,

केरल स्कूल प्रबंधकों के लिए जे. बी. दादाचंजी '

वी. ओ. अब्राहम और जे. बी. दादा के साथ संबंध

बडोगरा और क्विलंडी में सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंधकों के संघ के लिए चांजी, कैथोलिक यूनियन ऑफ इंडिया और

कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ बॉम्बे। प्रस्तावना में

संविधान नागरिकों को सुरक्षित करने की बात करता है

भारतीय बिरादरी व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देती है

और राष्ट्र की एकता। इस एकता को सुरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 25 से 30 बनाए गए हैं। कला. 30 यह पूर्ण रूप से लागू होता है और इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के विनियमन या प्रतिबंध की अनुमति नहीं देता है। उनकी पसंद "कला में। 30

राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह हुआ है

अल्पसंख्यक संस्थानों को चलाने का सामान्य तरीका

सहायता और मान्यता के साथ। कला में निहित। 30 (1) माता-पिता या अभिभावक का यह अधिकार है कि वह अपने बच्चों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्रदान करे। बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी बनाम। द स्टेट ऑफ बॉम्बे, (56 बॉम। एल. आर. 643 653 पर)। यह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है।

उस समुदाय द्वारा प्रशासित स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षित करना। द स्टेट ऑफ बॉम्बे v. बॉम्बे

एजुकेशन सोसाइटी, ([1955] 1 एस. सी. आर. 568 586 पर)। "प्रशासन" शब्द की व्याख्या 69 में की जानी चाहिए।

एल. एड. 1070 1076, 67 एल. एड. 1042 1045 और 71 पर

एल. एड. 646 647 पर। साधारण शब्दकोश का अर्थ

प्रशासन का अर्थ है 'प्रबंधित करना' या 'जारी रखना'। यह कानून

प्रकृति अप्रत्यक्ष रूप से भी मौलिक का उल्लंघन नहीं कर सकती है।

अधिकार। द्वारकादास श्रीनिवास बनाम। शोलापुर स्पिन

निंग एंड वीविंग कंपनी। लिमिटेड, ([1954] 683 पर एस. सी. आर. 674); एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1007

पंजाब प्रांत बनाम। दौलत सिंह, (73.आई. ए. 59); द. बॉम्बे राज्य बनाम। बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, ([1955] 1 एस. सी. आर. 568 583 पर)। अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस, वॉल्यूम। 11 , पी। 724 , सेक. 95. विधेयक की पूरी योजना शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए है और इस प्रकार यह निधि का उल्लंघन करता है

कला के तहत मानसिक अधिकारों की गारंटी। 30. विधेयक का खंड 3 जिसमें एक विद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। 10 जो सरकार को अल्पसंख्यक सामुदायिक विद्यालयों और सामुदायिक विद्यालयों में शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार देता है। 26 जो माता-पिता के लिए अपने बच्चों को सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में भेजना अनिवार्य बनाता है जहां अनिवार्य शिक्षा है।

बल प्रयोग, सभी कला का अपमान करते हैं। 30. इसी तरह सीएलएस। 6 , 7 , 8 , 11 , 12 , पी 14,15 और 28 इस मौलिक अधिकार के लिए विनाशकारी हैं।

फ्रैंक एंथनी और पी. सी. अग्रवाल, फॉर द ऑल

इंडिया एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन एंड फॉर द एपोस्टोलिक

कार्मेल एजुकेशन सोसाइटी और रोमन कैथोलिक डियो सेसे। कला के तहत। 143 इस न्यायालय को विवेकाधिकार है कि

भूमि और भवन, ([1943] एफ. सी. आर. 20 22 पर)। द. वर्तमान संदर्भ सबसे अधूरा है और पूरी तरह से अपूर्ण है।

संतोषजनक और न्यायालय को जफरुल्लाह खान जे. के बाद एस्टेट ड्यूटी के लेवी, ([1944] एफ. सी. आर. 317 334,335 पर) में इसका जवाब देने से इनकार कर देना चाहिए। संदर्भ अधूरा है क्योंकि इस न्यायालय को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या विधेयक के कुछ प्रावधान कुछ प्रावधानों को आहत करते हैं।

निर्दिष्ट मौलिक अधिकार हालांकि वास्तव में वे

प्रावधान अन्य मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिन्हें विशेष रूप से संदर्भित नहीं किया गया है, जो मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं। इस तरह का संदर्भ अनुचित है

अदालत और मेरे मुवक्किलों के लिए घातक। I यदि यह न्यायालय संदर्भ पर अपनी राय देने के पक्ष में है, तो विधेयक के प्रावधानों की वैधता पर सभी आपत्तियों को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, और यह

न्यायालय के पास ऐसा करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है।

जे

एंग्लो-इंडियन स्कूलों का एक विशेष स्थान है।

अनुच्छेद 30 (1) एंग्लो-इंडियन समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार देता है। ये मौलिक अधिकार थे। किसी भी सामाजिक नियंत्रण के अधीन नहीं। का उद्देश्य

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केरल शिक्षा विधेयक ईसाई चर्च, विशेष रूप से कैथोलिकों पर हमला करने के लिए था, ताकि उनके धर्म को समाप्त किया जा सके, उनकी संपत्ति को छीन लिया जा सके, राज्य के अलावा अन्य सभी शिक्षा एजेंसियों को समाप्त किया जा सके ताकि राज्य शिक्षा को व्यवस्थित कर सके और बच्चों को शिक्षा दे सके।

निर्देश को लागू करने का प्रयास करने वाला विधेयक

कला में राज्य नीति के सिद्धांत। 45 मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना कला का उल्लंघन है। 30 (1) . निर्देशात्मक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। मद्रास राज्य बनाम। श्रीमती. चंपकम दोराईराजन, (1951)

एस. सी. आर. 521 531 पर)। राज्य छोटे शैक्षणिक संस्थानों को शुल्क नहीं लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

बच्चों के जाने पर विधेयक द्वारा लगाया गया प्रतिबंध सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल कला द्वारा गारंटीकृत अल्पसंख्यकों की पसंद को अलग करेंगे। 30. मान्यता के अधिकार का हिस्सा था

कला के तहत अल्पसंख्यक। 30. अनुच्छेद 337 एंग्लो-इंडियंस द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को विशेष अनुदान या सहायता प्रदान करता है और राज्य इसे हटा नहीं सकता है या उस पर शर्तें या प्रतिबंध नहीं लगा सकता है।

विधेयक का खंड 3 (5) दोनों कला का उल्लंघन करता है। 30 (1) और

कला. 14. यह मौजूदा स्कूलों के बीच भेदभाव करता है।

जो शुल्क लेना जारी रख सकते हैं और प्राथमिक कक्षाएं और नए स्कूल जो मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तरह की शुल्क नहीं ले सकते हैं। अल्पसंख्यकों द्वारा नए विद्यालय खोलने पर लगाई गई शर्तें ऐसी हैं कि वे उन्हें कला के तहत अधिकार से वंचित करती हैं। 30 (1) .

नूर-उद-दीन अहमद, एस. एस. शुक्ला और पी. सी. आगर

वाला, अखिल भारतीय जमीयत-उल-उलेमा-ए-हिंद के लिए। इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को प्राप्त करना है

संस्थान और इस प्रकार अल्पसंख्यकों को कला के तहत अपनी पसंद के स्कूलों की स्थापना और प्रशासन के उनके अधिकार से वंचित करना। 30. इस अधिकार में अल्पसंख्यकों का सहायता प्राप्त करने का

अधिकार और बिना किसी प्रतिबंध के अपने स्कूलों की सरकारी मान्यता प्राप्त करना भी शामिल है। विधेयक के प्रावधान राज्य को उसके प्रयोग के लिए आधार और मानक निर्धारित किए बिना शक्तियां प्रदान करते हैं। शक्ति।

एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1009

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जी. सी. माथुर और सी. पी. लाल।

महान्यायवादी की दलीलें स्वीकार की गईं

भारत।

बी. के. बी. नायडू, केरल राज्य मुस्लिम लीग के लिए

जी. एस. पाठक और फ्रैंक के तर्कों को अपनाया

एंथनी।

डी. एन. प्रित, सरदार बहादुर और सी. एम. कुरुविला,

केरल राज्य के लिए। जिन प्रश्नों का उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय कुछ संदेहों से उत्पन्न हुआ

विधेयक के कुछ अनुकूल दृष्टिकोण के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा विचार किया गया। यदि राष्ट्रपति ने मनोरंजन नहीं किया

कुछ अन्य संदेह, पक्ष इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि

राष्ट्रपति को वे अन्य संदेह भी रहे होंगे। द.

अदालत के पास उन प्रश्नों से परे जाने की कोई शक्ति नहीं है।

जो संदर्भ में उठाए गए हैं। केरल राज्य

निर्दिष्ट किया गया है और यह उस दृष्टिकोण का पालन करेगा जो अदालत इन प्रश्नों पर अपनी बात रखेगी।

केरल शिक्षा विधेयक एक प्रगतिशील विधेयक है।

कानून जो राज्य में शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर संगठन और विकास और विविध और व्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है

पूरे राज्य में सेवा। यह लगभग 70,000 शिक्षकों को उन्हें सहायता प्रदान करने और शिक्षकों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। विधेयक कला में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का भी प्रयास करता है। 45 सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का समर्थन करके।

विधेयक में एक स्पष्ट सिद्धांत और नीति निर्धारित की गई है, जैसे -

शिक्षा के बेहतर संगठन और विकास के लिए अपने उद्देश्यों में कहा गया है। यह प्रस्तावना द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है जो एक विविध और व्यापक शैक्षिक सेवा प्रदान करने का प्रयास करती है।

पूरे राज्य में। राष्ट्रीयकरण जिसे आसानी से और कानूनी रूप से प्राप्त किया जा सकता था, राज्य द्वारा अपनाई गई नीति नहीं थी। इसकी नीति स्कूलों की तीन अलग-अलग श्रेणियों, सरकार द्वारा संचालित स्कूलों, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को मुख्य रूप से प्रभावित करने की थी। अदालत को तब तक पूरी तस्वीर नहीं मिल सकी जब तक कि नियम नहीं बनाए गए।

नियमों को अनिवार्य रूप से सरकार पर छोड़ दिया जाना था।

इस तरह का प्रत्यायोजित कानून एक अभिन्न और अपरिहार्य है।

एक आधुनिक राज्य शक्ति का सक्षम हिस्सा। सी. एल. के साथ पठित विधेयक का खंड 3 (5)। 36 कला का उल्लंघन नहीं करता है। 14. जादुनान दान यादव बनाम। आर. पी. सिंह (ए. आई. आर. 1958 पैट। 43 47); विश्वंभर सिंह बनाम। उड़ीसा राज्य ([1954] एस. सी. आर. 842); पन्नालाल बिंजराज बनाम। भारत संघ,

[1957] एस. सी. आर. 233 पर 248,256,262); सरदार इंदर सिंह बनाम। राजस्थान राज्य ([1957] एस. सी. आर. 605)। सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियम चले जाएंगे।

उसी विधानमंडल के समक्ष जांच के लिए जिसने विधेयक पारित किया था और जब विधानमंडल द्वारा पारित किया जाएगा तो नियम अधिनियम का हिस्सा बन जाएंगे। यह वास्तव में अच्छा नहीं था।

गेटेड कानून लेकिन दो चरणों में कानून।

सार्वभौमिक मुफ्त शिक्षा के लिए नागरिकों के अधिकारों को नष्ट नहीं कर सकते। अगर अल्पसंख्यक सरकारी सहायता चाहते हैं और उनके स्कूलों के लिए मान्यता, वे हो सकता है

लागू होने वाले सामान्य नियमों और शर्तों पर दिया गया

दूसरों के लिए सक्षम। उनकी पसंद के 'सी' शब्दों की व्याख्या कर दाता के धन की सहायता से और उन स्कूलों में जाने के लिए पर्याप्त छात्रों के आश्वासन के साथ स्कूलों की स्थापना के रूप में नहीं की जा सकती है।

केरल में ईसाई और मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं। ईसाई, दूसरा सबसे बड़ा समुदाय बनाते हुए,

आबादी का एक चौथाई हिस्सा मुस्लिमों का था, जबकि तीसरा सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिमों का था, जो कुल आबादी का सातवां हिस्सा था। में अल्पसंख्यकों

संविधान के तहत गारंटीकृत शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ का अर्थ केवल राज्य के विशेष क्षेत्रों में आबादी के उन वर्गों से है जो एक छोटे वर्ग में हैं, न कि उन लोगों से जिन्हें पूरे देश में अल्पसंख्यक माना जा सकता है। एकमात्र अल्पसंख्यक समुदाय केरल में ऐसा राज्य जो कला के लाभ का दावा कर सकता है। 30 (1) यहूदी हैं, जो अपना नहीं चुनते हैं

शैक्षणिक संस्थान।

केरल में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूल नहीं थे

कला द्वारा परिकल्पित रूप से अल्पसंख्यक विद्यालय। 30 (1) क्योंकि वे मुख्य रूप से एस. सी. आर. के बच्चों के लिए नहीं चलाए जाते थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1011

अल्पसंख्यक समुदाय। इनमें से अधिकांश विद्यालयों में कम से कम 75 प्रतिशत। इनमें से कई छात्र गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से थे। अनुच्छेद 30 (1) केवल अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की शिक्षा के लिए स्कूलों पर विचार करता है। अल्पसंख्यक समुदायों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार

अपनी पसंद के संस्थानों में अपनी शर्तों पर सहायता और मान्यता प्राप्त करने का अधिकार शामिल नहीं है। अनुच्छेद 30 (2) केवल राज्य को किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित करता है।

धर्म या भाषा का आधार।

कला के संचालन को आकर्षित करने के लिए। 30 (1) यह

यह स्थापित किया जाना चाहिए कि एक अल्पसंख्यक समुदाय है, कि इसने एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की है और यह कि शैक्षणिक संस्थान के लिए चलाया जाता है

उस समुदाय के सदस्यों की शिक्षा। रमानी कांता बोस बनाम। गुवाहाटी विश्वविद्यालय (आई. एल. आर. [1951]

गांड। 348 352 पर)। इनमें से कोई भी शर्त पूर्ण नहीं है।

राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भरा हुआ। कला में चयन। 30 (1) यह एक विद्यालय की स्थापना में निहित है न कि उसके प्रबंधन में।

स्थापना से संबंधित विधेयक के प्रावधान

विद्यालयों की संस्तुति और मान्यता, विद्यालय की संपत्ति के अलगाव पर प्रतिबंध, प्रबंधकों की नियुक्ति,

राज्य लोक सेवा द्वारा शिक्षकों का चयन

आयोग और प्रबंधन का अधिग्रहण

लोक हित में सभी स्कूल उचित स्थिति में हैं।

शिक्षा के बेहतर संगठन और शिक्षकों के लिए सेवा शर्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए।

विद्यालयों की वह श्रेणी जिसके संबंध में

अधिग्रहण की शक्ति का प्रयोग सी. एल. के तहत किया जा सकता है। 15 में से

विधेयक एक वर्गीकरण के तहत आता है जो अलग है

इसे उन अन्य श्रेणियों से अलग करता है जिन्हें वर्गीकरण से बाहर रखा गया है जैसे कि गणना की जाती है कानून में अंतर्निहित उद्देश्यों और नीतियों को आगे बढ़ाना। खंड 15 कला का उल्लंघन नहीं करता है। 14 में

सभी।

सी. एल. लागू करने में। 33 विधेयक का राज्य विधानमंडल

इरादा नहीं था, और ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कला के संचालन को प्रभावित करने का इरादा। 226 किसी भी तरह से।

एस. ईश्वर अय्यर और के. आर. चौधरी

केरल निजी माध्यमिक विद्यालय कार्यालय कर्मचारी 1012

एसोसिएशन और केरल प्राइवेट टीचर्स फेडरेशन,

डी. एन. प्रित के तर्कों को अपनाया।

ला

कर्र। एड. वैल्ट।

1958. 22 मई। दास सी. जे., भगवती की राय,

बी. पी. सिन्हा, जाफर इमाम, एस. के. दास और जे. एल. कपूर,

जे जे। दास सी. जे. वेंकटरामा अय्यर द्वारा दिया गया था जे. ने एक अलग राय दी।

डी. ए. एस. सी. जे.-यह संदर्भ द्वारा दिया गया है

कला के तहत राष्ट्रपति। 143 (1) के संविधान से

कुछ प्रश्नों पर इस न्यायालय की राय के लिए भारत काफी सार्वजनिक महत्व के कानून कि

के कुछ प्रावधानों से उत्पन्न हुए हैं या उन्हें छू रहे हैं

केरल शिक्षा विधेयक, 1957, इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है। "उक्त विधेयक" के रूप में, जिसे पारित किया गया था

केरल राज्य की विधान सभा

2 सितंबर, 1957, और कला के तहत था। 200 , आरक्षित

केरल के राज्यपाल द्वारा विचार के लिए

राष्ट्रपति। के गुजरने के तथ्य का पाठ करने के बाद

केरल विधान सभा द्वारा उक्त विधेयक

और इसके राज्यपाल द्वारा इसके लिए आरक्षण

राष्ट्रपति का विचार और बाहर निकलने के बाद

उक्त विधेयक के कुछ खंड और विशिष्टताएँ

उन संदेहों को दूर करना जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे उत्पन्न हुए हैं

डेंट ने इस न्यायालय को कुछ प्रश्न भेजे हैं इसके बाद विचार के लिए उल्लेख किया गया है और

फिर भी राष्ट्रपति की सहमति से संदेह प्राप्त हुए, इस संदर्भ तक पहुँचते हुए, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है

किसी के वास्तविक अनुप्रयोग से उत्पन्न होने के लिए

किसी भी पक्ष के तथ्यों पर किसी अधिनियम की निर्दिष्ट धारा कुलर केस और तदनुसार प्रश्न जो हैं

इस न्यायालय को इसके विचार के लिए भेजा गया है

अनिवार्य रूप से एक अमूर्त या काल्पनिक प्रकृति का और

किसी विशेष मामले में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों की तरह नहीं हैं पीड़ित पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष लाया गया

किसी विशेष कानून का संचालन जिस पर वह आक्षेप करता है।

इसके अलावा, इस संदर्भ को इस रूप में वर्णित किया गया है

उसमें अपूर्ण और असंतोषजनक, के अनुसार कुछ संस्थानों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

यह स्पष्ट रूप से सभी संवैधानिक एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों को सामने नहीं लाता है।

1013

विधेयक के प्रावधानों से जुड़ी खामियां और गंभीर आशंका हमारे समक्ष विद्वान वकील द्वारा व्यक्त की गई है कि इन अलग-अलग अमूर्त या काल्पनिक प्रश्नों पर हमारी राय उन संस्थानों के हितों को बहुत सकारात्मक रूप से पूर्वाग्रहित कर सकती है, यदि वे पूरी तरह से अस्तित्व को नष्ट नहीं करते हैं, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और परिस्थितियों में, हमें इस संदर्भ को स्वीकार करने या कोई सलाहकार राय देने के लिए नहीं कहा गया है।

हमसे पूछे गए प्रश्नों पर।

शुरुआत में विज्ञापन देना फायदेमंद हो सकता है,

अधिकारिता के दायरे और दायरे के लिए

कला के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया। 143 में से

संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान या ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

अधिनियम, 1900 (63 और 64 विक। च. 12) और, सहमति

विशेष रूप से, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायशास्त्र राष्ट्र और न्यायालय की शक्तियां केवल उसके समक्ष आने वाले ठोस मामलों के निर्णय तक फैली हुई हैं, उन्होंने कार्यपालिका को सलाहकार राय देने से इनकार कर दिया है या

राज्य की विधायी शाखाएँ। एस के तहत। 60 में से कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम, 1906, गवर्नर

सामान्य परिषद महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख कर सकती है -

उच्चतम न्यायालय के कुछ मामलों से संबंधित कानून

और ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय आयोजित किया गया था

संदर्भ का मनोरंजन करने और जवाब देने के लिए बाध्य

उस पर सवाल उठाए। फिर भी, प्रिवी काउंसिल

इस तरह की सलाहकार राय के खतरों की ओर इशारा किया है

और सामान्य सिद्धांतों पर इस तरह का अवमूल्यन किया है

संदर्भ। हेल्सबरी एल. सी. के अर्ल ने कहा

ओंटारियो के लिए महान्यायवादी बनाम। हैमिल्टन स्ट्रीट रेल

तरीका (1): —

वे अटकलबाजी के रूप में बेकार होंगे।

काल्पनिक प्रश्नों पर राय। यह होगा

सिद्धांत के विपरीत, असुविधाजनक और अक्षम

कि ऐसे प्रश्नों पर राय को बिल्कुल भी त्याग दिया जाना चाहिए। जब वे उठती हैं, तो उन्हें कंक्रीट में उठना चाहिए

निजी अधिकारों से जुड़े मामले; और यह होगा

किसी भी न्यायिक न्यायाधिकरण के लिए प्रयास करना अत्यंत मूर्खतापूर्ण है।

सभी संभावित मामलों और तथ्यों को समाप्त करने के लिए पहले से

(1) [1903] ए. सी. 524,529।

आई 1014

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1959]

जो अर्हता प्राप्त करने, कटौती करने और ओवरराइड करने के लिए हो सकता है

विशेष शब्दों का संचालन जब

ठोस मामला उसके सामने नहीं है।

ब्रिटिश कोलंबिया बनाम के लिए अटॉर्नी जनरल में लॉर्ड हाल्डेन की टिप्पणियाँ इसी तरह के प्रभाव वाली हैं। कनाडा के लिए महान्यायवादी (1):

" ..... इस प्रक्रिया के तहत सवाल पूछे जा सकते हैं।

एक प्रकार का जिसका संतोषजनक जवाब देना असंभव है। न केवल भविष्य के वादियों के प्रश्न को अदालत द्वारा किसी भी संदर्भ या संबंध के बिना एक अमूर्त रूप में सिद्धांतों को निर्धारित करने से पूर्वाग्रहित किया जा सकता है

वास्तविक तथ्य, लेकिन किसी सिद्धांत को पर्याप्त रूप से और सुरक्षित रूप से परिभाषित करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो सकता है, बिना उन सटीक तथ्यों के पूर्व निर्धारण के जिन पर इसे लागू किया जाना है।

लाभ के साथ, संदर्भ भी दिया जा सकता है

में लॉर्ड सेंकी एल. सी. की टिप्पणियों के बाद

रे एयरोनॉटिक्स का विनियमन और नियंत्रण

कनाडा (3):

" ..... यह अवांछनीय है कि न्यायालय को होना चाहिए

उन रायों को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है जो उन व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं जो इसके समक्ष प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं या इस तरह के मामलों को छू सकते हैं कि इसके जवाब उन पक्षों के संबंध में पूरी तरह से अप्रभावी होने चाहिए जो इसके सामने नहीं हैं और जिन्हें नहीं लाया जा सकता है-उदाहरण के लिए, विदेशी सरकार।

न्यायिक समिति अधिनियम, 1833 की धारा 4 (3 और 4 विलियम IV, Ch. 41) यह प्रावधान करता है कि "महामहिम के लिए यह वैध होगा कि वह किसी भी ऐसे अन्य मामले की सुनवाई और विचार के लिए उक्त न्यायिक समिति को संदर्भित करें जो महामहिम उचित समझते हैं और ऐसे मामले।

इसके बाद समिति इसे सुनेगी और उस पर विचार करेगी और महामहिम को पहले बताए गए तरीके से सलाह देगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायिक समिति के लिए यह सुनना और विचार करना अनिवार्य कर दिया गया है

मामला और उस पर महामहिम को सलाह दें। शासन भारत अधिनियम, 1935 की धारा। 213 (1) , गवर्नर-जनरल को संघीय न्यायालय से परामर्श करने के लिए अधिकृत किया गया, यदि

किसी भी समय गवर्नर-जनरल को यह प्रतीत हुआ कि कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ था या उत्पन्न होने की संभावना थी

(2) [1932] ए. सी. 54,66।

(1) [1914] ए. सी. 153,162।

एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1015

ऐसी प्रकृति की और ऐसी सार्वजनिक विधि यह महत्वपूर्ण है कि इस पर संघीय न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन था और यह अधिकार दिया गया था कि

न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद, जिस पर वे उचित समझते हैं, गवर्नर-जनरल को रिपोर्ट करें। इस प्रावधान को तब से शब्द दर शब्द पुनः प्रस्तुत किया गया है, सिवाय अदालत के नाम के, सी. एल. में। (1) हमारे संविधान का अनुच्छेद 143। उस अनुच्छेद में एक नया खंड है, जो सी. एल. है। (2) जो राष्ट्रपति को कुछ भी होने के बावजूद अधिकार देता है

कला के लिए प्रावधान। 131 , उक्त खंड में उल्लिखित प्रकार के विवाद को राय के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करना और सर्वोच्च न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय के बारे में सूचित करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि, जबकि

सीएल के तहत। (2) इस न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी निर्देश पर विचार करे और राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय बताए, इस न्यायालय ने सी. एल. के तहत कहा है। (1) , मामले में विवेकाधिकार और उचित मामले में और अच्छे कारणों से हो सकता है

उप-प्रश्नों पर कोई राय व्यक्त करने से इनकार करना उस पर चढ़ गए। एस में उपयोग की जाने वाली भाषा को देखते हुए। 213 (1) , किस कला पर? 143 (1) हमारे संविधान का आधार है,

से, कला के तहत किए गए संदर्भ का दायरा। 143 (1) है। स्पष्ट रूप से एस के तहत एक संदर्भ से अलग है। 4

कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम, 1906 और यह न्यायालय, कला के तहत। 143 (1) , मामले में विवेक है और

फलस्वरूप उनके प्रभुत्त्व की टिप्पणियाँ

ऊपर उद्धृत प्रिवी काउंसिल काफी उपयुक्त है

और इसे ध्यान में रखना होगा।

सभी को चार संदर्भ बताए गए हैं

गवर्नर-एस के तहत जनरल। 213 (1) भारत सरकार अधिनियम, 1935 और उनमें से दो में से कुछ

संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों ने टिप्पणियां की हैं

इस तरह के संदर्भ के दायरे और दायरे पर। इस प्रकार

भूमि और भवनों के पुनः आवंटन (1) में, ग्वायर सी. जे. उन्होंने कहाः

" प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार करने पर

मामले में, हमें कुछ संदेह महसूस हुआ कि क्या कोई उपयोगी उद्देश्य है

(1) [1943] एफ. सी. आर. 20,22

1016

एस के तहत एक राय देकर सेवा की जाएगी। 213 अधिनियम से। उस धारा की शर्तें न्यायालय पर कोई दायित्व नहीं लगाती हैं, हालाँकि हमें हमेशा एक संदर्भ को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, सिवाय अच्छे कारण के; और दो कठिनाइयाँ सामने आईं। सबसे पहले, ऐसा लगता था कि स्वामित्व के प्रश्न जल्द या बाद में शामिल हो सकते हैं, यदि सरकार, जिसकी दलीलों को न्यायालय का समर्थन मिला, चाहे, जैसा कि कागजातों से पता चलता है, कि कुछ भूमि का निपटान निजी व्यक्तियों को किया जाए, और स्पष्ट रूप से एस के तहत कोई सलाहकार राय नहीं। 213 एस के तहत ली गई कार्यवाहियों में इस न्यायालय की घोषणा से उत्पन्न होने वाले शीर्षक की एक अच्छी जड़ प्रदान करेगा। 204 (1) एक सरकार द्वारा दूसरे के विरुद्ध अधिनियम। इन री लेवी ऑफ एस्टेट ड्यूटी (1) स्पेंस सी. जे. ने पी. 320 अधिकृत रिपोर्टः

" शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि जब पार्लियामेंट ने एस को लागू करने के लिए उचित सोचा है। 213 संविधान अधिनियम के अनुसार, हमारे निर्णय में न्यायालय के लिए यह नहीं है कि वह सलाहकार क्षेत्राधिकार की अक्षमता (एक निश्चित विचारधारा के अनुसार) पर जोर दे। न ही यह कहने में सहायता करता है कि न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्रश्नों पर व्यक्त की गई राय का "विधि अधिकारियों की राय से अधिक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा": अटॉर्नी-ओंटारियो के लिए जीन राल बनाम। अटॉर्नी-कनाडा के लिए जनरल (2)। यह अधिकार क्षेत्र होने का आवश्यक परिणाम है

सलाहकार "। इस आपत्ति का उल्लेख करते हुए कि प्रश्न विचार किए गए विधान से संबंधित हैं और किसी उपाय की वैधता या संचालन से संबंधित नहीं हैं, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने पी। 321 :

" यह तथ्य कि संदर्भित प्रश्न भविष्य के विधान से संबंधित हैं, अपने आप में ऐसा नहीं माना जा सकता है -

वैध आपत्ति। धारा 214 गवर्नर जनरल को कानून के सवाल "उत्पन्न होने की संभावना" होने पर संदर्भ देने का अधिकार देती है।

इस वर्ग के मामलों में, संदर्भ, चीजों की प्रकृति में, कानून बनने से पहले किया जाना चाहिए।

(1) [1944] एफ. सी. आर. 317,320,321,35°।

(2) [1912] ए. जी 571,589।

एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1017

प्रस्तुत किया गया और परिकल्पना के आधार पर आपत्ति प्रश्नों के शाब्दिक चरित्र में कोई बल नहीं हो सकता है। हम.

हालाँकि, यह जोड़ा जा सकता है कि उदाहरण हमारे लिए लाए गए थे सूचना जिसमें इसके तहत संदर्भ दिए गए थे

कनाडाई सुप्रीम में संबंधित प्रावधान

न्यायालय अधिनियम जब मामला एक स्तर पर था

जफरुल्ला खान जे. ने इस संदर्भ पर विचार करने से इनकार कर दिया। और उच्च प्राधिकारी के प्रश्नों का उत्तर देना

अपनी अलग राय में विस्तृत रूप से उद्धृत और चर्चा की। विद्वान न्यायाधीश ने अपनी राय के पहले भाग में यह इंगित करने के बाद कि यह एक अधिकार क्षेत्र था जिसका प्रयोग सभी अवसरों पर नाजुकता और सावधानी का विषय होना चाहिए, पृष्ठ 350 पर निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपनी राय का समापन किया:

" उपलब्ध कराई गई सामग्री की स्थिति में

मुझे नहीं लगता कि कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा

संदर्भित प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के मेरे प्रयास से। वास्तव में, मुझे आशंका है कि इस तरह के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप दी गई राय को अंतहीन मुकदमेबाजी की नींव बनाया जा सकता है, इसके अलावा प्रस्तावित कानून के अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रश्न से अलग, और उन व्यक्तियों के गंभीर पूर्वाग्रह के लिए काम कर सकता है जिनके साथ उस कानून की शरारत लाने का प्रयास किया जा सकता है। यह किसी भी चीज़ की तुलना में कहीं अधिक परेशान करने वाले भूतों को उठाने के लिए बाध्य है जो यह रखने का काम कर सकता है। इन कारणों से मैं मजबूर हूँ इस पर कोई भी राय व्यक्त करने से इनकार करने के लिए

संदर्भित प्रश्न "।

वर्तमान संदर्भ अपनी तरह का दूसरा है

कला. 143 (1) संविधान के अनुसार, पहला दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 (1) से जुड़ा हुआ है। कला के तहत संदर्भ की प्रकृति और दायरा। 143 (1) दिल्ली कानून अधिनियम मामले (1) में चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन हम मानते हैं कि न्यायिक समिति और संघीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का हवाला दिया गया था।

उपरोक्त इस न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को इंगित करने वाले एक मूल्यवान मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

अब हमारे सामने संदर्भ से निपटने और निपटाने में। न्यायपालिका द्वारा स्थापित सिद्धांत

(1) [1951] एससीआर 747।

[1959]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1018

निर्णय स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यह शिकायत कि हमारे पास भेजे गए प्रश्न किसी कानून की वैधता से संबंधित नहीं हैं, बल्कि उस विधेयक की वैधता से संबंधित हैं, जिसे अभी तक राष्ट्रपति की सहमति से कानून में पारित नहीं किया गया है, जैसा कि स्पेंस सी. जे. आर्ट द्वारा कहा गया है, उस संदर्भ को स्वीकार नहीं करने के लिए एक अच्छा आधार नहीं है। 143 (1) कानून के किसी प्रश्न के संदर्भ पर विचार करता है

यह "उत्पन्न होने की संभावना" है। यह तर्क दिया जाता है कि कई अन्य संवैधानिक आपत्तियाँ भी कुछ से उत्पन्न होती हैं

के आलोक में विचार किए गए विधेयक के प्रावधानों का

संविधान के अन्य प्रावधान, जैसे, अनुच्छेद। 19 (1) (जी)

और कला। 337 और जैसा कि उन आपत्तियों में नहीं है

इस न्यायालय को संदर्भ में शामिल नहीं किया जाना चाहिए

दिए गए उत्तरों के लिए एक अपूर्ण संदर्भ का उपयोग करें

दी गई प्रश्नों की अनुपस्थिति में भ्रामक हो सकता है

उत्पन्न होने वाले अन्य प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले

राष्ट्रपति को यह निर्धारित करना है कि क्या प्रश्नों को संदर्भित किया जाना चाहिए और यदि वह प्रवेश नहीं करता है

अन्य प्रावधानों पर कोई गंभीर संदेह नहीं है

किसी भी पक्ष के लिए यह कहना कि उनमें से भी संदेह उत्पन्न होते हैं

और हम संदर्भ से परे नहीं जा सकते और चर्चा नहीं कर सकते

उन समस्याओं को। ऐसी स्थिति जिसमें राष्ट्रपति

अन्य प्रश्नों को संदर्भित करना उचित नहीं समझा है

बिल ने इस आधार पर कहा कि वे दूसरों का उल्लंघन करते हैं संविधान के प्रावधान अच्छे या अच्छे नहीं हो सकते हैं।

इस संदर्भ को स्वीकार करने से इनकार करने का ठोस कारण

और मामलों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें

जिनका राष्ट्रपति सम्मान करते हैं सन्देह हो रहा है।

सही अर्थ को समझने के लिए, आयात और

उक्त विधेयक के प्रावधानों के निहितार्थ संदेह को जन्म देने के लिए, यह आवश्यक होगा कि

जिनका निम्नलिखित प्रश्नों पर प्रभाव पड़ सकता है विचार और फिर के वास्तविक प्रावधानों के लिए

बिल। प्रेरक और उदात्त रूप से व्यक्त प्रस्तावना

हमारा संविधान के गंभीर संकल्प को दर्ज करता है भारत को एक संप्रभु देश बनाने के लिए भारत के लोग

लोकतांत्रिक गणराज्य और, अन्य के बीच

अपने सभी नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए,

स्वतंत्रता और समानता और 1019 के बीच बढ़ावा देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

वे सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देते हैं। इस प्रकार, हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक अपने सभी नागरिकों को विचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

दबाव, विश्वास, विश्वास और पूजा। कुछ भी उत्तेजित नहीं करता है और लोगों में विचार और अभिव्यक्ति को अधिक उत्तेजित करता है

शिक्षा से अधिक। यह शिक्षा ही है जो हमें स्पष्ट करती है

विश्वास और विश्वास और हमारी पूजा की भावना को मजबूत करने में मदद करता है। प्रस्तावना के भाग II में उल्लिखित इन सर्वोच्च उद्देश्यों को लागू करना और मजबूत करना।

हमारे संविधान ने हमें कुछ मूलभूत मानसिक अधिकार प्रदान किए हैं। अनुच्छेद 14, जो लेखों में से एक है

दो प्रश्नों में संदर्भित, गारंटी प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक या अन्यथा, का समान संरक्षण

भारत के क्षेत्र के भीतर कानून। अनुच्छेद 16

सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है

नियुक्ति या नियुक्ति से संबंधित मामले

राज्य के अधीन कोई भी कार्यालय। ताकि उनका लाभ उठाया जा सके। इस अनुच्छेद से सभी नागरिकों को लाभ होगा।

संभवतः समान अवसर होना चाहिए

योग्यता प्राप्त करना, शैक्षणिक या अन्यथा,

ऐसी नियुक्ति या नियुक्ति के लिए आवश्यक।

अनुच्छेद 19 (1) नागरिकों को इन अधिकारों की गारंटी देता है।

अन्य, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए (उप-क्ल।

(क) और किसी भी पेशे का अभ्यास करना, या किसी भी पेशे को जारी रखना।

व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय (उप-क्ल। (जी))। ये हैं अधिकार

हालाँकि, द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण के अधीन हैं

ओल्स। (2) और (6) कला का। 19. कला के तहत। 25 सभी लोग हैं

समान रूप से हकदार, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और

स्वास्थ्य और भाग III के अन्य प्रावधानों के लिए,

विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने का अधिकार, धर्म का पालन और प्रचार करें। अनुच्छेद 26 में कहा गया है -

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय का मौलिक अधिकार या उसकी कोई भी धारा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता के अधीन

और स्वास्थ्य, संस्थानों की स्थापना और रखरखाव के लिए

धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य, अपने स्वयं के प्रबंधन के लिए धर्म के मामलों में, संपत्ति अर्जित करने के लिए और

कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करना।

भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने का आदर्श है। बता दें, कला के तहत कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। 28 (1) , को

किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पूरी तरह से प्रदान किया जाए राज्य निधि से बाहर और उसके तहत बनाए रखा। सी. एल.

1020 समान अनुच्छेद कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षा में भाग नहीं ले रहा है

राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त करने वाली संस्था

इला।

किसी भी कार्य में भाग लेने के लिए राज्य निधि की आवश्यकता होती है। धार्मिक शिक्षा जो इस प्रकार दी जा सकती है

संस्था या किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए

ऐसी संस्था में या किसी पूर्व में आयोजित किया जा सकता है

जब तक कि ऐसा व्यक्ति या यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, तो उसके अभिभावक ने उसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है। अनुच्छेद 29 (1) नागरिकों के किसी भी वर्ग को एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति प्रदान करता है। इसे संरक्षित करने का अपना अधिकार है।

उस अनुच्छेद के खंड (2) में प्रावधान है कि कोई भी नागरिक

किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार किया जाए राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य से बाहर सहायता प्राप्त करना

केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा के आधार पर धन उम्र या उनमें से कोई भी। अनुच्छेद 30, सीएल। (1) जिनका विषय इस संदर्भ के प्रश्न 2 का विषय है, इस प्रकार चलता है

निम्नलिखित है:

66 30 (1) सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म पर आधारित हों

या भाषा को स्थापित करने का अधिकार होगा और

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करें।

(2) राज्य शिक्षा को सहायता देने में मदद नहीं करेगा।

राष्ट्रीय संस्थान, किसी भी शिक्षा के खिलाफ भेदभाव करते हैं राष्ट्रीय संस्था इस आधार पर कि यह इसके अधीन है

अल्पसंख्यक समुदाय का प्रबंधन, चाहे वह धर्म पर आधारित हो। या भाषा "।

जबकि हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी है

संविधान का भाग III, इसका भाग IV,

दूसरी ओर, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है

राज्य की नीति। उस भाग में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन सिद्धांत

फिर भी, इसमें निर्धारित मौलिक हैं - देश का शासन और यह कर्तव्य होगा

कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य।

अनुच्छेद 39 राज्य को अपनी नीति को इस दिशा में निर्देशित करने का आदेश देता है अन्य बातों के अलावा, यह सुनिश्चित करना कि नागरिक, पुरुष

और महिलाओं को, समान रूप से, पर्याप्त अधिकार है आजीविका के साधन। अनुच्छेद 41 राज्य से अपेक्षा करता है,

अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर

निवेश, सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए

सही, अन्य बातों के साथ-साथ, शिक्षा के लिए। कला के तहत।

संविधान के प्रारंभ से दस साल की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, जब तक कि

वे चौदह वर्ष की आयु पूरी करते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य से लोगों के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने की अपेक्षा करता है।

हमारे संविधान का भाग XVI भी यह सुनिश्चित करता है कि

कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। इस प्रकार

कला. 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 331 में लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। आरक्षण कला द्वारा किया जाता है। 332 और 333, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए और अनुसूचत जनजाति और एंग्लो-इंडियंस प्रत्येक राज्य की विधान सभा में दस साल के लिए, जिसके बाद, कला के अनुसार। 334 , ये विशेष प्रावधान समाप्त होने वाले हैं। विशेष प्रावधान भी किया जाता है

कला. 336 एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए

कुछ सेवाओं में नियुक्ति का मामला। अनुच्छेद 337

इसका हमारे सामने के प्रश्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह प्रावधान है कि पहले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान

इस संविधान के प्रारंभ के बाद, वही

अनुदान, यदि कोई हो, संघ द्वारा और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए प्रत्येक राज्य

31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में शिक्षा के संबंध में जो प्रावधान किए गए थे,

1948 और यह कि तीन की प्रत्येक सफल अवधि के दौरान

वर्षों तक यह अनुदान दस प्रतिशत कम हो सकता है। तीन की तुरंत पिछली अवधि के लिए उन लोगों की तुलना में वर्ष, बशर्ते कि संविधान के प्रारंभ से दस वर्षों के अंत में ऐसे अनुदान, जिस हद तक वे एक विशेष रियायत हैं,

रुकिए। हालाँकि, उस आर्टिएल के लिए दूसरा प्रावधान,

यह प्रावधान है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं होगा

इस अनुच्छेद के तहत कोई भी अनुदान प्राप्त करने का हकदार है जब तक कि

कम से कम चालीस प्रतिशत। वहाँ वार्षिक प्रवेश समुदायों के सदस्यों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

एंग्लो-इंडियन समुदाय के अलावा। यह 1022 है।

स्पष्ट रूप से एक शर्त जो स्वयं संविधान द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्राप्त करने के अधिकार पर लगाई गई थी

ज़ा

इस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अनुदान। अनुच्छेद 366 (2)

"एंग्लो-इंडियन" को परिभाषित करता है।

संभवतः उपरोक्त निर्देशात्मक सिद्धांतों को लागू करने के लिए केरल विधान सभा ने

कला द्वारा इसे प्रदत्त शक्ति। 245 और संविधान के 246 को सूची II की प्रविष्टि 11 के साथ पढ़ा गया संविधान की सातवीं अनुसूची। हालाँकि, इस विधायी शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद के तहत किया जाना है। 245

66 इस संविधान के प्रावधानों के अधीन "। इसलिए, हालांकि यह कानून हो सकता है

निर्देशात्मक सिद्धांतों द्वारा उस पर लगाए गए दायित्व के निर्वहन में केरल राज्य द्वारा किया गया कार्य

संविधान के भाग IV में निहित, यह होना चाहिए,

फिर भी, समर्पण करें और अति न करें-आरती के प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए मानसिक अधिकारों का उपयोग करें।

संविधान के भाग III में निहित क्लेस और

ऊपर उल्लिखित। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मद्रास राज्य बनाम में समझाया गया है। श्रीमती. चंपकम दोराईराजन (*) और हाल ही में मोहम्मद में दोहराया गया। हनीफ कुरेशी बनाम।

बिहार राज्य (2) "के निर्देशक सिद्धांत राज्य की नीति को सहायक के रूप में पालन और संचालन करना होगा।

मौलिक अधिकारों पर अध्याय "। कभी नहीं

या निकाय न्यायालय इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता है में निर्धारित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

संविधान का भाग IV लेकिन इसे अपनाना चाहिए

सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत और चाहिए दोनों को यथासंभव प्रभावी बनाने का प्रयास करें।

उपरोक्त निर्माण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए

हम अब स्पष्ट संदर्भ प्राप्त करने के लिए उक्त विधेयक के प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

उसमें से।

उक्त विधेयक का लंबा शीर्षक इसे "राज्य में शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर संगठन और विकास के लिए एक विधेयक" के रूप में वर्णित करता है। इसकी प्रस्तावना इस प्रकार है: " जबकि इसे प्रो के लिए आवश्यक माना जाता है

(1) [1951] एस. सी. आर. 525,531

(2) [1959] एस. सी. आर 629

एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1023

राज्य में विभिन्न प्रकार की और व्यापक शैक्षणिक सेवा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर संगठन और विकास के लिए

राज्य "। इसलिए, हमें नीति के आलोक में उक्त विधेयक के मूल प्रावधानों से संपर्क करना चाहिए।

सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से लागू होगी और विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं। इस विधेयक के संकेत-एक ऐसा तथ्य जो संकेत देता है कि सरकार स्थिति का अध्ययन करेगी और इसे लागू करेगी।

उक्त विधेयक के ऐसे प्रावधानों को लागू करना जो अपने लोगों की वास्तविक जरूरतों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा। खंड 2 में उक्त विधेयक में उपयोग किए गए कुछ शब्दों की परिभाषाएँ हैं जिनमें से निम्नलिखित उपखंड हो सकते हैं -

नोट किया:

" (1) " सहायता प्राप्त विद्यालय का अर्थ है एक निजी विद्यालय जो

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सहायता प्राप्त कर रहा है;

(3) " विद्यमान विद्यालय "से कोई सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है।

या कॉम से पहले स्थापित सरकारी स्कूल

इस अधिनियम का उल्लेख और इस प्रकार जारी रहना - इस तरह की शुरुआत;

(6) " निजी विद्यालय "से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है।

(7) “ मान्यता प्राप्त "का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक निजी विद्यालय"।

खंड 3 "विद्यालयों की स्थापना और मान्यता" से संबंधित है। उपखंड (1) सरकार को "सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के प्राथमिक और अन्य चरणों और निर्देश के पाठ्यक्रमों को विनियमित करने" का अधिकार देता है।

उपखंड (2) सरकार से "समय-समय पर ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा करता है जो वे उठा सकें।

सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन

[1959]

और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए "। उपखंड (3) में प्रावधान है कि "सरकार, प्रो के उद्देश्य के लिए

ऐसी सुविधाओं का उपयोग करना: -(क) विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव; या (ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव की अनुमति देना; या (ग) किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित और बनाए गए किसी भी विद्यालय को मान्यता देना।

या व्यक्तियों का शरीर "। सभी मौजूदा विद्यालय, जिनका परिभाषा के अनुसार कोई भी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त या सरकारी विद्यालय हैं, जो विधेयक के प्रारंभ से पहले स्थापित किए गए हैं और जो जारी हैं, उपखंड द्वारा हैं। (4) इस विधेयक के अनुसार स्थापित किया गया माना जाए। उपखंड (4) का परंतुक मौजूदा सहायता प्राप्त विद्यालय की शैक्षणिक एजेंसी को एक विकल्प देता है।

उस खंड के प्रारंभ पर, सरकार को ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना देने के बाद, ऐसे प्रारंभ के एक महीने के भीतर किसी भी समय, उसमें उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन स्कूल को एक मान्यता प्राप्त स्कूल के रूप में चलाने का विकल्प चुनना। सी. एल. का उपखंड (5)। 3 , जो, आंशिक रूप से, संदर्भित प्रश्नों में से दो की विषय वस्तु निम्नानुसार है:

" 3 (5) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद,

किसी नए विद्यालय की स्थापना या किसी निजी विद्यालय में उच्च कक्षा का उद्घाटन इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा और कोई भी विद्यालय या उच्च वर्ग जो इस तरह के दृष्टिकोण के अनुसार स्थापित या खोला गया है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। विधेयक के खंड 4 में एक राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है जिसमें अधिकारी और गैर-अधिकारी शामिल हैं, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, उनका कार्यकाल और उनके कर्तव्य। इस तरह के बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य यह है कि वह शिक्षा विभाग की शिक्षा नीति और प्रशासन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह दे। खंड 5 प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन प्रत्येक सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक से सरकार के अधिकृत अधिकारी को संपत्तियों की एक सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है।

स्कूल के चलने योग्य और अचल। ऐसी सूची प्रस्तुत करने में चूक उप-सी. एल. के तहत होती है। (2) उस खंड का, रखरखाव अनुदान को रोकना।

खंड 6 किसी भी एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के अलगाव पर प्रतिबंध लगाता है।

1025

सहायता प्राप्त विद्यालय की संपत्ति, सिवाय सरकार के अधिकृत अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के। आदेश के खिलाफ अपील की जाती है।

ऐसा करने से इनकार करने या देने वाले प्राधिकृत अधिकारी का

उप-क्ल के तहत अनुमति। (1) . उपखंड (3) उपखंड के उल्लंघन में किसी भी लेनदेन को प्रस्तुत करता है। (1) या उप-सी. एल. (2) शून्य और इस तरह के उल्लंघन पर

सरकार, उप-क्ल के तहत। (4) , के लिए अधिकृत है स्कूल को कोई भी अनुदान दें। खंड 7 से संबंधित है -

सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक। उपखंड (1) किसी भी शिक्षा एजेंसी को किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है।

सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक, अधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के अधीन, सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी मौजूदा प्रबंधकों को उक्त विधेयक के तहत नियुक्त किया गया है। इस विधेयक के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अनुसार स्कूल के संचालन के लिए प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उप.

खंड (4) प्रबंधक का कर्तव्य बनाता है कि वह विद्यालय के ऐसे अभिलेख और खातों को बनाए रखे और

रीति जो नियमों द्वारा विहित की जाए। उप-क्ल द्वारा प्रबंधक है। (5) , सभी आवश्यक और उचित सहायता और सुविधाओं को वहन करने के लिए आवश्यक

विद्यालय और उसके अभिलेखों और खातों का निरीक्षण

अधिकृत अधिकारी द्वारा। उपखंड (6) प्रबंधक को अधिकृत अधिकारी को एक वर्ष का नोटिस दिए बिना किसी भी स्कूल को बंद करने से मना करता है जो उसके इरादे के किसी भी वर्ष 31 मई को समाप्त हो जाता है। उपखंड (7) में प्रावधान है कि स्कूल के बंद होने या बंद होने या इसकी मान्यता होने की स्थिति में

वापस लिए जाने पर, प्रबंधक स्कूल के सभी अभिलेखों और खातों को अधिकृत अधिकारी को सौंप देगा। उपखंड (8) उपखंडों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है। (6) और (7)। खंड 8 में देय राशियों की वसूली का प्रावधान है -

भूमि राजस्व के बकाया के रूप में सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रबंधक। सी. एल. का उपखंड (3)। 8 , जिसे एक प्रश्न में भी संदर्भित किया गया है, निम्नानुसार चलता है:

" 8 (3) विशेष शुल्क के अलावा सभी शुल्क और अन्य देय राशि

इस धारा के शुरू होने के बाद सहायता प्राप्त विद्यालय में छात्रों से एकत्र की गई फीस; किसी भी समझौते में कुछ भी निहित नहीं होने के साथ, योजना सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1959]

या व्यवस्था, सरकार को ऐसी रीति से सौंपी जाए जो विहित की जाए।

खंड 9 सरकार पर यह अनिवार्य बनाता है कि वह सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी शिक्षकों के वेतन का भुगतान सीधे या स्कूल के प्रधानाध्यापक के माध्यम से करे और भुगतान भी करे।

सहायता प्राप्त विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन। यह सरकार को यह निर्धारित करने की शक्ति देता है कि

सहायता प्राप्त विद्यालय की किसी भी भूमि, भवन या उपकरण की खरीद, सुधार और मरम्मत के लिए सहायता। खंड 10 सरकार से सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के पास होने वाली अर्हताओं को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ परिभाषा के अनुसार सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल है। राज्य लोक सेवा आयोग को सी. एल. में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार है। 11 . संक्षेप में, प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले लोक सेवा आयोग प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग उम्मीदवारों का चयन करेगा।

वर्ष के दौरान शिक्षकों की रिक्तियों की संभावित संख्या को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार चुने गए उम्मीदवारों की सूची राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और प्रबंधक उनकी नियुक्ति करेगा। सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक केवल उस जिले के लिए इस प्रकार चुने गए उम्मीदवारों में से हैं जिसमें विद्यालय स्थित है, बशर्ते कि प्रबंधक,

आयोग की अनुमति से किसी अन्य जिले के लिए चुने गए शिक्षकों की नियुक्ति पर्याप्त कारण से की जाती है। इस प्रकार प्रकाशित उम्मीदवारों की सूची से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी की जानी है। उम्मीदवारों के चयन में आयोग के पास होना चाहिए

सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों का ध्यान रखना

कला की धारा (4) के तहत। 16 संविधान का, अर्थात, शिक्षा सेवा में प्रतिनिधित्व देना

अनुसूचित जातियों या जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

1027

-एक प्रावधान जिसकी एंग्लो-इंडियन और मुस्लिम समुदायों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। खंड 12 सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करता है।

स्पष्ट रूप से कार्यकाल की कुछ सुरक्षा का खर्च उठाने का इरादा था

सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को। इसमें कहा गया है कि सरकारी शिक्षकों के लिए लागू वेतनमान

इस खंड से। शिक्षकों के लिए लागू नियम सरकारी स्कूलों को भी कुछ स्थानों पर आवेदन करना है।

उप-वर्ग में उल्लिखित सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक। (2) .

स्कूल को बर्खास्त किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, रैंक में कम किया जाएगा या प्रबंधक द्वारा पूर्व के बिना निलंबित किया गया

अधिकृत अधिकारी की मंजूरी। अन्य शर्तें

नियमों द्वारा निर्धारित। खंड 14 महत्वपूर्ण है। इसका महत्व यह है कि यह उपखंड (1) द्वारा प्रदान करता है कि

सरकार, जब भी यह प्रतीत होती है कि

किसी भी सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक ने प्रदर्शन करने में लापरवाही की है। विधेयक द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों में से कोई

उसके तहत बनाए गए नियम, और वह जनहित में

ऐसा करना आवश्यक है, हो सकता है, एक उचित देने के बाद

शैक्षिक अभिकरण के प्रबंधक को अवसर

प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने के लिए,

पाँच से अधिक अवधि के लिए प्रबंधन पर

वर्षों से। आपात स्थिति के मामलों में सरकार,

उप-क्ल के तहत। (2) , के बाद प्रबंधन को संभालें राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन

शैक्षणिक एजेंसी को कोई नोटिस दिए बिना

बिना किसी सूचना के शैक्षिक एजेंसी या प्रबंधक प्रकाशन के तीन महीने के भीतर

अधिसूचना के लिए, सरकार को आवेदन करें

इसके लिए कारण दर्शाते हुए विद्यालय का जीर्णोद्धार।

सरकार आदेश देने के लिए अधिकृत है जो के संबंध में आवश्यक या समीचीन हो सकता है

सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रबंधन संभालना।

उप-क्ल के अंतर्गत। (5) सरकार को इस तरह का किराया देना है

के संबंध में कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

कब्जे में ली गई संपत्तियाँ। किसी भी 1028 को लेने पर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1959]

इस स्कूल को चलाने के लिए सरकार अधिकृत है कोई विशेष शैक्षिक सुविधा जो विद्यालय में थी

इस तरह के अधिग्रहण से तुरंत पहले कर रहे हैं। का अधिकार

जिला न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील की जाती है

कलेक्टर द्वारा किराया तय करने का आदेश। उप-सी. एल. (8) बनाता है

सरकार के लिए स्कूल का अधिग्रहण करना वैध है।

इस खंड के तहत लिया जाता है यदि सरकार है

संतुष्ट है कि सार्वजनिक रूप से ऐसा करना आवश्यक है

ब्याज, जिस स्थिति में क्षतिपूर्ति देय होगी सी. एल. में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार। 15

क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए। खंड 15 शक्ति देता है

सरकार को किसी भी श्रेणी के स्कूलों का अधिग्रहण करने के लिए।

इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सरकार

संतुष्ट हैं कि सामान्य शिक्षा के मानकीकरण के लिए

राज्य या किसी भी राज्य में साक्षरता के स्तर में सुधार के लिए

क्षेत्र या सहायता प्राप्त शिक्षा के अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए

किसी भी क्षेत्र में या शिक्षा लाने के लिए राष्ट्रीय संस्थान

जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। नहीं। किसी भी विद्यालय के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की जानी है।

जब तक अधिग्रहण के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जाता है विधान सभा के एक प्रस्ताव द्वारा। प्रावधान

के मूल्यांकन और विभाजन के लिए बनाया गया है

जिले को मुआवजा और एक अपील प्रदान की जाती है

कलेक्टर द्वारा पारित आदेश से न्यायालय ने निर्णय लिया

मुआवजे की राशि और उसका बंटवारा

उन व्यक्तियों के बीच जो इसके हकदार हैं। इस प्रकार यह विधेयक

स्वीकृति के दो तरीकों पर विचार करता है और प्रदान करता है

उप-क्ल के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों का गठन। (8) सी. एल. 14 होने के बाद सरकार एक स्कूल का अधिग्रहण कर सकती है

पूर्ववर्ती उपखंडों के तहत इसका कब्जा लिया गया

या सरकार सी. एल. के तहत कर सकती है। 15 , कोई भी प्राप्त करें किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में सहायता प्राप्त विद्यालयों की श्रेणी

उस में उल्लिखित कई विशिष्ट उद्देश्यों में से

खंड। खंड 16 सरकार को शक्ति प्रदान करता है। अचल संपत्तियों को लेने से छूट

ऊपर या अधिग्रहित। खंड 17 में इस बात का प्रावधान है कि

स्थानीय शिक्षा प्राधिकरणों का आशीर्वाद, उनके

पद का गठन और कार्यकाल और खंड 18 विनिर्देशन

स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण के कार्यों को पूरा करता है

रियायतें। खंड 19 और 20 महत्वपूर्ण हैं और इन्हें इस प्रकार पढ़ा जाता है -

निम्नलिखित है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1029

" 19. मान्यता प्राप्त विद्यालयः -- उप के प्रावधान

धारा 7 I की धारा (2), (4), (5), (6), (7), (8) और (9) मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर उसी हद तक लागू होंगी।

और उसी तरह जैसे वे सहायता प्राप्त लोगों पर लागू होते हैं स्कूल "।

" 20. छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

प्राथमिक वर्ग-किसी भी वर्ग द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होगा।

किसी भी प्राथमिक कक्षा में किसी भी ट्यूशन के लिए छात्र

सरकारी या निजी स्कूल "।

विधेयक का भाग II अनिवार्य विषय से संबंधित है

शिक्षा. वह भाग निर्दिष्ट क्षेत्रों पर लागू होता है

सी. एल. 21. खंड 23 में निःशुल्क और अनिवार्य प्रावधान हैं।

राज्य भर में बच्चों की शिक्षा

दस वर्ष की अवधि और स्पष्ट रूप से इरादा है अनुच्छेद द्वारा राज्य पर निर्धारित दायित्व का निर्वहन। 45 में से

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। खंड 24 और

समितियाँ और उनके कार्य। खंड 26, जो हमारे चलने से पहले चर्चा में काफी हद तक मुद्दा उठाया गया है

निम्नलिखित हैः

" 26. बच्चों को भेजने का दायित्व अभिभावक पर

विद्यालयः -बाध्यता के किसी भी क्षेत्र में, संरक्षक प्रत्येक बच्चा, यदि ऐसा अभिभावक सामान्य रूप से वहाँ रहता है।

ऐसे क्षेत्र में, ऐसे बच्चे को सरकार में भाग लेने के लिए प्रेरित करें,

या निजी स्कूल और एक बार एक बच्चे को ऐसा हुआ है

इस अधिनियम के तहत स्कूल जाने के लिए बच्चा होगा प्राथमिक शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मजबूर

केशन या बच्चे को स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जाएगा।

जब तक वह चौदह वर्ष की आयु तक न पहुँच जाए।

हम कुछ खंडों को छोड़ सकते हैं, न कि हमारे लिए सामग्री

उद्देश्य, जब तक हम सी एल पर नहीं आते। 33 जिसका उल्लेख किया गया है

उन प्रश्नों में से एक जिस पर हमें विचार करना है। वह खंड

प्रदान करता है -

" 33. अदालतें निषेधाज्ञा नहीं देंगी-नोटिस के साथ

सिविल प्रो संहिता में निहित कुछ भी होना

लागू होने पर, कोई भी अदालत कोई अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं देगी। किसी भी प्रो को प्रतिबंधित करने वाला कोई अंतरिम आदेश देना या बनाना

आहार जो लिया जा रहा है या जिसके तहत लिया जाना है

यह अधिनियम "।

खंड 36 सरकार को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट बनाने की शक्ति प्रदान करता है [1959]

विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम और विशेष रूप से स्कूलों की स्थापना और रखरखाव के उद्देश्य के लिए, निजी स्कूलों को अनुदान और सहायता देना, निजी स्कूलों को मान्यता देना, सहायता प्राप्त स्कूलों में शुल्क लगाना और संग्रह करना, मान्यता प्राप्त स्कूलों में शुल्क की दरों को विनियमित करना, जिस तरह से खातों, रजिस्टरों और अभिलेखों को बनाए रखा जाएगा, प्रबंधकों द्वारा विवरणी, रिपोर्ट और खातों को प्रस्तुत करना, प्रबंधन के मानकों को लागू करना।

शिक्षा और अध्ययन के पाठ्यक्रम और अन्य मामले उप-क्ल में निर्दिष्ट। (2) उस खंड से। खंड 37 इस प्रकार है

निम्नलिखित है:

" 37. विधान सभा के समक्ष रखे जाने वाले नियम: -- इस अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के बाद जल्द से जल्द कम चौदह दिनों के लिए विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

और इस तरह के संशोधनों के अधीन होगा

विधान सभा सत्र के दौरान बना सकती है

सी. एल. के तहत। 38 विधेयक का कोई भी प्रावधान उस स्कूल पर लागू नहीं होता है जो सरकारी या निजी नहीं है। स्कूल, आई। ई. , सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय।

यह आशा की जाती है कि उपरोक्त सारांश उक्त विधेयक के प्रावधानों के उद्देश्य और दायरे को स्पष्ट रूप से सामने लाएगा। इसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि उक्त

विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

शिक्षा के प्रबंधन पर राज्य का नियंत्रण

राज्य में सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त संस्थान। द. जहाँ तक वे सहायता प्राप्त संस्थानों को प्रभावित करते हैं, प्रावधान उन प्रावधानों की तुलना में बहुत अधिक कठोर हैं जो केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों पर लागू होते हैं। शक्ति की चौड़ाई

इस प्रकार राज्य द्वारा नियंत्रण ग्रहण करने की मांग की गई धीरे से राष्ट्रपति को गणना करने के लिए दिखाई दिया

कुछ की संवैधानिक वैधता के बारे में संदेह पैदा करें

उक्त विधेयक के खंडों के आधार पर

संविधान द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को गारंटी दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

शिक्षा, और तदनुसार शक्तियों के प्रयोग में कला द्वारा उसे निहित किया गया। 143 (1) राष्ट्रपति ने निम्नलिखित पर विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए इस न्यायालय को भेजा है:

सवाल - .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

1031

(1) क्या केरल के खंड 3 का उपखंड (5)

शिक्षा विधेयक, जिसे उसके खंड 36 के साथ पढ़ा जाए या 1 में से कोई भी

उक्त उपखंड के प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 14 को किसी भी विवरण या किसी भी हद तक आहत करते हैं?

(2) खंड 3 का उपखंड (5), उपखंड (3) करें।

केरल शिक्षा के खंड 8 और खंड 9 से 13

विधेयक, या उसके कोई प्रावधान, के खंड (1) का उल्लंघन करते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 30 किसी भी विवरण में या

किसी भी हद तक?

(3) केरल शिक्षा विधेयक का खंड 15 क्या है?

या उसके किसी भी प्रावधान से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

किसी भी विवरण में या किसी भी हद तक?

(4) केरल शिक्षा विधेयक का खंड 33 क्या है?

या उसके किसी भी प्रावधान से अनुच्छेद 226 का उल्लंघन होता है।

संविधान किसी भी विवरण में या किसी भी हद तक? संदर्भ प्राप्त होने पर इस न्यायालय ने नोटिस जारी किए

मामले में रुचि रखने वाले उन्हें अपनी याचिका दायर करने के लिए कहते हैं उपरोक्त से संबंधित मामले के संबंधित बयान

उल्लिखित प्रश्न। तीन और संस्थान थे

बाद में, उनके अपने आवेदनों पर, छुट्टी दी गई

सुनवाई में उपस्थित होना। भारत संघ, द

केरल राज्य और सभी उक्त व्यक्ति और संस्थान

राष्ट्रों ने मामले के अपने-अपने बयान दायर किए हैं और

वकील द्वारा हमारे सामने पेश हुए हैं और इसमें भाग लिया है

डाक द्वारा अपने विचार भेजे लेकिन उपस्थित नहीं हुए सुनना। हमें सुनने का बहुत फायदा हुआ है।

प्रश्न से उत्पन्न होने वाले बिंदुओं पर पूर्ण तर्क विद्वानों और हम विद्वानों की सलाह के लिए बहुत ऋणी हैं

बहुत बड़ी सहायता के लिए पार्टियों के लिए उपस्थित होना

डी

उन्होंने हमें प्रदान किया है।

इस स्तर पर जमीन को साफ करना आवश्यक होगा।

के दायरे और दायरे के रूप में एक बिंदु का निपटान करके

प्रश्न 1 और 2। यह ध्यान दिया जाएगा कि ये दोनों

सवाल संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हैं, अंतर

अन्य रूप से, उक्त विधेयक के खंड 3 (5) 'जो पहले से ही है

विस्तार में उद्धृत किया गया है। तर्क द्वारा आगे बढ़ाया गया

विद्वान महान्यायवादी और अन्य विद्वान।

निकायों या संस्थानों की ओर से पेश वकील ने चुनौती दी

उक्त विधेयक मानो उप-क्ल में क्रमबद्ध रूप से निर्धारित किया गया हो। (5) स्वयं। इसलिए, जब प्रश्न 1 और 2 चुनौती देते हैं सी. एल की संवैधानिक वैधता। 3 (5) वे, वास्तव में, उक्त के अन्य सभी खंडों की वैधता पर सवाल उठाते हैं

बिल। हालाँकि, केरल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील कई आधारों पर इस तर्क का विरोध करते हैं। सबसे पहले, वह उस सी. एल. का विरोध करता है। 3 (5) इस विधेयक के केवल उन प्रावधानों को आकर्षित करता है जो एक नए विद्यालय की स्थापना से संबंधित हैं। कब

यह निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया कि उक्त विधेयक के कौन से प्रावधान एक नए स्कूल की स्थापना से संबंधित हैं, जो उनके अनुसार, सी. एल. द्वारा आकर्षित हैं। 3 (5) , एकमात्र प्रावधान जिसका वे उल्लेख करते हैं वह उप-क्ल है। (3) सी. एल. 3. केरल राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि सी. एल. 3 (5) केवल सी. एल. आकर्षित करता है। 3 (3) और वे नियम जो सी. एल. के तहत बनाए जा सकते हैं। 36 (2) (क) और उक्त विधेयक का कोई अन्य खंड नहीं है और इसलिए, कोई अन्य खंड इस दायरे में शामिल नहीं है।

जब तक, निश्चित रूप से, प्रश्नों में उनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ खंड, वास्तव में, प्रश्न 2 में विशेष रूप से उल्लिखित हैं। अगर

सी. एल. का उल्लेख। 3 (5) विद्वान वकील पूछते हैं कि उन प्रश्नों में, वास्तव में, उक्त विधेयक के अन्य सभी खंडों को आकर्षित किया, क्यों अन्य खंडों को विशेष रूप से प्रश्न 2 में उल्लिखित किया गया था? विद्वान वकील का यह भी मानना है कि एक विद्यालय की स्थापना के बाद अन्य खंड उस विद्यालय पर लागू होंगे और इस स्पष्ट प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं थी कि एक नव स्थापित विद्यालय विधेयक के अन्य अनुकूल दृष्टिकोण के अधीन होगा। जैसा कि विधेयक के अन्य खंड विधेयक के बाद स्थापित सभी विद्यालयों पर लागू होंगे सीएल की सहायता के बिना एक अधिनियम आता है। 3 (5) , प्रश्नों में उस खंड का संदर्भ शामिल नहीं किया जा सकता है।

उनके दायरे में विधेयक का कोई भी खंड है जिसका प्रश्नों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अंत में विद्वान वकील का तर्क है कि भले ही सी. एल. 3 (5) आकर्षित करता है। विधेयक के अन्य प्रावधानों के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि अन्य प्रावधान भी प्रश्नों का विषय हों।

हमारे निर्णय में, एस. सी. आर. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

1033

दोनों में से कोई भी चरम स्थिति गंभीर नहीं हो सकती है।

बनाए रखा।

आई.

विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क

केरल राज्य हमें कई आलोचनाओं के लिए खुला प्रतीत होता है। यदि उप-क्ल का इरादा। (5) सी. एल. 3 था।

विधेयक के केवल उन प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए जो

केवल एक नए विद्यालय की स्थापना से संबंधित और

यदि उप-सी. एल. (3) सी. एल. 3 इसमें एकमात्र प्रावधान था इसके तहत बनाए जाने वाले नियमों के अलावा

सी. एल. 36 (2) (क), तब बोधगम्य प्रारूपण की बात के रूप में उप-क्ल में कहना अधिक उचित होता। (3) सी. एल. 3 , कि नए विद्यालयों की स्थापना इस खंड के प्रावधानों और सी. एल. के तहत बनाए जाने वाले नियमों के अधीन होगी। 36 (2) (अ) "। खंड 3 (5) स्पष्ट रूप से नए विद्यालयों की स्थापना से संबंधित है।

सरकारी, सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल, और कहते हैं

कि विधेयक के कानून बनने के बाद सभी नए स्कूल विधेयक के अन्य प्रावधानों के अधीन होंगे। जहाँ तक

नए सरकारी स्कूलों का संबंध है, सी. एल. 3 (5)

निश्चित रूप से सीएल को आकर्षित करता है। 3 (3) (क) उस प्रावधान के लिए लेखक सरकार को नए स्कूल स्थापित करने के लिए कहता है; लेकिन

कहो कि सी. एल. 3 (5) केवल सी. एल. आकर्षित करता है। 3 (3) प्रतीत होता है कि असमर्थनीय, उस उपखंड के लिए अनुकूल नहीं है

नई सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त संस्थाओं की स्थापना के लिए

विद्यालय। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सीएल। 3 (3) ((क) विशेष रूप से

स्थापना और रखरखाव के लिए प्रदान करता है

केवल सरकार द्वारा नए स्कूल। खंड 3 (3) (बी)

केवल अनुमति देने के लिए प्रदान करता है

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को स्थापित करने के लिए सरकार

और सहायता प्राप्त विद्यालयों का रखरखाव करना। इसी तरह क्ल. 3 (3) (सी)

सरकार को केवल किसी को मान्यता देने के लिए अधिकृत करता है

किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित और अनुरक्षित विद्यालय या

व्यक्तियों का शरीर। खंड 3 (4) एक काल्पनिक कथा का परिचय देता है।

जिसके तहत सभी मौजूदा स्कूल, जिसका अर्थ है सभी मौजूदा स्कूल

सरकारी, सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय,

यह बिल। फिर क्ल आता है। 3 (5) जिसे अंदर रखा गया है बहुत व्यापक शब्द। यह कहता है, अन्य बातों के साथ, कि इसके बाद

उक्त विधेयक के प्रवर्तन की शुरुआत नए विद्यालयों की स्थापना के अधीन होना चाहिए

विधेयक के अन्य प्रावधान और वहां बनाए गए नियम

नीचे। सी. एल. के तहत बनाए जाने वाले नियम।

(ग) क्रमशः सी. एल. से सहसंबद्ध प्रतीत होता है। 3 (3) (ए), (बी) और (सी)। सीएल के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। 38

ला

जो सरकार के अलावा अन्य सभी स्कूलों को स्थान देता है और

निजी, आई। ई. , सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल, बाहर

विधेयक की परिधि, किस प्रकार की स्थापना नए स्कूल, हम पूछते हैं, उप-सी. एल. करते हैं। (5) विचार करें और अधिकृत करें? स्पष्ट रूप से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल

विधेयक के कानून बनने के बाद इसकी स्थापना की गई। खंड 3 (5), जैसे सी. एल. 3 (3) , जाहिर तौर पर बहुत कलात्मक रूप से किया गया है

खींचा, लेकिन खंड को समग्र और आंशिक रूप से पढ़ना इसका अंतिम भाग, अर्थात्, कि कोई भी

इसके अनुसार स्थापित स्कूल

ऐसे प्रावधान मान्यता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

सरकार द्वारा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सी. एल. 3 (5)

स्वयं विचार करता है और प्रतिष्ठान को अधिकृत करता है

सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूलों के रूप में नए स्कूलों का गठन। द. नए विद्यालयों का उद्घाटन और सहायता प्राप्त करना या

सरकार से मान्यता का गठन करता है

सी. एल. द्वारा विचार किए गए नए विद्यालयों की स्थापना। 3 (5) सीएल के साथ पढ़ें। 3 (3) . सी. एल. पढ़ना। 3 (5) के संदर्भ में

केवल नए विद्यालयों की स्थापना को अधिकृत करने के लिए लेकिन नए स्कूलों के सभी प्रावधानों के अधीन करने के लिए

उक्त विधेयक और उसके अधीन बनाए गए नियम। एसी के लिए सी. पी. टी. प्रतिबंधात्मक तर्क कि सी. एल. 3 (5) केवल सी. एल. आकर्षित करता है। 3 (3) सब-सी. एल. पर बहुत संकीर्ण

निर्माण किया जाएगा। (5) इसकी व्यापक भाषा या सी. एल. की भाषा द्वारा समर्थित नहीं है। 3 (3) . हमें नहीं लगता कि

इस तर्क में बहुत बल है कि यह नहीं था

आवेदन के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करने के लिए आवश्यक

नए स्कूलों की स्थापना के लिए अन्य प्रावधान

विधेयक के कानून बनने के बाद और अन्य खंड

उक्त विधेयक के अपने बल से और बिना उप-क्ल की सहायता। (5) इस तरह के नए स्थापित स्कूलों पर लागू होता है, क्योंकि नए स्कूलों को स्पष्ट रूप से अन्य प्रावधानों के अधीन बनाया गया है जो यह खुला नहीं है

केरल राज्य को अब यह कहने के लिए कि उप-क्ल। (5) जरूरत है।

उक्त विधेयक के अन्य प्रावधान नहीं किए हैं।

संचालन में आता है या यह आकर्षित नहीं करता है अन्य खंड हालांकि यह स्पष्ट रूप से करने के लिए अभिप्रेत है या

कि यह उन लोगों के लिए खुला नहीं है जो एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट को संदर्भित करने के लिए विधेयक का विरोध करते हैं

1035

उनके मामले के समर्थन में किसी अन्य खंड के लिए। यदि सी. एल. 3 (5) स्पष्ट रूप से अन्य प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया,

राष्ट्रपति ने शायद प्रश्नों को अलग तरीके से तैयार किया होगा।

यदि, इसलिए, यह माना जाता है, जैसा कि हम करने के लिए इच्छुक हैं,

वह सी. एल. 3 (5) नए स्कूलों को उक्त विधेयक के अन्य प्रावधानों के अधीन बनाता है, स्थिति क्या होगी? यदि, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है

जनरल और उनका समर्थन करने वाले अन्य वकील, उक्त विधेयक के कुछ खंड अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों या उनके द्वारा स्थापित या स्थापित किए जाने वाले शैक्षणिक संस्थानों के मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं। 3 (5) उन खंडों को उन नए विद्यालयों पर लागू करता है जिन्हें वे विधेयक के बाद स्थापित कर सकते हैं -

कानून आता है, तो न केवल वे अन्य खंड उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि क्ल। 3 (5) जो खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से उन अन्य खंडों को ऐसे नए स्कूलों पर लागू करता है, उन्हें भी असंवैधानिकता की चुनौती का सामना करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन अन्य खंडों की असंवैधानिकता का दोष, यदि कोई हो, तो सी. एल. के साथ संलग्न होना चाहिए। 3 (5) क्योंकि यह बाद वाला है जो नए स्कूलों को बनाता है

उन आपत्तिजनक खंडों के अधीन। इसलिए, एल की वैधता पर चर्चा में। 3 (5) अन्य खंडों की वैधता पर चर्चा करना सामान्य हो जाता है। संक्षेप में, हालांकि अन्य खंडों की वैधता अपने आप में और स्वतंत्र रूप से नहीं है, उन प्रश्नों में से किसी एक का विषय-वस्तु है, फिर भी क्ल की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में उनकी वैधता या अन्य विवेकपूर्णता पर विचार किया जाना चाहिए। 3 (5) जो उन खंडों को नए स्थापित स्कूलों पर लागू करता है। यह इस अर्थ में है कि, हम सोचते हैं कि अन्य खंडों की वैधता की चर्चा प्रश्न 1 और 2 के अवलोकन के भीतर आती है। हम, संदर्भ में, भाषा को देखते हुए इसे सही नहीं मानते हैं। इस सीएल में कार्यरत। 3 (5) , के अन्य खंडों की संवैधानिक वैधता पर विचार को बाहर करना

प्रश्न 1 और 2 पर चर्चा से विधेयक जो सी. एल. की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है। 3 (5) उक्त विधेयक का। वास्तव में, 1 हमारे सामने तर्क में

अक्सर दूसरे के लिए संदर्भ दिए गए हैं

प्रश्न 1 और 2 पर चर्चा करते हुए उक्त विधेयक के खंड और हमने विद्वान सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1959] के संबंधित तर्कों को सुना है।

उन खंडों की वैधता या अन्यथा के बारे में परामर्श दें जहाँ तक कि वे हमारे सामने रखे गए प्रश्नों पर असर डालते हैं जिन पर अब हम विचार और उत्तर देने के लिए आगे बढ़ते हैं।

री. प्रश्न 1 और 3। प्रश्न 1 चुनौती देता है

उप-क्ल की संवैधानिक वैधता। (5) सी. एल. 3 उक्त विधेयक को सी. एल. के साथ पढ़ा गया। 36 इस आधार पर कि

यह अनुच्छेद द्वारा सभी व्यक्तियों को दिए गए कानूनों के समान संरक्षण का उल्लंघन करता है। 14 संविधान से। प्रश्न 3 हमले सी. एल. 15 उक्त विधेयक का उसी आधार पर, अर्थात्, कि यह कला का उल्लंघन है। 14 संविधान से। चूंकि दोनों प्रश्नों के तहत हमले का आधार समान है, इसलिए उनसे एक साथ निपटना सुविधाजनक होगा।

कला का वास्तविक अर्थ, दायरा और प्रभाव। 14 हमारी तरफ से

संविधान चिरनजीत लाल चौधरी बनाम के मामले से शुरू होने वाले कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा चर्चा और निर्णय का विषय रहा है। भारत संघ और अन्य (1)। बुधन चौधरी बनाम। बिहार राज्य (1) इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने उस अनुच्छेद के सही अर्थ और दायरे को समझाया। हाल ही में राम कृष्ण डालमिया और अन्य के मामले में v. श्री

न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर (3), इस न्यायालय द्वारा 28 मार्च, 1958 को दिए गए अपने फैसले द्वारा स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई थी और इस न्यायालय के फैसलों द्वारा दृढ़ता से सूचीबद्ध कई सिद्धांतों को उस फैसले में क्रमिक रूप से निर्धारित किया गया था। मोहम्मद के और भी हाल के मामले में स्थिति को फिर से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य (1) निम्नलिखित में

शब्दों का उच्चारण:

" कला का अर्थ, दायरा और प्रभाव। 14 , जो

हमारे संविधान में समान संरक्षण खंड है, इस न्यायालय द्वारा एक श्रृंखला में समझाया गया है

चिरनजीत लाल चौ धुरी बनाम से शुरू होने वाले मामलों में निर्णय। भारत संघ (1) और राम कृष्ण डालमिया बनाम के हाल के मामले के साथ समाप्त होता है। श्री न्याय

एस. आर. तेंदुलकर (3)। यह अब अच्छी तरह से स्थापित है कि जबकि कला। 14 वर्ग कानून को मना करता है यह कानून के उद्देश्यों के लिए उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है

(2) [1955] 1 एस सी आर 1045.

(1) [1950] एस. सी. आर. 869

(4) [1959] एस. सी. आर

629

(3) [1959] एस. सी. आर. 279, एस. सी. आर. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

1037

और यह कि अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, 1 (i) वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतर पर आधारित किया जाना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह से बाहर रह गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत हैं और (ii) ऐसे अंतर का एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए। यह माना गया है कि वर्गीकरण विभिन्न आधारों, अर्थात् भौगोलिक, या वस्तुओं या व्यवसायों या इसी तरह के आधार पर किया जा सकता है और जो आवश्यक है वह यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। इस न्यायालय की घोषणाएं अन्य बातों के अलावा यह भी स्थापित करती हैं कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और यह कि -

उस पर बोझ है, जो उस पर हमला करता है, यह दिखाने के लिए कि संवैधानिक राजकुमार का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है

शिष्यों। न्यायालयों को यह स्वीकार करना चाहिए कि

विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से सराहना करती है, कि उसके कानून निर्देशित हैं

अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं और

इसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित हैं।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विधायिका स्वतंत्र है।

हानि की मात्रा को पहचानना और अपने प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित करना जहां आवश्यकता को सबसे स्पष्ट माना जाता है और अंत में इसे बनाए रखने के लिए

संवैधानिकता का अनुमान न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, समय के इतिहास को ध्यान में रख सकता है।

और मई। तथ्यों की हर स्थिति को मान लें जो हो सकता है कानून के समय मौजूद कल्पना की गई।

राम कृष्ण के मामले में इस अदालत के फैसले में

मिया का मामला (1) वे क़ानून जो विचार के लिए सामने आए इस न्यायालय के समक्ष पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था

श्रेणियाँ जैसा कि उसमें गिना गया है। कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं चर्चा को फिर से शुरू किया जाएगा और,

विलेख, उस ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है

विद्वान सलाहकार। इसलिए हम जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

उपरोक्त के आलोक में विवादित प्रावधान

इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत।

अब इस पर आधारित मुख्य तर्क पर आते हैं

(1) [1959] एस. सी. आर 279

कला. 14 , यह कहा जाता है कि यह विधेयक केरल में अब सत्ता में पार्टी की ओर से ईसाई चर्च और विशेष रूप से कैथोलिक अनुनय पर हमला करने, धर्म को खत्म करने, अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित अपने स्कूलों के अल्पसंख्यक समुदायों को हड़पने और संक्षेप में, राज्य के अलावा सभी शैक्षणिक एजेंसियों को समाप्त करने के लिए एक जानबूझकर प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है ताकि शिक्षा की एक रेजिमेंट बनाई जा सके और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा और उनके माध्यम से अपने राजनीतिक दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार किया जा सके और बढ़ती पीढ़ी के प्रभावशाली दिमागों को प्रेरित किया जा सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रश्नों द्वारा उठाई गई विशुद्ध रूप से कानूनी और संवैधानिक समस्या के रूप में देखी जाने वाली चर्चा में कुछ हद तक गर्मजोशी और जुनून पेश किया गया था; लेकिन शायद यह राज्य के लोगों के कुछ वर्गों के मन में उक्त विधेयक द्वारा भड़काए गए कड़वे आंदोलन और उत्साह के संदर्भ में समझ में आता है। तथापि, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह न्यायालय सरकार की नीति की योग्यता या अन्यथा से संबंधित नहीं है जिसने इस उपाय को प्रायोजित किया है और हमें केवल उन संवैधानिक प्रश्नों की जांच करने और विधेयक के उन प्रावधानों की वैधता या अन्यथा पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहा जाता है जो उचित रूप से उन प्रश्नों के दायरे में आ सकते हैं।

जिन शंकाओं के कारण प्रश्न 1 का निर्माण हुआ, उन्हें इस प्रकार संदर्भ के क्रम में पढ़ा जाता है, जिसे बेहतर तरीके से अपने शब्दों में कहा जाना चाहिए: " और जहाँ उक्त विधेयक के खंड 3 का उपखंड (3) केरल सरकार को सक्षम बनाता है,

अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त खंड के उपखंड (2) में निर्धारित सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा स्थापित और बनाए गए किसी भी स्कूल को मान्यता देना, अर्थात्, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा और ट्रेन के लिए सुविधाएं।

शिक्षकों की नियुक्ति;

और जहाँ उक्त विधेयक के खंड 3 के उपखंड (5) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी नया विद्यालय स्थापित किया गया है या कोई उच्च वर्ग किसी निजी एस. सी. आर. में खोला गया है।

1039

स्कूल, बिल के एक अधिनियम और अधिनियम बनने के बाद

लागू हो गया है, अन्यथा के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के साथ

उसकी धारा 36 के तहत, होने का हकदार नहीं होगा केरल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त;

और जहाँ एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या

खंड 3 के उक्त उपखंड (5) के प्रावधान

उक्त विधेयक सरकार को एक दिशाहीन प्रदान करता है

नए विद्यालयों की मान्यता के संबंध में शक्ति और

किसी भी निजी विद्यालय में उच्च कक्षाएं खोलना

जो मनमाने ढंग से प्रयोग करने में सक्षम है

और भेदभावपूर्ण तरीके से;

और जहाँ एक संदेह और पैदा हो गया है

क्या नए विद्यालयों की मान्यता की ऐसी शक्ति और

निजी विद्यालयों में उच्च कक्षाएं सक्षम नहीं हैं अधिकार को प्रभावित करने वाले तरीके से प्रयोग किया जा रहा है

संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) द्वारा गारंटीकृत अल्पसंख्यक

शिक्षा की स्थापना और प्रशासन के लिए संविधान

अपनी पसंद के संस्थान;

इसी तरह सी. एल. के बारे में संदेह। 15 तैयार किए जाते हैं संदर्भ के क्रम में निम्नलिखित पाठों में:

" और जहाँ उक्त विधेयक का खंड 15

केरल सरकार को अधिकार देने के लिए, द्वारा

राजपत्र में अधिसूचना, किसी भी श्रेणी की सहायता प्राप्त

किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में स्कूल, यदि वे हैं

संतुष्ट हैं कि सामान्य शिक्षा के मानकीकरण के लिए

केरल राज्य या के स्तर में सुधार के लिए

किसी भी क्षेत्र में या अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए साक्षरता

किसी भी क्षेत्र में सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या किसी भी श्रेणी की शिक्षा को उनके प्रत्यक्ष अधीन लाना

लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

बाजार के आधार पर मुआवजे के भुगतान पर

वहाँ कटौती करने के बाद इस प्रकार लिए गए विद्यालयों का मूल्य

उसके द्वारा दी गई सहायता या अनुदान की राशि से माँग, निर्माण या सुधार के लिए सरकार

विद्यालयों की संपत्ति का प्रबंधन;

और जहाँ एक संदेह पैदा हुआ है कि क्या

ऐसी शक्ति एक में प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। मनमाना और भेदभावपूर्ण तरीके से।

" "

1040

विधेयक की वैधता को चुनौती देने वाले व्यक्तियों या संस्थानों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा दो प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामले के कानूनी पहलू को आगे विस्तार से बताया गया है: खंड 3 (5) सभी बनाता है

नए स्कूलों पर लागू विधेयक के प्रावधान जो एस. सी. आर. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट करते हैं विधेयक के कानून बनने के बाद इसे स्थापित किया जा सकता है। खंड 3 (5) सरकार को एक निर्देशित, अनियंत्रित और अप्रचलित शक्ति प्रदान करता है जो "बुरी नजर और असमान हाथ से" प्रयोग करने में सक्षम है और सरकार, अपनी इच्छा या इच्छा पर, किसी भी व्यक्ति या संस्था को अलग कर सकती है और उसे अधीन कर सकती है।

शत्रुतापूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार। विधेयक में विधेयक के विभिन्न खंडों द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के प्रयोग के मामले में सरकार के मार्गदर्शन के लिए कोई नीति या सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि सी. एल. 3 ऐसी कोई नीति या सिद्धांत निर्धारित नहीं करता है जिस पर सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को सहायता प्राप्त विद्यालय की स्थापना और रखरखाव करने या किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित विद्यालय को मान्यता देने की अनुमति दे या न दे। बेटा। सरकार ऐसी अनुमति या मान्यता उन व्यक्तियों को दे सकती है जो इसकी नीति का समर्थन करते हैं लेकिन अन्य लोगों को नहीं जो इसका विरोध करते हैं। खंड 6 में यह नहीं कहा गया है कि सरकार का अधिकृत अधिकारी किन परिस्थितियों में सहायता प्राप्त विद्यालय की संपत्ति के हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। वह एक मामले में अनुमति दे सकता है लेकिन मनमाने ढंग से इसे दूसरे समान मामले में रोक सकता है। इसी तरह लेखक

सेवानिवृत्त अधिकारी, सी. एल. के तहत नहीं हो सकता है। 7 , किसी विशेष व्यक्ति के राजनीतिक विचारों या संबद्धता के लिए उसकी सरकार के पूर्वाग्रह या नापसंद से बेहतर कारण के लिए किसी सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक के रूप में किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति को मंजूरी देना। सरकार कर सकती है,

सीएल के तहत। 9 , एक सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक को रखरखाव अनुदान का भुगतान करें, लेकिन दूसरे को नहीं। पार्टिकलर स्कूल या विशेष रूप से स्कूलों की श्रेणियां सी. एल. एस. के तहत भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए क्षेत्रों को अलग किया जा सकता है। 14 और विधेयक के 15. यह आगे बताया गया है कि, यदि सी. एल. 3 (5) सी. एल. एस. के साथ पढ़ा जाता है। 21 , 26 और विधेयक का 28 परिणाम स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण होगा।

क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र में जो मजबूरी का क्षेत्र नहीं है, एक नया स्कूल जो विधेयक के बाद स्थापित किया जा सकता है

1041

संचालन में आता है और जो मान्यता या सहायता नहीं मांग सकता है, शुल्क ले सकता है और फिर भी विद्वानों को आकर्षित कर सकता है l लेकिन मजबूरी के क्षेत्र में इसी तरह स्थापित एक नया स्कूल सीधे सी. एल. द्वारा प्रभावित होगा। 26 और कोई नहीं होगा

विद्वानों, क्योंकि कोई भी अभिभावक कानूनी रूप से अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में नहीं भेज पाएगा जो न तो सरकार है

न ही कोई निजी स्कूल और ऐसा नया स्कूल बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कोई छात्र नहीं होगा और किसी भी कक्षा में इसकी फीस लेने का सवाल ही नहीं उठेगा। इस अंतिम उल्लिखित बिंदु में कोई बल नहीं है, क्योंकि विधानमंडल को फिर से सदस्य बनाया जाना चाहिए, अपने लोगों की जरूरतों को जानता है और अपने प्रतिबंधों को उन स्थानों तक सीमित रखने का हकदार है जहां

आवश्यकताओं को सबसे स्पष्ट माना जाता है और इसलिए, मजबूरी वाले क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंध काफी हैं।

भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण के आधार पर अनुमेय। संघ के जो भी अन्य प्रावधान हों

इस तरह के प्रतिबंध का मैं उल्लंघन कर सकता हूं या नहीं भी कर सकता हूं। जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी, यह निश्चित रूप से नहीं है

फ्रिंज आर्ट। 14 .

भेदभाव की एक और संभावना को कहा जाता है

एक ही प्रो के आवेदन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है उन सभी स्कूलों के लिए विधेयक का दृष्टिकोण जो नहीं हैं

इसी तरह की स्थिति। इस प्रकार तर्क विकसित किया गया है:

संविधान, यह बताया गया है, से संबंधित है अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा एक तरह से स्थापित विद्यालय

यह अन्य विद्यालयों के साथ व्यवहार करने के तरीके से अलग है।

इस प्रकार एंग्लो-इंडियन स्कूलों को अनुदान दिया जाता है।

कला. 337 संविधान और शैक्षणिक संस्थान

सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा शुरू किए गए राष्ट्र

एंग्लो-इंडियंस कला द्वारा संरक्षित हैं। 29 और 30.

इस प्रकार अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान हैं -

स्थापित शैक्षणिक संस्थानों से अलग

विशेषाधिकार या संरक्षण और फिर भी विधेयक का उद्देश्य है - सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक ही कक्षा में रखें

हालाँकि उनकी समान विशेषताएं नहीं हैं और

असमान लोगों पर समान बोझ डालें। यह अविवेकी

समान प्रावधानों को विभिन्न संस्थानों में लागू करना

अलग-अलग विशेषताओं वाले राष्ट्र और एक होने के नाते

बराबरी एक गंभीर उल्लंघनकारी भेदभाव लाती है

संविधान के समान संरक्षण खंड का।

1042 में

इस तर्क का समर्थन निर्भरता पर रखा गया है

कम्बर में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

एलैंड कोल कं. वी. संशोधन बोर्ड (1)। उस निर्णय का, हमारे निर्णय में, तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है

हमारे सामने मामला। वहाँ कर अधिकारियों

शहर में कोयला भूमि के मालिकों का मूल्यांकन किया

कंबरलैंड 50 प्रतिशत की सपाट दर लागू करके। संपत्तियों के वास्तविक मूल्य पर नहीं, बल्कि 260 डॉलर प्रति एकड़ के कृत्रिम मूल्यांकन पर मनमाने ढंग से शहर की सभी कोयला भूमि को आवंटित किया जाता है, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो।

260 डॉलर प्रति एकड़ का कृत्रिम मूल्यांकन बहुत अधिक था। उन संपत्तियों के वास्तविक मूल्य से नीचे जो थे

नदी के किनारे या रेलवे के पास, जबकि संपत्तियों का मूल्य नदी के किनारे या रेलवे से बहुत दूर स्थित होता है, निर्धारित मूल्य के लगभग बराबर था। कर की समान दर, अर्थात् 50 प्रतिशत, लागू करने का परिणाम। निर्धारित मूल्य पर यह था कि

अधिक मूल्यवान संपत्तियों के मालिकों को भुगतान करना पड़ा

उन संपत्तियों के वास्तविक मूल्य पर वे जितना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते, उससे बहुत कम। वहाँ

इसके अलावा, मूल्यांकन की विधि स्पष्ट रूप से शहर के दूरदराज के हिस्सों में स्थित संपत्तियों के मालिकों के नुकसान के लिए काम करती है और स्पष्ट रूप से अलग थी।

आपराधिक। वहाँ भेदभाव बहुत था।

कराधान के उस तरीके का एक बड़ा हिस्सा। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्थिति, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है

उक्त विधेयक के प्रावधान और परिणामस्वरूप रियासत

उस निर्णय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है मामला। हालाँकि, यह मामले को समाप्त नहीं करता है और हमें अभी तक मुख्य तर्क से निपटना है कि

विधेयक में कोई नीति या सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है

के अभ्यास में सरकार का मार्गदर्शन

विधेयक द्वारा इसमें निहित व्यापक शक्तियाँ।

लंबे शीर्षक का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है।

और विधेयक की प्रस्तावना। कि नीति और

किसी दिए गए उपाय का उद्देश्य लंबे शीर्षक से निकाला जा सकता है और इसकी प्रस्तावना को मान्यता दी गई है।

(1) (1931) 284 यू. एस. 23; 76 एल एड। 146 , 150 .

एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1043

इस न्यायालय के कई निर्णयों में और तैयार संदर्भ के रूप में हम बिस-1 वांबर सिंह बनाम में अपने निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। उड़ीसा राज्य (1) एक उदाहरण के रूप में। विधेयक की सामान्य नीति जैसा कि निर्धारित किया गया है

इसके शीर्षक में और प्रस्तावना में विस्तृत रूप से कहा गया है, "विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों के बेहतर संगठन और विकास के लिए प्रयास करना।

पूरे देश में व्यापक शैक्षिक सेवा

राज्य "। विधेयक के प्रत्येक खंड की व्याख्या इस नीति के आलोक में की जानी चाहिए और पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, जब कोई विशेष

खंड सरकार पर कोई भी कार्रवाई करने का कोई भी विवेकाधिकार छोड़ता है, यह समझना आवश्यक है कि इस तरह के प्रावधान का उपयोग आगे बढ़ने के उद्देश्य से किया जाना है।

और इसे लागू करने और बाधित न करने में सहायता के लिए

नीति। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि नहीं। नीति या सिद्धांत बिल्कुल निर्धारित किया गया है

विवेकाधिकार के प्रयोग का मार्गदर्शन करने के लिए विधेयक

इस विधेयक के खंडों द्वारा सरकार। बात यह है

हालाँकि, वह वहाँ आराम नहीं करता है। आम नीति

विधेयक के लंबे शीर्षक और प्रस्तावना से निकाला जा सकता है

अधिक निश्चित बयानों द्वारा और अधिक प्रबलित किया जाता है

उसके विभिन्न खंडों में नीति। इस प्रकार यह शक्ति

सी. एल. के अधीन सरकार में निहित। 3 (2) हो सकता है

केवल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से

सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए। यह "प्रदान करने के उद्देश्य के लिए है

ऐसी सुविधाएँ "कि तीनों के तहत कई शक्तियाँ

उस उपखंड के शीर्ष (ए), (बी) और (सी) सरकार को प्रदान किए गए हैं। स्पष्ट निहितार्थ

दीर्घ शीर्षक और प्रस्तावना से घटाई जा सकने वाली नीति के आलोक में पढ़े जाने वाले इन प्रावधानों में से यह है कि अनुमति या मान्यता देने के मामले में सरकार को इस विचार से निर्देशित किया जाना चाहिए कि क्या ऐसी अनुमति या मान्यता देने से राज्य में शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर संगठन और विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्या यह सामान्य या विशेष शिक्षा प्रदान करने या शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाएगा और यदि ऐसा करता है तो अनुमति या मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन यदि यह उस उद्देश्य में बाधा डालता है तो इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह सच है कि

(1) [1954] एस. सी. आर. 842,855

"मे" शब्द का प्रयोग उप-क्ल में किया गया है। (3) , लेकिन, कानूनों के निर्माण के प्रसिद्ध नियम के अनुसार, यदि उद्देश्य का अस्तित्व स्थापित हो जाता है और विवेक के प्रयोग की शर्तों को पूरा किया जाता है, तो सरकार ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगी और विवेक के मनमाने प्रयोग का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है। [जूलियस वी. की तुलना करें। ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड बिशप (1)]। यदि वास्तव में कोई भेदभाव किया जाता है

सरकार तब इस तरह का भेदभाव उक्त विधेयक से ही कटौती योग्य नीति और सिद्धांत का उल्लंघन होगा और अदालत तब विधेयक के प्रावधानों को नहीं बल्कि सरकार के भेदभावपूर्ण कार्य को रद्द कर देगी। सी. एल. पर गुजर रहा है। 14 , हम पाते हैं कि सरकार को इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक ने इसकी उपेक्षा की है।

उस पर लगाए गए कर्तव्यों का पालन करना और यह कि लोक हित में शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। यहाँ फिर से सिद्धांत का संकेत दिया गया है और सरकार को कोई मनमाना या निर्देशित शक्ति नहीं दी गई है। इसी तरह शक्ति, सी. एल. के तहत। 15 (1) इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य में सामान्य शिक्षा के मानकीकरण या किसी भी क्षेत्र में साक्षरता के स्तर में सुधार के लिए या किसी भी क्षेत्र में सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए या किसी भी श्रेणी की शिक्षा को उनके दायरे में लाने के लिए इसका उपयोग करना आवश्यक है।

प्रत्यक्ष नियंत्रण "और सबसे बढ़कर" जनहित में "शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। उद्देश्य अच्छे हैं या बुरे, यह राज्य की नीति का सवाल है जिसके गुण-दोष के बारे में हम वर्तमान चर्चा में चिंतित नहीं हैं। अब हम केवल यह इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं कि विचाराधीन खंड उस खंड द्वारा प्रदत्त बहुत व्यापक शक्ति के प्रयोग के मामले में सरकार के मार्गदर्शन के लिए एक नीति निर्धारित करता है। शक्ति का प्रयोग इस परंतुक द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है कि उस उपखंड के तहत कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि अधिग्रहण का प्रस्ताव न हो। विधान सभा के एक प्रस्ताव द्वारा समर्थित है-एक परंतुक

(1) (1880) . 5 ऐप. कैस। 214 .

एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1045

जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सरकार द्वारा अपनी इच्छा या खुशी से शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मैं कुछ खंडों को छोड़ते हुए, हम सी. एल. पर आते हैं। 36. सीएल द्वारा सरकार को दी गई शक्ति। 36 नियम बनाने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए" प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, बनाए जाने वाले नियमों को अपने लंबे शीर्षक में निर्धारित नीति और उद्देश्य और उक्त विधेयक के अन्य खंडों की प्रस्तावना और प्रावधानों को लागू करना चाहिए। इसके अलावा, सीएल के तहत। 37 नियम बनाए जाने के बाद उन्हें जल्द से जल्द विधान सभा के समक्ष कम से कम 14 दिनों के लिए रखा जाना चाहिए और ऐसे संशोधनों के अधीन होना चाहिए जो विधान सभा सत्र के दौरान कर सकती है।

जो वे इतने व्यवस्थित हैं। नियम पहले निर्धारित किए जाने के बाद

विधान सभा में उनका परिवर्तन किया जा सकता है या संशोधन किया गया और यह तब है कि नियम, जैसा कि संशोधित किया गया है

प्रभावी बनें। यदि कोई संशोधन नहीं किया जाता है

नियम 14 दिनों की अवधि के बाद लागू होते हैं।

समाप्त हो जाता है। यहां तक कि इस बाद की घटना में भी नियम उनके ऋणी हैं

विधान सभा की मौन सहमति के लिए प्रभावकारिता

स्वयं। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

केरल ने सुरम्य भाषा में प्रस्तुत किया कि यहाँ

जिसे उचित रूप से विधान कहा जा सकता था

दो चरण और वह उपाय जो अंततः सामने आएगा विधेयक और नियमों के साथ या उसके बिना

संशोधन विधायिका की आवाज का प्रतिनिधित्व करेगा।

स्वयं सभा और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि

कानून बनाने की दिशाहीन और अनियंत्रित शक्ति रही है

अनुचित रूप से सरकार को सौंपा गया। क्या

उसके समक्ष रखे गए नियमों को मंजूरी देने में विधान विधानसभा केरल के विधानमंडल के रूप में कार्य करती है या

विधानमंडल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है जिसमें शामिल हैं

विधान सभा और राज्यपाल, में है

केरल विधान सभा, जितना हम कर सकते हैं उससे अधिक तय करें। लेकिन हमें बस इतना कहने की जरूरत है कि

के मार्गदर्शन के लिए नीति निर्धारित करने से

शक्तियों के प्रयोग के मामले में सरकार

के विभिन्न प्रावधानों के तहत इसे प्रदान किया गया

सीएल सहित बिल। 36 , केरल विधानमंडल ने

सी. एल. 15 और सी. एल. 37 अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की।

इस सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में

1046

[1959]

संबंध हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या रखा गया है

इस न्यायालय द्वारा एक से अधिक निर्णयों में, अर्थात्,

कि विवेकाधीन शक्ति अनिवार्य रूप से एक भेदभाव नहीं है

देशी शक्ति और सरकार द्वारा शक्ति का दुरुपयोग

इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। बताए गए कारणों से

ऊपर यह हमें प्रतीत होता है कि असंवैधानिक का आरोप

कई खंडों की राष्ट्रीयता जो इसके भीतर आती है

अब विचाराधीन दो प्रश्न

कला. 14 कायम नहीं रखा जा सकता। पद बनाया गया है और भी स्पष्ट जब हम प्रश्न पर विचार करते हैं

सी. एल की वैधता। 15 (1) नीति के अलावा और

लंबे शीर्षक और पूर्व से अनुमानित सिद्धांत

विधेयक और उस उपखंड से ही,

इसके लिए परंतुक स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधानमंडल अपने कार्य का त्याग नहीं किया है और जबकि यह है

सरकार को एक बहुत व्यापक शक्ति प्रदान की गई

विद्यालयों की श्रेणियों का अधिग्रहण न केवल यह प्रदान करता है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग केवल इसके लिए किया जा सकता है

खंड में ही उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्यों पर आगे और अधिक प्रभावी नियंत्रण भी रखा गया है

शक्ति का प्रयोग, यह आवश्यक करके कि यह होना है इसका प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब विधानमंडल द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है।

स्थानीय सभा सरकार को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करती है। हमारी राय में, यह विधेयक राम कृष्ण डालमिया के मामले (1) में उल्लिखित श्रेणी (iii) के भीतर नहीं आता है, जैसा कि श्री जी. एस. पाठक ने तर्क दिया है। ((iv) और यदि सरकार विधेयक में निर्धारित नीति और सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए प्रावधानों को लागू करती है तो कार्यकारी कार्रवाई श्रेणी (v) के तहत आएगी।

लेकिन विधेयक नहीं और उस कार्रवाई को रद्द करना होगा। इसलिए, परिणाम यह है कि विधेयक के कई खंडों की अयोग्यता का आरोप, जो कला के उल्लंघन के आधार पर प्रश्न 1 और 3 के दायरे में आते हैं। 14 पीछे हटना चाहिए और 1 और 3 दोनों प्रश्नों के हमारे उत्तर नकारात्मक होने चाहिए।

री. प्रश्न 2: अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लिखित हैं -

हमारे संविधान का भाग III जो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इन्हें "सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार" उप-शीर्ष के तहत एक साथ समूहीकृत किया गया है। दोनों अनुच्छेदों के पाठ और सीमांत टिप्पणियों से पता चलता है कि उनका उद्देश्य उन मूलभूत बातों को प्रदान करना है।

(1) [1959] एस. सी. आर 279

समुदाय के कुछ वर्गों पर अधिकार जो अल्पसंख्यक समुदायों का गठन करते हैं। सी. एल. के तहत। (1) आई आर्ट। 29 भारत के राज्य या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग जिसके पास एक विशिष्ट धारा है।

अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। यह स्पष्ट है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा और उनके माध्यम से अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति का प्रभावी ढंग से संरक्षण कर सकता है।

और, इसलिए, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के अधिकार के लिए एक आवश्यक संगत है और यही वह है जो कला द्वारा सभी अल्पसंख्यकों पर लाया गया है। 30 (1) जिसे यहाँ पहले भी पूरा उद्धृत किया गया है। हालाँकि, यह अधिकार सी. एल. के अधीन है। 2 कला की। 29 जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा बनाए गए या सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य निधि से बाहर।

जैसे ही हम कला तक पहुँचते हैं। 30 (1) के लिए विद्वान सलाहकार

केरल राज्य तुरंत सवाल उठाता है: अल्पसंख्यक क्या है? यह एक ऐसा शब्द है जिसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। यह कहना आसान है कि अल्पसंख्यक समुदाय का अर्थ है एक ऐसा समुदाय जो संख्यात्मक रूप से 50 प्रतिशत से कम है। , लेकिन फिर प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्रश्न के कुछ हिस्से का उत्तर दिया जाना बाकी है, अर्थात् 50 प्रतिशत। किससे? क्या यह 50 प्रतिशत है? भारत की पूरी आबादी का या 50 प्रतिशत। राज्य की जनसंख्या का एक हिस्सा बनाना

संघ? केरल राज्य ने यहां दायर अपने मामले के बयान में जो रुख अपनाया है, वह इस प्रकार है: --

" इस सवाल का एक और पहलू यह है कि

विचार के लिए आता है, अर्थात्, कि कला के तहत अल्पसंख्यक क्या है। 30 (1) . राज्य का तर्क है कि ईसाई, जिनमें से एक निश्चित वर्ग इस आरोप पर विधेयक पर अपनी आपत्ति में मुखर है कि यह कला का उल्लंघन करता है। 30 (1) , राज्य में वे अल्पसंख्यक नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे राज्य में ईसाई गणितीय बहुमत में नहीं हैं। वे आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा हैं; लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कला के अर्थ में अल्पसंख्यक हैं। 30 (1) . *

तर्क जो वे करते हैं, अगर इसके तार्किक पर धकेल दिया जाता है

निष्कर्ष का अर्थ होगा कि लोगों का कोई भी वर्ग पचास प्रतिशत से कम है। जनसंख्या को अल्पसंख्यक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उनसे इस प्रकार निपटा जाना चाहिए

इस तरह।

केरल राज्य में ईसाई समुदाय दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है; हालाँकि, वे बहुसंख्यक समुदाय हैं।

राज्य के कुछ क्षेत्रों में समुदाय। मुसलमान राज्य में तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है, जो कुल आबादी का लगभग एक-सातवां हिस्सा है। हालाँकि, वे राज्य के कुछ अन्य क्षेत्रों में बहुसंख्यक समुदाय भी हैं। (आई. एल. आर. (1951) 3 असम 384 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिन व्यक्तियों पर अल्पसंख्यक होने का आरोप है, वे उस विशेष क्षेत्र में अल्पसंख्यक होने चाहिए जिसमें संस्था स्थित है। केरल राज्य, इसलिए, तर्क देता है कि एक अल्पसंख्यक का गठन करने के लिए जो अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों को गारंटीकृत मानसिक अधिकारों का दावा कर सकता है। 29 (1) और 30 (1) व्यक्तियों को उस विशेष क्षेत्र में संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक होना चाहिए जिसमें विचाराधीन शैक्षणिक संस्थान स्थित है या होने का इरादा है। • एक छोटा सा चिंतन तुरंत दिखाएगा कि यह एक संतोषजनक परीक्षण नहीं है। कहाँ रेखा खींची जानी है और कौन सी इकाई ली जानी है? क्या हम अपनी इकाई के रूप में एक जिला, या एक उप-मंडल या एक तालुक या एक शहर या उसके उपनगरों या एक नगरपालिका या उसके वार्डों को लेना चाहते हैं? यह सर्वविदित है कि कई शहरों में एक विशेष समुदाय के लोग शहर के उपनगर या नगरपालिका के एक वार्ड में एक साथ आते हैं। इस प्रकार एंग्लो-इंडियन या ईसाई या मुसलमान किसी शहर या किसी विशेष उपनगर में एकत्र हो सकते हैं।

नगरपालिका का एक विशेष वार्ड और वे वहां बहुमत में हो सकते हैं। केरल राज्य के विद्वान वकील के तर्क के अनुसार, उस इलाके के एंग्लो-इंडियन या ईसाई या मुसलमान, जिन्हें एक इकाई के रूप में लिया जाता है, विचाराधीन अनुच्छेदों के अर्थ के भीतर "अल्पसंख्यक" नहीं होंगे और इसलिए, उस इलाके में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव के हकदार नहीं होंगे, लेकिन अगर एंग्लो-इंडियन या ईसाई समुदाय के कुछ सदस्य उसी शहर के दूसरे उपनगर में या उसी नगरपालिका के किसी अन्य वार्ड में रहते हैं तो एस. सी. आर. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

1049

और उनकी संख्या वहां रहने वाले अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में कम होगी, तो एंग्लो-इंडियन या ईसाई समुदाय के वे सदस्य होंगे

कला के अर्थ के भीतर अल्पसंख्यक। 29 और 30 और

उस इलाके में अपनी पसंद के संस्थान। वैसा ही करोलबाग में रहने वाले तमिल, अगर वे होते हैं

अन्य कॉम के सदस्यों की तुलना में संख्या में अधिक होना

करोलबाग में रहने वाले धन, इसके हकदार नहीं होंगे करोलबाग में एक तमिल स्कूल की स्थापना और रखरखाव,

जबकि दरियागंज में रहने वाले तमिल लोग कहते हैं

जहाँ उनकी संख्या सदस्यों की तुलना में कम हो सकती है

दरियागंज में रहने वाले अन्य समुदायों का एक होगा कला के अर्थ के भीतर अल्पसंख्यक या खंड। 29

और 30. फिर से सिंधु में रहने वाले बिहारी मजदूर

कलकत्ता में या उसके आसपास परीक्षण क्षेत्र जहाँ वे हो सकते हैं

उस इलाके के बहुसंख्यक लोग इसके हकदार नहीं होंगे

अल्पसंख्यक और उन बिहारियों के पास कोई अधिकार नहीं होंगे।

अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान

हिंदी में शिक्षा, हालांकि वे संख्यात्मक रूप से एक हैं

अल्पसंख्यक अगर हम पूरे कलकत्ता शहर या

एक इकाई के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य। इसी तरह बंगाली बिहार के एक शहर के एक विशेष वार्ड में रहने वाले जहाँ

वे बहुमत बनाने के हकदार नहीं होंगे उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण

शिक्षा बंगाली में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये चरम हैं। चित्रण, लेकिन वे भ्रांति को सामने लाने का काम करते हैं

मामले के इस भाग पर तर्क में निहित केरल राज्य के विद्वान वकील द्वारा उन्नत।

कला का उल्लेख किया गया है। 350 - ए के समर्थन में तर्क कि एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में लिया जा सकता है

एक इकाई। ऊपर दिए गए चित्र उस पर लागू होंगे।

मामला भी। आगे इस तरह के निर्माण की आवश्यकता होगी। "उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर" शब्दों को जोड़ना

तर्क। हालाँकि, हमें इस अवसर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मामले में आगे बढ़ें और चर्चा शुरू करें

और इस बारे में अंतिम राय व्यक्त करें कि क्या शिक्षा

राज्य का विषय होने के नाते सूची II की मद 11 है

संविधान की सातवीं अनुसूची केवल

सूची ई और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1959] की प्रविष्टियों 62,63,64 और 66 के प्रावधान

मुसलमान। 1951 की जनगणना के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन से पहले त्रावणकोर राज्य में एंग्लो-इंडियंस की संख्या केवल 11,990 थी। हम इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि प्रश्न 2 स्वयं इस आधार पर आगे बढ़ता है कि केरल में अल्पसंख्यक हैं जो कला द्वारा प्रदत्त अधिकारों के हकदार हैं। 30 (1) और, कड़ाई से बोलते हुए, प्रश्न 2 का उत्तर देने के लिए हमें यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय का क्या अर्थ है या इसका पता कैसे लगाया जाना है।

अब हम अपने सामने रखे गए मुख्य बिंदु पर जाते हैं, अर्थात्, कला द्वारा प्रदत्त अधिकार का दायरा और दायरा क्या है। 30 (1) . मामले के इस हिस्से पर मुख्य तर्क पर आने से पहले, हम केरल राज्य के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए एक छोटे से मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। उनका तर्क है कि तीन शर्तें हैं जिन्हें कला के संरक्षण और विशेषाधिकारों से पहले पूरा किया जाना चाहिए। 30 (1) दावा किया जा सकता है, अर्थात्, (1) एक अल्पसंख्यक समुदाय होना चाहिए, (2) उस समुदाय के एक या अधिक सदस्यों को, संविधान के प्रारंभ के बाद, अपनी पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और (3) अपने स्वयं के सदस्यों के लिए एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए।

समुदाय। हम पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं, ऊपर उल्लिखित परीक्षण के अनुसार, एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में एंग्लो-इंडियन, ईसाई और मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हैं।

1051

केरल राज्य। हम यह नहीं मानते कि कला का संरक्षण और विशेषाधिकार है। 30 (1) केवल हमारे संघ की तारीख के बाद स्थापित शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तार करें।

शासन लागू हुआ या जो इसके बाद हो सकता है

स्थापित किया जाए। इस परिकल्पना पर शैक्षिक

शुरू होने से पहले इन समुदायों के संविधान लाभों का हकदार नहीं होगा

कला की। 30 (1) . इस तर्क की भ्रांति बन जाती है जैसे ही हम कला की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है।

नेस, व्यवसाय या पेशा पहले से ही शुरू हो चुका है और जिन्हें शुरू किया जा सकता है और ले जाया जा सकता है

संविधान के प्रारंभ के बाद। वहाँ

केवल स्थापित शैक्षणिक संस्थानों तक ही सीमित संविधान के प्रारंभ के बाद। द.

कला में प्रयुक्त भाषा। 30 (1) काफी चौड़ी है

संविधान पूर्व और संविधान के बाद दोनों को शामिल करता है।

संस्थाएं। इस कला को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 30 (1)

अल्पसंख्यकों को दो अधिकार देता है, अर्थात् (ए) स्थापित करने के लिए, और (ख) उनके शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करना।

चयन करें। दूसरा अधिकार स्पष्ट रूप से संविधान पूर्व को शामिल करता है।

स्कूल कला के रूप में। 26 अधिकार को शामिल करता है संविधान पूर्व धार्मिक संस्थानों को बनाए रखना। जिस बारे में

ऊपर वर्णित तीसरी शर्त, तर्क

इसके तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि यदि किसी अन्य समुदाय के एकल सदस्य को प्रवेश दिया जाता है।

एक प्रतिभागी के सदस्यों के लिए स्थापित एक स्कूल में

लार अल्पसंख्यक समुदाय, फिर शैक्षणिक संस्थान

✔

यह एक स्थापित शैक्षणिक संस्थान नहीं रह गया है

विशेष अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा। तर्क एक संदर्भ द्वारा प्रबलित करने की मांग की जाती है

कला. 29 (2) . कहा जाता है कि एक शैक्षणिक संस्थान

एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित जो नहीं है

राज्य के कोष से कोई सहायता लेने के लिए स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा किसी अन्य समुदाय से संबंधित एक एकल विद्वान

कि यह किसके लाभ के लिए स्थापित किया गया था लेकिन यह कि

जैसे ही ऐसा कोई शैक्षणिक संस्थान खोजता है और प्राप्त करता है

राज्य के खजाने से सहायता कला। 29 (2) इसे रोक देंगे

अन्य कॉम के सदस्यों को प्रवेश से इनकार करने से

केवल धर्म, नस्ल, जाति, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर धन

भाषा या उनमें से कोई भी और इसके परिणामस्वरूप यह अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान नहीं रहेगा जिसने इसे स्थापित किया था। यह तर्क हमें अनुच्छेद की भाषा द्वारा ही समर्थनीय नहीं लगता है। कला में ऐसी कोई सीमा नहीं है। 30 (1) और इस सीमा को स्वीकार करने के लिए आवश्यक रूप से अनुच्छेद में "अपने समुदाय के लिए" शब्दों को जोड़ना शामिल होगा जो व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित नियमों के अनुसार अनुमेय नहीं है। न ही यह मान लेना उचित है कि यह कला का उद्देश्य है। 29 (2) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से प्राप्त सहायता से वंचित करना था। कहने के लिए कि एक संस्थान जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक होने के कारण सहायता प्राप्त करता है

संस्थान को किसी भी ज्ञापन को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए

किसी भी अन्य समुदाय के लिए केवल उसमें उल्लिखित आधारों पर और फिर यह कहना कि जैसे ही ऐसी संस्था ऐसे बाहरी व्यक्ति को स्वीकार करती है, यह बंद हो जाएगा।

अल्पसंख्यक संस्थान होना यह कहने के समान है कि अल्पसंख्यक संस्थान, अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में, किसी भी सहायता के हकदार नहीं होंगे। वास्तविक आयात

कला. 29 (2) और कला। 30 (1) हमें लगता है कि वे

स्पष्ट रूप से एक अल्पसंख्यक संस्थान पर विचार करें

अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति इनके बीच प्रचार करके बेहतर सेवा दी जाए

विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के गैर-सदस्य।

हमारी राय में, इस शर्त को पढ़ना संभव नहीं है

कला में। 30 (1) संविधान से।

निर्दिष्ट लघु बिंदु का निपटान करने के बाद

ऊपर, अब हम मुख्य तर्क को आगे बढ़ाते हैं

कला की सामग्री के बारे में हमारे सामने। 30 (1) . सबसे पहले

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अनुच्छेद कुछ अधिकार देता है।

न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी अल्पसंख्यक। अगले स्थान पर, अधिकार प्रदान किया गया है

ऐसे अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करनी है।

उनकी पसंद से। यह नहीं कहता कि अल्पसंख्यकों के आधार पर

धर्म पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए।

केवल धर्म पढ़ाने के लिए, या भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए।

सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1053

केवल अपनी भाषा पढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए। लेख में मैं जो कहता हूं और जिसका मतलब है वह यह है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए। वहाँ कोई नहीं है

ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर सीमा निर्धारित की गई है। इस तरह के अल्पसंख्यक आदेश देंगे

विश्वविद्यालय शिक्षा और पूरी तरह से दुनिया में बाहर जाना इस तरह की बौद्धिक उपलब्धियों से सुसज्जित

उन्हें सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा में प्रवेश के लिए उपयुक्त बनाना।

इसमें सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान शामिल हैं। वह भी। दूसरे शब्दों में, लेख इसे छोड़ देता है

ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए उनकी पसंद

जैसा कि दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, अर्थात्,

उनके धर्म, भाषा या संस्कृति का संरक्षण करना, और एक संपूर्ण, अच्छा सामान्य देने का उद्देश्य भी

अपने बच्चों को शिक्षा दें। ध्यान देने वाली अगली बात

यह है कि अनुच्छेद, संदर्भ में, सभी अल्पसंख्यकों को देता है,

चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, दो अधिकार,

अर्थात्, स्थापना का अधिकार और विज्ञापन का अधिकार

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों के मंत्री। द.

सही अर्थ को समझने की कुंजी और

विचाराधीन अनुच्छेद के निहितार्थ "उनकी अपनी पसंद के" शब्द हैं। कहा जाता है कि डोमी

शून्य शब्द "विकल्प" है और उस लेख की सामग्री है।

विशेष अल्पसंख्यक कॉम की पसंद के रूप में व्यापक है

मुनिटी इसे बना सकती है। प्रदत्त अधिकारों का दायरा

स्वयं शैक्षणिक संस्थानों से। शिक्षा. द्वारा स्थापित या प्रशासित राष्ट्रीय संस्थान

अल्पसंख्यक या इस तरह से स्थापित या प्रशासित होने के लिए

उस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए

इसे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् (1) जो सहायता या मान्यता नहीं चाहते हैं

राज्य, (2) जो सहायता चाहते हैं, और (3) जो सहायता चाहते हैं

जो केवल मान्यता चाहते हैं लेकिन सहायता नहीं चाहते हैं।

उन संस्थानों के संबंध में जो इसके भीतर आते हैं

पहली श्रेणी, वे हैं, सी. एल. द्वारा।

1054

विधेयक का कार्यक्षेत्र और केरल राज्य के विद्वान वकील के अनुसार, विधेयक के तहत उनके पक्ष या विपक्ष में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कला के तहत उनका अधिकार है। 30 (1) और वे, विद्वान वकील कहते हैं, विधेयक द्वारा बाधित किए बिना अपने दिल की सामग्री के उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर, विधेयक की वैधता को चुनौती देने वाले संस्थानों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सी. एल. की ओर इशारा करते हैं। 26 जिस विधेयक का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। उनका कहना है कि यदि वर्तमान या भविष्य के शैक्षणिक संस्थान, जो पहली श्रेणी में आते हैं, मजबूरी के क्षेत्र में स्थित होते हैं तो उन्हें छात्रों की कमी के कारण सभी अभिभावकों के लिए बंद करना होगा

ऐसे क्षेत्र के भीतर रहने वाले हैं, क्ल द्वारा। 26 , आदेश दिया, सी. एल. द्वारा प्रदान किए गए दंड के दर्द पर। 28 , अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूलों या निजी स्कूलों में भेजना, जिसका अर्थ परिभाषा के अनुसार सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल है। खंड 26, यह आग्रह किया जाता है, अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को कम करता है और वास्तव में छीन लेता है। 30 (1) और इसलिए यह असंवैधानिक है। भीतर आने वाले शैक्षणिक संस्थान

पहली श्रेणी, जिन्हें सहायता या मान्यता नहीं दी जा रही है, वे सी. एल. द्वारा हैं। 38 , प्रथम दृष्टया विधेयक के दायरे से बाहर। विधेयक के प्रावधानों में से कोई भी नहीं जिसमें वे भी शामिल हैं

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्न उन पर लागू होता है और उनके द्वारा उठाए जाने वाले बिंदु के अनुसार, अर्थात् -

कला के तहत उनके अधिकार का उल्लंघन। 30 (1) सी. एल. द्वारा 26 विधेयक प्रश्न 2 के दायरे में नहीं आता है और हम वर्तमान संदर्भ पर उस बिंदु पर कोई राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं।

जहाँ तक दूसरी श्रेणी का संबंध है, हमें करना होगा

उप-इसे दो वर्गों में विभाजित करें, अर्थात् (क) वे जो स्वयं संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से पात्र बनाए गए हैं।

अनुदान प्राप्त करने के लिए, और (ख) वे जो संविधान के किसी स्पष्ट प्रावधान के आधार पर किसी भी अनुदान के हकदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी, सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।

आंग्ल-भारतीय शैक्षणिक संस्थान उप-श्रेणी (ए) में आते हैं। कला में एंग्लो-इंडियन को परिभाषित किया गया है। 366 (2) . एंग्लो-इंडियन समुदाय भारत में धर्म पर आधारित एक प्रसिद्ध अल्पसंख्यक समुदाय है।

भाषा के साथ-साथ एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को मान्यता दी गई है

1055

बम्बई राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा। बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी (1)। श्री फ्रैंक एंथनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत दो एंग्लो-इंडियन संस्थानों द्वारा दायर मामले के बयान में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है, भारत में 268 मान्यता प्राप्त एंग्लो-इंडियन स्कूल हैं जिनमें से दस केरल राज्य में हैं। 1948 से पहले स्थापित आंग्ल-भारतीय शैक्षणिक संस्थान उन दिनों की सरकार से अनुदान प्राप्त करते थे। अनुच्छेद 337, संभवतः संबंधित विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

लो-भारतीय समुदाय और उनकी प्रकृति को शांत करने के लिए

उनके भविष्य की भलाई के लिए डर, इस इनाम को दस साल की अवधि के लिए संरक्षित किया। उस अनुच्छेद के अनुसार 31 मार्च, 1948 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक अनुदान प्राप्त करने वाले सभी आंग्ल-भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को दस प्रतिशत की त्रैवार्षिक कमी के अधीन एक ही अनुदान प्राप्त होता रहेगा। दस साल की समाप्ति तक जब अनुदान, इस हद तक कि यह एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए एक विशेष रियायत है, बंद हो जाना चाहिए। दूसरा प्रावधान इस शर्त को लागू करता है कि कम से कम 40 प्रतिशत। वार्षिक प्रवेश सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी के अलावा अन्य समुदायों का। इसी तरह कला। 29 (2) अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर। ये एकमात्र संवैधानिक हैं

एंग्लो-इंडियन शैक्षिक संस्थानों के सहायता प्राप्त करने के अधिकार की सीमाएँ।

सीखा है।

स

लाहकार

दो एंग्लो-इंडियन स्कूलों के लिए उपस्थित होने के लिए प्रतिस्पर्धा

कि केरल राज्य कला के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य है। 337. वास्तव में यह कहा गया है कि

केरल राज्य द्वारा दायर मामले का बयान कि

सभी ईसाई स्कूलों को उस राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और

इसलिए, एंग्लो-इंडियन स्कूल, जो ईसाई स्कूल भी हैं, अब तक राज्य से प्राप्त कर रहे हैं

केरल अनुदान जिसके वे हकदार हैं

कला. 337. उनकी शिकायत यह है कि परिचय देकर।

(1) [1955] 1 एस. सी. आर. 568,583

134

यह विधेयक केरल राज्य अब लागू करना चाहता है, में उल्लिखित संवैधानिक सीमाओं के अलावा

कला के लिए दूसरा प्रावधान। 337 और कला। 29 (2) , एंग्लो को इस अनुदान पर आगे और अधिक कठिन शर्तें

भारतीय शैक्षणिक संस्थान हालांकि उनके स्थायी

इस तरह के अनुदान का न्यायिक अधिकार अभी भी मौजूद है। राज्य ने

उन पर स्पष्ट रूप से सख्त प्रावधान लागू हो रहे हैं

सी. एल. एस. 8 (3) , और सी. एल. द्वारा आकर्षित अन्य खंडों के अलावा 9 से 13 तक। 3 (5) विधेयक में कटौती और, के अनुसार

उन्हें, पूरी तरह से छीनते हुए, उनका संवैधानिक

के लिए एक कीमत के रूप में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार

जिसे कला के तहत अनुदान दिया जाता है। 337 , वे हकदार हैं

में उल्लिखित सीमा को छोड़कर सशर्त उस अनुच्छेद और कला में दूसरा परंतुक। 29 (2) .

केरल राज्य के लिए विद्वान वकील नहीं है

गंभीरता से विवाद, जैसा कि वास्तव में वह निष्पक्ष रूप से नहीं कर सकता है, कि

जहाँ तक कला के तहत अनुदान की बात है। 337 इस बात की चिंता है कि

आंग्ल-भारतीय शैक्षणिक संस्थान इसके हकदार हैं -

बिना किसी नए तार के समान प्राप्त करें

इस तरह के अनुदान से जुड़ा हुआ है, हालांकि वह थोड़ा सा सुझाव देता है

उस शब्द के अर्थ के भीतर "सहायता" के रूप में उपयोग किया जाता है बिल। हम उसके उस हिस्से को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

“ अनुदान कला में उपयोग किया जाता है। 337 "सहायता" शब्द का प्रयोग कला में किया जाता है। 29 (2) और कला। 30 (2) , लेकिन ऐसा नहीं हो सकता

सवाल यह है कि इन दो अनुच्छेदों में "सहायता" शब्द

कला के तहत "अनुदान" को शामिल किया जाएगा। 337. इससे पहले उक्त विधेयक द एंग्लो-इंडियन एजुकेशनल का पारित होना

संस्थानों को पहले मद्रास राज्य या त्रावणकोर-कोच्चि से और इसके गठन के बाद वर्तमान नए राज्य केरल से इनाम मिल रहा था। इन परिस्थितियों में, एंग्लो इंडियन संस्थानों द्वारा कला के तहत अनुदान के रूप में प्राप्त राशि। 337 होना चाहिए।

उक्त के अर्थ के भीतर "सहायता" के रूप में समझा गया

बिल और ये आंग्ल-भारतीय शैक्षणिक संस्थान

कला के तहत देय इस अनुदान की प्राप्ति में। 337 होना चाहिए।

तदनुसार एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के भीतर "सहायता प्राप्त स्कूलों" के रूप में माना जाए

1057

परिभाषाओं का अर्थ। 2 , उप-सीएलएस। (1) और

(6) . नए रूप में सख्त शर्तों को लागू करना

या इस अनुदान के लिए पूर्ववर्ती अतिरिक्त शर्तें

एंग्लो-इंडियन शैक्षणिक संस्थानों को,

इसलिए, न केवल कला के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। 337

लेकिन कला के तहत भी। 30 (1) . अगर एंग्लो-इंडियन शिक्षा राष्ट्रीय संस्थानों को वह अनुदान नहीं मिल सकता है जिसे वे देते हैं

प्रो द्वारा निर्धारित शर्तों को छोड़कर हकदार हैं

विधेयक के दर्शन तब, यदि वे अधिकार पर जोर देते हैं

कला द्वारा उन्हें गारंटीकृत प्रशासन। 30 (1) वे परंतुक के तहत अपने विकल्प का प्रयोग करना होगा

सी. एल. 3 (4) और केवल मान्यता के साथ संतुष्ट रहें,

उसमें उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन जो हो सकता है एक कष्टप्रद और असहनीय अतिक्रमण भी हो

उनके प्रशासन का अधिकार। लेकिन असली बात यह है कि

कि आधुनिक समय में कोई भी शैक्षणिक संस्थान ऐसा नहीं कर सकता है,

कुछ के बिना जीवित रहने और कुशलता से कार्य करने का सामर्थ्य

वे, हमारी राय में, वैध रूप से काम कर सकते हैं स्पष्ट करें कि जहाँ तक कला के तहत अनुदान की बात है। 337 हैं।

संबंधित, विधेयक के खंडों के प्रावधान

कला के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 30 (1) और उस हद तक शून्य हैं। यह विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया जाता है

केरल राज्य के लिए कि इस न्यायालय को नियम बनाए जाने तक इस प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर देना चाहिए, लेकिन यदि विधेयक के प्रावधान उनके लिए अप्रिय हैं, तो कोई भी नियम उस दोष को ठीक नहीं कर सकता है। न ही हम सोचते हैं

कि दिए गए तर्क में कोई सार है केरल के विद्वान वकील ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा नहीं है

कुछ भी नया शुरू किया गया और एंग्लो-इंडियन स्कूलों को उनके दायरे से परे कुछ भी नहीं दिया जा रहा है।

त्रावणकोर या कोचीन या मद्रास के शिक्षा अधिनियमों और संहिताओं के तहत प्रस्तुत कर रहे हैं। 1945 में या

1947 जब वे अधिनियम और संहिताएँ लागू हुईं

कोई मौलिक अधिकार नहीं थे और केवल गैर-के आधार पर मौलिक अधिकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इसका अभ्यास करें। यहाँ विरोध का कोई मामला नहीं है, यह मानते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1959] के खिलाफ विरोध हो सकता है।

संविधान। अतः इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि एंग्लो-इंडियन शैक्षणिक संस्थान जो हैं - कला के तहत अपने अनुदान के हकदार। 337 कठोर शर्तों और उक्त विधेयक के प्रावधानों के अधीन हैं जो वैध रूप से प्रश्न 2 के भीतर आते हैं क्योंकि हमारे द्वारा न केवल अनुच्छेद के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। 337 लेकिन कला के तहत उनके अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। 30 (1) कि उन्हें प्रभावी ढंग से व्यायाम करने से रोका जाता है

उन अधिकारों को। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी उपाय या उसके संबंध में किसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता का निर्धारण मौलिक अधिकार पर उसके वास्तविक प्रभाव और प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए। राशिद अहमद बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों को देखें।

नगर निगम बोर्ड कैराना का मामला (1), मोहम्मद। यासीन वी।

नगर क्षेत्र समिति, जलालाबाद का मामला (2 2) और बॉम्बे राज्य बनाम। बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी

मामला (3)।

केरल राज्य के लिए विद्वान वकील का अगला आग्रह

कि प्रत्येक एंग्लो-इंडियन शिक्षाविद

राष्ट्रीय संस्थानों को इससे कहीं अधिक मिल रहा है वे कला के तहत हकदार हैं। 337 और वह कॉन्स

जहाँ तक इन आंग्ल-भारतीय शिक्षाओं का संबंध है संस्थानों को उनके कारण से अधिक मिल रहा है

संस्थान 1948 के बाद शुरू हुए और अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थान

के किसी भी स्पष्ट प्रावधान के तहत सहायता का कोई अधिकार नहीं

संविधान लेकिन सहायता प्राप्त कर रहे हैं या इसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

यह हमें मामलों पर विचार करने के लिए ले जाता है

शैक्षणिक संस्थान जो उप-श्रेणी में आते हैं

(ख) ऊपर उल्लिखित, अर्थात्, वे संस्थान जो

किसी भी आधार पर सहायता के अनुदान के हकदार नहीं हैं

संविधान के प्रावधान को व्यक्त करें लेकिन, फिर भी,

राज्य से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करें।

हम उस कला को पहले ही देख चुके हैं। 337 संविधान का

राष्ट्र एंग्लो को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान करता है

इससे पहले स्थापित भारतीय शैक्षणिक संस्थान

1948. इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

. द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सहायता का अनुदान

(2) [1952] एस. सी. आर. 572,577

(1) [1950] एस. सी. आर. 566,571

(3) [1955] 1 एस. सी. आर. 568,583

एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1059

1948 के बाद एंग्लो-इंडियन समुदाय या उनके लिए

किसी भी आई में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित

समय। अन्य अल्पसंख्यक समुदाय या यहाँ तक कि

1948 के बाद के संबंध में एंग्लो-भारतीय समुदाय

शैक्षणिक संस्थानों को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।

मौलिक या अन्यथा, से कोई अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य। लेकिन यह सर्वविदित है कि

आधुनिक समय की माँगें और आवश्यकताएँ

शैक्षणिक संस्थानों को उचित और कुशल होना चाहिए

दौड़ने के लिए काफी खर्च की आवश्यकता होती है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है

पूरी तरह से विद्वानों और निजी लोगों से एकत्र शुल्क द्वारा

पर्याप्त सहायता के बिना दक्षता और उपयोगिता राज्य से। अनुच्छेद 28 (3), 29 (2) और 30 (2) अभिनिर्धारित करते हैं।

राज्य से बाहर सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान

कोष। अब विचाराधीन विधेयक के अनुसार राज्य केरल सरकार भी सहायता देने पर विचार कर रही है

शैक्षणिक संस्थान। तथापि उक्त विधेयक, पूर्ववर्ती शर्तों के रूप में कठोर शर्तें लागू करता है

विधेयक के दृष्टिकोण को पहले ही संक्षेप में प्रस्तुत किया जा चुका है इस राय के पहले भाग में विस्तार से और आवश्यक नहीं है

पुनरावृत्ति की जाए। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यदि उक्त विधेयक

राज्य से सहायता प्राप्त करने के लिए तब कानून बन जाता है

कोष, एक शैक्षणिक संस्थान को जमा करना होगा

सीएलएस में निर्धारित शर्तों के लिए। 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,

11 , 12 , 14 , 15 और 20. खंड 36 सरकार को सशक्त बनाता है

सहायता प्रदान करने के लिए नियम बनाने का विचार

निजी स्कूलों में। के लिए उपस्थित विद्वान वकील विधेयक का विरोध करने वाले शैक्षणिक संस्थानों ने शिकायत की

कि वे खंड अपने ग्राहकों को वस्तुतः वंचित कर देते हैं कला के तहत उनके अधिकार। 30 (1) .

उनकी शिकायतें इस प्रकार बताई गई हैं: इसका सार

एक स्कूल के प्रशासन का अधिकार की शक्ति है

शिक्षकों की नियुक्ति, नियंत्रण और बर्खास्तगी और

अन्य कर्मचारी। लेकिन उक्त विधेयक के तहत ऐसी शक्ति

प्रबंधन व्यावहारिक रूप से छीन लिया जाता है। इस प्रकार यह प्रबंधक को वार्षिक विवरण (सी. एल.) प्रस्तुत करना होगा। 5)। द.

लेखक की अनुमति के अलावा निपटा जाए सेवानिवृत्त अधिकारी (सीएल. 6)। सहायता प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की कोई शैक्षणिक एजेंसी नहीं

1060

[1959]

विद्यालय अपनी पसंद के प्रबंधक की नियुक्ति कर सकता है और

प्रबंधक पूरी तरह से लेखक के नियंत्रण में है।

में।

सेवानिवृत्त अधिकारी, क्योंकि उसे तरीके से लेखा रखना चाहिए

उसे आवधिक निरीक्षण करने और देने के लिए कहा जाता है

उन्हें, और स्कूल के बंद होने पर खाते

अधिकृत अधिकारी (सी. एल.) को सौंपा जाना चाहिए। 7)। एकत्र किए गए सभी शुल्कों आदि का भुगतान करना होगा

सरकार (सीएल। 8 (3)) . सरकार उठाएगी कदम

शिक्षकों और गैर-शिक्षण को भुगतान करने का कार्य

उनकी पसंद के एक शिक्षक को नियुक्त करें, लेकिन उन्हें करना होगा जनता द्वारा तय किए गए पैनल से व्यक्तियों को नियुक्त करें

सेवा आयोग (सी. 11)। स्कूल अधिकारियों ने

शिक्षकों को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता है,

बिना किसी शिक्षक को हटाए, कम करें या निलंबित भी करें। प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी (सी. एल. 12)।

सरकार प्रबंधन को अपने हाथ में ले सकती है।

कुछ मामलों के बारे में संतुष्ट और फिर इसे प्राप्त कर सकते हैं

बिल्कुल (सी. एल.) 14) और यह सहायता प्राप्त भी कर सकता है

जिस पर आसानी से मनोरंजन किया जा सकता है विचार (सी. एल. 15)। खंड 20 आकस्मिक रूप से एक

निजी विद्यालय, जिसका अर्थ है सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय

स्कूल, प्राथमिक में ट्यूशन के लिए कोई भी शुल्क लेने से ऐसे वर्ग जहाँ विद्वानों की संख्या सबसे अधिक हो।

तदनुसार वे तर्क देते हैं कि वे प्रावधान करते हैं उनके द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना।

कला. 30 (1) .

केरल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

कला के चरम विवाद को आगे बढ़ाता है। 30 (1)

अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन

इस तरह के अधिकारों का प्रयोग जितना वे चाहते हैं और जितना वे चाहते हैं जैसा कि वे अपने संसाधनों पर ऐसा करने की परवाह करते हैं। लेकिन यह

मौलिक अधिकार इससे आगे नहीं जाता है और संभवतः नहीं जा सकता है।

राज्य के खजाने। यदि वे चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं राज्य से सहायता, उन्हें शर्तों का पालन करना होगा

जिसे राज्य अन्य सभी शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है।

एक व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों द्वारा स्थापित संस्थान एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

1061

यदि वह किसी अंतर्देशीय पत्र के लिए डाक टिकट खरीदना चाहता है तो उसे 15 पैसे का भुगतान करना होगा। दो एंग्लो-इंडियन स्कूलों के साथ-साथ विद्वान परामर्श भी दिखाई देते हैं।

दूसरी ओर, जमात-उल-उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश विद्वान वकील, अपनी ओर से, एक समान चरम प्रस्ताव पर जोर देते हैं, अर्थात्, कला के तहत उनके मुवक्किलों के मौलिक अधिकार। 30 (1) शब्दों में, निरपेक्ष हैं और न केवल इसे हटाया जा सकता है बल्कि किसी भी हद तक संक्षिप्त भी नहीं किया जा सकता है। वे हमारा ध्यान सबसे पहले कला की ओर आकर्षित करते हैं। 19 (1) (छ) जो नागरिकों को किसी भी कार्य को करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

व्यापार और फिर सी. एल. 6 उस अनुच्छेद का जो उस मौलिक मानसिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है और वे तर्क देते हैं कि, जैसा कि कोई नहीं है

कला में ऐसा प्रावधान। 30 (1) राज्य को सामाजिक दायित्वों को लागू करने के लिए कोई भी पुलिस शक्ति प्रदान करना।

नियंत्रण, कला के तहत मौलिक अधिकार। 30 (1) इसे निरपेक्ष माना जाना चाहिए और किसी भी तरह के प्रतिबंध के अधीन नहीं किया जा सकता है। वे कला पर भरोसा करके अपने तर्कों को मजबूत करते हैं। 28 (3) , 29 (2) और 30 (2) जो, वे उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं, सहायता के अनुदान पर विचार करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान

मुद्राएँ। विद्वान परामर्शदाता भी कला पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं। 41 और संविधान का 46 जो, निर्देश के रूप में

राज्य नीति के सिद्धांत, शैक्षणिक संस्थानों की सहायता करना और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य बनाते हैं और लोगों का कमजोर वर्ग। विद्वान देशों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करना सरकार का सामान्य कार्य है। द.

संविधान में राज्य द्वारा पूरी तरह से प्रभावित संस्थानों के साथ-साथ राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों पर भी विचार किया गया है। यदि, इसलिए, सहायता प्रदान करना एक सरकारी कार्य है, तो वे कहते हैं, इसे उचित तरीके से और अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना आरोप लगाया जाना चाहिए। किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने वाले किसी भी व्यक्ति या निकाय को राज्य से सहायता प्राप्त करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया जा सकता है और वास्तव में यदि राज्य के पास पर्याप्त धन नहीं है तो वह किसी को भी वितरित नहीं कर सकता है। फिर भी अगर

राज्य सहायता वितरित करता है, उनका तर्क है कि वह इसके साथ ऐसी शर्तें नहीं जोड़ सकता है जो 1062 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1959] को वंचित कर देंगी।

कला के तहत उनके मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यक। 30 (1) . सख्त शर्तों को जोड़ना, जैसे कि वे समर्थक

उक्त विधेयक द्वारा समर्थित और ऊपर संक्षेपित, अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों को गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है। 30 (1) . उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मौलिक अधिकारों के समर्पण को राज्य द्वारा दी गई सहायता की कीमत के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

इस प्रकार हम काफी जटिलता की समस्या का सामना कर रहे हैं जिसका समाधान करना स्पष्ट रूप से कठिन है। वहाँ है।

एक तरफ अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार। 30 (1) अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना और सरकार का कर्तव्य

दूसरी ओर, कला के तहत शिक्षा को बढ़ावा देना राज्य का दायित्व है। 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा शुरू करने का प्रयास करना। . हमें इन दोनों परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा

और यदि संभव हो तो दोनों को प्रभावी बनाना और दोनों के बीच एक संश्लेषण लाना। निर्देशक सिद्धांत मूल बातों को नजरअंदाज या ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अधिकार लेकिन, जैसा कि हमने कहा है, मानसिक अधिकारों के आधार पर होना चाहिए। हम. पहले ही देखा जा चुका है कि

कला. 30 (1) अल्पसंख्यकों को दो अधिकार देता है, (1) अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और (2) उनका प्रशासन करना। प्रशासन के अधिकार में स्पष्ट रूप से कुशासन का अधिकार शामिल नहीं हो सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग निश्चित रूप से ऐसे शैक्षणिक संस्थान के लिए सहायता या मान्यता नहीं मांग सकता है जो उनके द्वारा अस्वास्थ्यकर परिवेश में, बिना किसी सक्षम शिक्षक के, योग्यता की कोई झलक रखने वाले, और जो शिक्षण के उचित मानक को भी बनाए नहीं रखता है या जो विद्वानों के कल्याण के प्रतिकूल मामलों को पढ़ाता है। अतः यह तर्कसंगत है कि उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने का संवैधानिक अधिकार आवश्यक रूप से राज्य के इस दावे के खिलाफ नहीं है कि सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए उचित विनियम निर्धारित कर सकता है। विद्वान महान्यायवादी स्वीकार करते हैं कि राज्य द्वारा सहायता या यहां तक कि मान्यता के लिए एक शर्त के रूप में तर्क योग्य विनियम निश्चित रूप से लगाए जा सकते हैं। एंग्लो-इंडियंस के अलावा किसी भी अल्पसंख्यक को सहायता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उनका तर्क है कि यदि राज्य एस. सी. आर. को चुनता है तो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1063

सहायता प्रदान करें तो यह नहीं कहना चाहिए-"मेरे पास पैसा है और मैं।

सहायता वितरित करूँगा लेकिन मैं आपको कोई सहायता नहीं दूंगा। जब तक आप मुझे अपने प्रशासन के अधिकार का समर्पण नहीं करते

यह "।

राज्य को इस तरह से सहायता नहीं देनी चाहिए।

जैसा कि मौलिक अधिकार को छीन लेगा

कला के तहत अल्पसंख्यक समुदाय। 30 (1) . श्री जी. एस. पाठक

विरोध करने वाले कुछ संस्थानों के लिए उपस्थित होना

विधेयक इस बात से सहमत है कि यह राज्य के लिए निर्धारित करने के लिए खुला है

मान्यता के लिए शर्तें, अर्थात्, कि एक संस्था धन या संपत्तियों की एक विशेष राशि होनी चाहिए

ऐसी मान्यता या सहायता के लिए निर्धारित शर्तें तथापि, बशर्ते कि ऐसा कानून संवैधानिक हो और

किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है

अल्पसंख्यक। श्री ने कहा कि मान्यता और सहायता का अनुदान

जी. एस. पाठक, सरकारी कार्य है और,

इसलिए, राज्य शर्तों को लागू नहीं कर सकता है।

मान्यता या सहायता के अनुदान के लिए पूर्ववर्ती जो

केरल राज्य द्वारा दायर मामले का बयान, प्रत्येक राज्य में ईसाई स्कूल को राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

अतः उक्त विधेयक द्वारा लगाई गई शर्तें -

द्वारा स्थापित और प्रशासित सहायता प्राप्त संस्थान ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदाय, जिनमें शामिल हैं

एंग्लो-इंडियन समुदाय, बंद होने की ओर ले जाएगा

इन सभी सहायता प्राप्त स्कूलों को तब तक बंद कर दें जब तक कि वे सहमत न हों

प्रबंधन के अपने मौलिक अधिकार का समर्पण करने में सक्षम

मन में। वास्तव में कोई भी शैक्षणिक संस्थान ऐसा नहीं कर सकता है। राज्य की सहायता के बिना अभ्यास किया जाए और

वित्तीय आवश्यकताओं की मजबूरी से वे अधिकार प्राप्त करेंगे, कला के तहत अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। 30 (1) .

विधायिकाओं को प्रदत्त विधायी शक्तियाँ

कला द्वारा राज्य। 245 और 246 संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं और निश्चित रूप से

भाग III के प्रावधान जो मौलिक प्रदान करते हैं

ऐसे अधिकार जो इसलिए राज्य विधानमंडलों के लिए बाध्यकारी हैं। यह स्पष्ट है कि राज्य विधानसभाएं उन प्रावधानों की अवहेलना या ओवरराइड नहीं कर सकती हैं।

सटीक रूप से प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करना

[1959]

एक ही परिणाम। यहां तक कि विधायिका भी अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकती जो वह निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती। फिर भी यह विधेयक के इन प्रावधानों के लागू होने और इस न्यायालय के फैसलों के अनुसार प्रभाव होगा।

जिसे पहले ही संदर्भित किया जा चुका है, वह वास्तविक प्रभाव है जिसके संबंध में

किसी भी उपाय की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में होना चाहिए। खंड 6,7,9,10,11,12,14,15 और 20 सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन से संबंधित हैं।

इनमें से कुछ प्रावधानों, जैसे 7,10,11 (1), 12 (1) (2) (3) और (5) को आसानी से उचित नियम माना जा सकता है। सहायता प्रदान करने के लिए राज्य या शर्तें। हालांकि, खंड 9,11 (2) और 12 (4) पर आपत्ति जताई गई है

धार्मिक संप्रदायों के लिए और पार्टी में स्वीकार्य होना कुलर उप-सी. एल. (2) उस खंड का हिस्सा आपत्तिजनक है क्योंकि यह धार्मिक संस्थानों पर बल देता है।

अनुसूचित जातियों के अल्पसंख्यक शिक्षक जिन्हें अपने धर्म के सिद्धांतों का कोई ज्ञान नहीं हो सकता है और अन्यथा वे शैक्षिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। बर्खास्तगी, हटाने, रैंक में कमी या निलंबन की शक्ति प्रबंधन के अधिकार का एक सूचकांक है और जिसे सी. एल. द्वारा छीन लिया जाता है। 12 (4) . इनमें कोई संदेह नहीं है कि ये प्रशासन के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण हैं और खतरनाक रूप से निकट प्रतीत होते हैं।

उस अधिकार का उल्लंघन करना। लेकिन यह देखते हुए कि वे अनुकूल दृष्टिकोण सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होते हैं

और यह कि सी. एल. एस. के विवादित भाग। 9 , 11 और 12 को खराब वेतन पाने वाले शिक्षकों को सुरक्षा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो राष्ट्र की सेवा करने और पिछड़े वर्गों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, इन खंड 9,11 (2) और 12 (4) को अनुमेय विनियमों के रूप में माना जाए जो एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट करता है।

1065

राज्य अल्पसंख्यकों पर एक शर्त के रूप में लागू कर सकता है

उनके शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करना। हम,

हालाँकि, सी. एल. एस. का समर्थन करना असंभव लगता है। 14 और 15 में से

उक्त विधेयक मात्र विनियमों के रूप में। के प्रावधान वे खंड अधिकारों के लिए पूरी तरह से विनाशकारी हो सकते हैं।

कला के तहत। 30 (1) . यह सच है कि सहायता का अधिकार नहीं है

कला में निहित। 30 (1) लेकिन उन खंडों के प्रावधान,

यदि उनकी तथ्यात्मक मजबूरी के कारण प्रस्तुत किया जाता है

सहायता की शर्त के रूप में, आसानी से कला का उल्लंघन हो सकता है। 30 (1) . संविधान से। राज्य के लिए विद्वान वकील केरल इस बात को पहचानता है। 14 और विधेयक का 15 अल्पसंख्यक समुदायों के प्रबंधन के अधिकार को समाप्त कर सकता है।

अपनी पसंद के लेकिन प्रस्तुत करने वाले शैक्षणिक संस्थान

कि उन खंडों की वैधता विषय नहीं है

प्रश्न 2 का विषय। लेकिन, जैसा कि पहले ही समझाया जा चुका है, सभी

सहायता या मान्यता प्राप्त करने के लिए नव स्थापित विद्यालय

सी. एल. की राष्ट्रीय वैधता। 3 (5) की वैधता पर चर्चा विधेयक के अन्य खंड प्रासंगिक हो जाते हैं, न कि

और एक अलग वस्तु के माध्यम से लेकिन निर्धारित करने में सी. एल के प्रावधानों की वैधता। 3 (5) . हमारी राय में,

उप-सी. एल. 3 सी. एल. 8 और सीएलएस। 9 , 10 , 11 , 12 और 13 हैं

केवल नियामक कला का अपमान नहीं करते हैं। 30 (1) , लेकिन

उप-क्ल के प्रावधान। (5) सी. एल. 3 सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को सी. एल. एस. के अधीन बनाकर। 14 और 15

सहायता के अनुदान के लिए शर्तें इसके खिलाफ अपराध करती हैं। कला. 30 (1) संविधान से।

अब हम शिक्षा की अंतिम श्रेणी पर आते हैं।

अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थान जो केवल मान्यता चाहते हैं लेकिन राज्य से सहायता नहीं चाहते हैं। केरल राज्य के विद्वान वकील और दोनों के विद्वान वकील द्वारा मान्यता के संबंध में चरम तर्क आगे बढ़े।

एंग्लो-इंडियन स्कूल और विद्वान के लिए परामर्श

मुस्लिम संस्थान उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हैं जैसे उनके द्वारा इस सवाल पर आगे बढ़ाया गया था कि

सहायता प्रदान करना, अर्थात् केरल राज्य

यह कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय कला के तहत अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 30 (1) जहाँ भी वे चाहें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके और उन्हें अपने तरीके से सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट (1959) द्वारा प्रशासित करके।

और सरकार से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि अल्पसंख्यक समुदाय राज्य की मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें शर्तों का पालन करना होगा।

प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान पर मान्यता के लिए पूर्ववर्ती शर्तों के रूप में लागू किया गया। दूसरी ओर, अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों का दावा है कि कला के तहत उनका मौलिक अधिकार है। 30 (1) निरपेक्ष है और किसी भी तरह के प्रतिबंध के अधीन नहीं किया जा सकता है। उन दोनों के लिए सीखी हुई सलाह

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर भरोसा करते हुए इस संदर्भ में उपस्थित एंग्लो-इंडियन स्कूलों का कहना है कि एक बच्चा राज्य का प्राणी नहीं है और माता-पिता को अपने बच्चे को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा दिलाने का अधिकार है। वे अमेरिकी निर्णय पांचवें और चौदहवें संशोधनों के उचित प्रक्रिया खंडों की भाषा पर आगे बढ़ते हैं और हमारे संविधान के तहत उत्पन्न होने वाली स्थिति पर कोई लागू नहीं होते हैं और हमें आगे, यहां विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने प्रस्तुत किए गए दो परस्पर विरोधी विचारों को दोहराते हुए हम दोहराते हैं कि दोनों चरम प्रस्तावों में से किसी को भी कायम नहीं रखा जा सकता है और यदि संभव हो तो हमें दोनों में सामंजस्य स्थापित करना होगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को स्वतंत्रता देता है।

या धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य और स्वास्थ्य के अधीन, इसकी कोई धारा। अनुच्छेद 29 (1) भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा और उनके माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही उनकी संस्कृति को लोगों के प्रभावशाली दिमागों में शामिल किया जा सकता है।

अपने समुदाय के बच्चे। यह शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से है कि मिनो रिति समुदाय की भाषा और लिपि को संरक्षित किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है और मजबूत हुआ। इसलिए यह वह कला है। 30 (1) सभी अल्पसंख्यकों को प्रदान करता है, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो

आयु, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अल्पसंख्यक, काफी हद तक, इसे आवश्यक मानते हैं कि शिक्षा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट हो

1067

एस सी आर।

उनके बच्चों की शिक्षा उनके धर्म की शिक्षाओं के अनुसार होनी चाहिए और वे पूरी ईमानदारी से मानते हैं कि इस तरह की शिक्षा आम स्कूलों में प्राप्त नहीं की जा सकती है जो जनता के सभी सदस्यों के लिए बनाई गई है, लेकिन केवल इसके तहत संचालित स्कूलों में ही सुरक्षित की जा सकती है।

अपने धर्म के सिद्धांतों और अपनी परंपराओं में अच्छी तरह से पारंगत लोगों का प्रभाव और मार्गदर्शन

संस्कृति। अल्पसंख्यक स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि शिक्षा

यह उनके समुदाय के बच्चों को उनकी संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल वातावरण में प्रदान किया जाना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने दावे की वैधता को स्वीकार किया और उनके डर को दूर किया

उन पर ऊपर उल्लिखित मौलिक अधिकार लाल हो जाते हैं।

लेकिन विशिष्ट भाषा, लिपि का संरक्षण

या संस्कृति ही मिनो की पसंद का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। धार्मिक समुदाय। वे यह भी चाहते हैं कि विद्वान

उनके शैक्षणिक संस्थानों को दुनिया में अच्छी तरह से जाना चाहिए और योग्यता के साथ पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए

जीवन में एक उपयोगी कैरियर के लिए आवश्यक। लेकिन समझौता करें।

शिक्षा संहिता, जो अब लागू है, जिसके प्रभाव का पता लगाने के लिए इसे संदर्भित करने की अनुमति है

गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्वानों को अनुमति नहीं है उच्चतर अवसरों का लाभ उठाने के लिए

सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश करना। बिना मान्यता के, इसलिए, स्थापित शैक्षणिक संस्थान या

अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता है

अपनी पसंद और अधिकारों के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा करें।

कला के तहत। 30 (1) प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। द.

उनके शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार

इसलिए, चयन का अर्थ वास्तविक स्थिति स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए।

संस्थान जो प्रभावी रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे उनके समुदाय और विद्वान जो उनका सहारा लेते हैं

शैक्षणिक संस्थान। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा नहीं है।

राज्य द्वारा मान्यता के मौलिक अधिकार के रूप में लेकिन शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने से इनकार करना

के समर्पण के समान शर्तों को छोड़कर

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन का उनका संवैधानिक अधिकार वास्तव में और प्रभावी रूप से उन्हें कला के तहत उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए है। 30 (1) . हम दोहराते हैं कि विधायी शक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अधीन है

1068

[1959]

मौलिक अधिकार और विधायिका अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों को छीनना या कम करना जो

ला

उक्त विधेयक जिसमें कोई भी उल्लंघनकारी खंड हो जाता है कानून। इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार

ऊपर, किसी भी कानून की वैधता का न्याय करने में

अपने वास्तविक इरादे और प्रभाव के लिए होना चाहिए

पीड़ित पक्षों के अधिकार, इसके रूप के बजाय।

शिक्षा संहिता के अनुसार कुछ शर्तें

निर्धारित किए जाते हैं-चाहे विधायी के रूप में या कार्यकारी के रूप में

जिन उपायों के लिए हम पूछताछ करना बंद नहीं करते हैं-शर्त के रूप में

मान्यता का अनुदान और यह कहा जाता है, जैसा कि कहा गया था

सहायता के प्रश्न पर चर्चा के दौरान, कि

कहा गया विधेयक इन से अधिक बोझ नहीं लगाता है

अन्य समुदाय पहले से ही इसके अधीन हैं। जैसे हम। देखा है, नुकसान का कोई सवाल नहीं हो सकता है

केवल इसका प्रयोग न करने से एक मौलिक अधिकार। यहाँ किसी भी अवरोध का कोई मामला नहीं है, यह मानते हुए कि

संविधान के खिलाफ कोई भी अवरोध हो सकता है।

अतः उक्त विधेयक के विवादित प्रावधान

इसके गुणों पर विचार किया जाना चाहिए।

सीएल द्वारा। 19 निम्नलिखित खंड, अर्थात् 7 (सिवाय इसके कि

उप-सीएलएस। 1 और 3 जो केवल सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होते हैं),

10 और 20 को मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू किया गया था।

हम उप-संघों के प्रावधानों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। 2 ,

4 सीएल के 9 तक। 7 और सी. एल के प्रावधान। 10 अनुमेय रूप से

नियम लेकिन सी. एल. का इलाज करना मुश्किल है। 20 बस के रूप में

नियामक। उस खंड के लिए अनिवार्य रूप से यह आवश्यक है कि

प्राइमरी में ट्यूशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

कक्षाएँ। संख्या को लेकर कोई विवाद नहीं है। छात्रों की

प्राथमिक कक्षाओं में अन्य की तुलना में अधिक है

कक्षाएँ। स्कूल जाने वाले बच्चों के 1955-1956 आंकड़े,

जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है, उस उम्र को दिखाएँ

6 से 11 प्रतिशत का समूह। लड़कों की कक्षाओं में भाग लेना,

जबकि 91 प्रतिशत। उस आयु वर्ग की लड़कियों में से

जब हम आते हैं तो उपस्थिति में कमी आती है

एक ही।

आयु वर्ग 11 से 14 तक। उस आयु वर्ग में 36.2 प्रति

प्रतिशत। लड़कों और 29 प्रतिशत। लड़कियाँ स्कूल जाती हैं। यह.

इसलिए यह स्पष्ट है कि हालांकि शुल्क की दर वसूल की जाती है

प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा उन लोगों की तुलना में कम है जिन पर शुल्क लिया जाता है उच्च वर्ग, विद्वानों से एकत्र की गई कुल राशि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

प्राथमिक कक्षाओं में भाग लेना काफी महत्वपूर्ण है और यह विद्यालय की कुल आय का एक सराहनीय हिस्सा है। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है, तो इन सभी विद्यालयों को आय के इस फलदायी स्रोत को छोड़ना होगा। हालाँकि, शुल्क के नुकसान को संतुलित करने का कोई प्रावधान नहीं है जो सी. एल. द्वारा लाया जाएगा। 20 जब यह लागू होता है। कोई प्रावधान नहीं है, जैसे कि सी. एल. में है। 9 जो केवल सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होता है, कि राज्य को उस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। इसलिए,

मान्यता की शर्त के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में किसी भी छात्र से शुल्क संग्रह के खिलाफ इस तरह के प्रतिबंध लगाने से प्रभावी रूप से अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान के लिए इसे लागू करना अनिवार्य हो जाएगा। यह सच है कि सी. एल. 36 (2) (ग) सरकार को नियम बनाने का अधिकार देता है। निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान और हमें अपनी राय को तब तक निलंबित करने के लिए कहा जाता है जब तक कि उक्त विधेयक लागू नहीं हो जाता और नियम वास्तव में नहीं बनाए जाते। लेकिन सी. एल. के तहत कोई नियम नहीं बनाया जाएगा। 36 (2) (ग) सी. एल. की संवैधानिक दुर्बलता को समाप्त कर सकता है। 3 (5) के साथ पढ़ें

सी. एल. 20 जिसकी गणना उक्त विधेयक के प्रारंभ के बाद स्थापित किए जाने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए की गई है।

केरल राज्य के विद्वान वकील ने हमें संदर्भित किया

कला में निहित निर्देशक सिद्धांत। 45 जिसके लिए राज्य को संविधान के प्रारंभ से दस साल की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना आवश्यक है, जब तक कि वे चौदह साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते और काफी गर्मजोशी और आक्रोश के साथ। राष्ट्र ने कहा कि किसी भी अल्पसंख्यक को देश के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के राज्य के पवित्र कर्तव्य के कार्यान्वयन के रास्ते में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि उनका उचित पालन-पोषण किया जा सके और उन्हें अच्छे नागरिकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। विद्वान वकील के अनुसार, इन अल्पसंख्यकों के स्वार्थी दावों को लुभाना प्रगति की घड़ी के हाथों को पीछे हटाना है। क्या ये चाहिए? विद्वान वकील ने कहा कि अल्पसंख्यकों को लोगों के सांप्रदायिक विखंडन को बनाए रखने की अनुमति दी जाए-सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1959]

और उन्हें अलग-अलग और अलग-थलग सांस्कृतिक परिक्षेत्रों में हमेशा अलग-थलग रखना और इस तरह राष्ट्र की एकता को बाधित करना? अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए विद्वान परामर्श अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति राज्य के पवित्र दायित्व के लिए समान रूप से वाक्पटु थे। देश के सर्वोच्च कानून के विवेक पर सवाल उठाना इस न्यायालय का काम नहीं है। हम भारत के लोगों ने खुद को वह संविधान दिया है जो किसी भी पक्षीय समुदाय या वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। इसके प्रावधानों का उद्देश्य सभी, अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक समुदायों की रक्षा करना है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि हमारे संविधान ने अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति और धर्म के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों की गारंटी दी है। ये रियायतें उन्हें अच्छे और वैध कारणों से दी गई होंगी। अनुच्छेद 45, निस्संदेह, राज्य से सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा करता है, लेकिन राज्य को सरकार और सहायता प्राप्त लोगों के माध्यम से उस गंभीर दायित्व का निर्वहन करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। स्कूल और कला। 45 उस दायित्व की आवश्यकता नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के धन की कीमत पर निर्वहन किया जाना। जब तक संविधान वैसा ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, हम समझते हैं कि यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मौलिक अधिकारों को बनाए रखे और इस प्रकार

अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति हमारे पवित्र दायित्व का सम्मान करें जो हमारे अपने हैं। सदियों से विभिन्न पंथों, संस्कृतियों और जातियों के लोगों की अंतहीन बाढ़-आर्य और गैर-आर्य, द्रविड़ और चीनी, सिथियन, हूण, पठान और मुगल दूरदराज के क्षेत्रों और जलवायु से इस प्राचीन भूमि पर आए हैं। भारत ने उन सभी का स्वागत किया है। वे मिले और इकट्ठे हुए, दिए और लिए और मिले, एक शरीर में विलीन हो गए और खो गए। इस प्रकार भारत की परंपरा को निम्नलिखित महान पंक्तियों में दर्शाया गया है:

" किसी को भी नहीं मोड़ा जाएगा। मानवता के इस विशाल समुद्र के तट से जो भारत है।

वास्तव में भारत ने हमारे राष्ट्रगान में निहित और घोषित सद्भावना का संदेश दुनिया को भेजा है:

* रवींद्रनाथ टैगोर की कविताएँ।

" दिन-रात तेरी आवाज़ निकलती है

भूमि से भूमि तक,

हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों को बुलाना

अपने सिंहासन के चारों ओर

और पारसी, मुसलमान और ईसाई। भेंट आपके मंदिर में लाए जाते हैं

पूर्व और पश्चिम

प्रेम की माला में बुना जाना।

आप सभी लोगों के दिलों को लाते हैं

एक जीवन के सामंजस्य में,

आप भारत के भाग्य के वितरक हैं,

विजय, विजय, विजय आपको "। *

यह इस प्रकार है कि भारत की प्रतिभा सभी पंथ और संस्कृतियों में से सर्वश्रेष्ठ को आत्मसात करके विविधता में एकता खोजने में सक्षम रही है। हमारा संविधान तदनुसार अल्पसंख्यकों के प्रति हमारे पवित्र दायित्वों को मान्यता देता है। ऊपर बताए गए दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से हमारे संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को गारंटीकृत अधिकारों को देखते हुए, हम

अनुमेय विनियम के रूप में माना जाता है जिसे राज्य अपने अनुसार एक शर्त के रूप में लागू करने का हकदार है किसी भी शैक्षणिक संस्थान को मान्यता लेकिन वह सी. एल. 20 जिसे सी. एल. द्वारा बढ़ाया गया है। 3 (5) जहां तक यह अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों को प्रभावित करता है, नए स्थापित मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए यह कला का उल्लंघन है। 30 (1) .

री. प्रश्न 4: यह सवाल संविधान को उठाता है।

सी. एल. की राष्ट्रीय वैधता। 33 उक्त विधेयक का। वह खंड, जिसे यहाँ पहले पूरी तरह से निर्धारित किया गया है, यह प्रावधान करता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद कोई भी न्यायालय कोई अस्थायी अनुमति नहीं देगा।

किसी भी कार्यवाही को रोकने के लिए निषेधाज्ञा या कोई अंतरिम आदेश देना जो विधेयक के प्रावधानों के तहत की जा रही है या होने वाली है जब यह एक अधिनियम बन जाता है। संविधान का अनुच्छेद 226 राज्यों में उच्च न्यायालयों को व्यापक अधिकार क्षेत्र और शक्ति प्रदान करता है।

यह अधिकार क्षेत्र और शक्ति उन सभी क्षेत्रों में फैली हुई है जिनके संबंध में उच्च न्यायालय प्रयोग करता है।

* रवींद्रनाथ टैगोर।

अधिकार क्षेत्र। यह किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी कर सकता है, जिसमें उपयुक्त मामलों में कोई भी सरकार शामिल है। कोष के प्रवर्तन के लिए उसमें उल्लिखित प्रकृति के वे क्षेत्र, निर्देश, आदेश या रिट

मानसिक अधिकार या किसी अन्य उद्देश्य के लिए। राज्य विधानमंडल का कोई भी अधिनियम, जब तक वह अनुच्छेद बना हुआ है, उस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और शक्ति को छीन या कम नहीं कर सकता है। सवाल यह है कि क्या सी. एल. 33 ऐसा करते हैं। सी. एल. के संबंध में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं। 33 इस प्रकार संदर्भ के क्रम में म्यूलेट किए जाते हैं:

" और जहां उक्त विधेयक का खंड 33 इसके पक्ष में है

यह स्पष्ट करता है कि, इसमें निहित कुछ भी होने के बावजूद

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, या उस समय लागू कोई अन्य कानून, कोई भी अदालत कोई अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दे सकती है या कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दे सकती है जो अधिनियम के तहत की जा रही या होने वाली किसी भी कार्यवाही को रोकती है।

और जहाँ एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या

उक्त खंड 33 के प्रावधान, जहाँ तक वे उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित हैं, अपराध करेंगे।

संविधान का अनुच्छेद 226 "।

केरल राज्य ने अपने मामले के बयान में निम्नलिखित शब्दों में उस संबंध में सभी इरादों का खंडन किया है:

" 52. केरल राज्य ने इस माननीय न्यायालय से कहा है कि

चौथे प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दें, इस आधार पर कि कला द्वारा उच्च न्यायालयों को दी गई शक्ति। 226 उक्त सी. एल. से अप्रभावित रहता है। 33 .

53. केरल राज्य का तर्क है कि

वह सी. एल. 33 कला को प्रभावित करता है। 226 बिना नींव के है।

54. संविधान सर्वोपरि कानून है

भूमि, और संविधान के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक संशोधन से कम कुछ भी संविधान के किसी भी प्रावधान को प्रभावित नहीं कर सकता है, जिसमें शामिल हैं -

कला. 226. उच्च न्यायालयों को प्रदत्त शक्ति

कला के तहत। 226 संविधान एक अति-सवारी है

कुछ शर्तों और परिस्थितियों में उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों को रिट, आदेश और निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, जो इसके विपरीत कोई नियम या कानून नहीं है।

केरल राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि सी. एल. 33 कला के विषय में पढ़ा जाना चाहिए। 226 और आई के 32

एयू

!

एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1073

संविधान। वह निर्माण के प्रसिद्ध सिद्धांत पर भरोसा करते हैं कि यदि किसी क़ानून में कोई प्रावधान दो व्याख्याओं में सक्षम है तो उस व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो प्रावधान को अमान्य बनाने के बजाय वैध बना देगा।

वह "कुछ समय के लिए अन्य कानून" शब्दों पर भरोसा करते हैं जो सकारात्मक रूप से इंगित करते हैं कि खंड में संविधान पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि संविधान को "कुछ समय के लिए लागू कानून" के रूप में कहना अनुचित होगा। वह कला में आने वाले "कानून" शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है। 2 , 4 , 32 (3) और संविधान की धारा 367 (1) जहाँ इसका अर्थ अधिनियमित विधि होना चाहिए।

एक विधायिका द्वारा। वह एस में "भारतीय कानून" की परिभाषा पर भी निर्भर करता है। 3 (29) सामान्य खंड अधिनियम और प्रस्तुत करता है कि "कानून" शब्द सी. एल. में है। 33 होना चाहिए।

इसका अर्थ है 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के समान एक कानून, अर्थात, अपने विधायी कार्य का प्रयोग करते हुए एक अनुमोदित निजी विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून और संविधान का उल्लेख नहीं कर सकती है। हम केरल राज्य के विद्वान वकील के इस तर्क से खुद को सहमत पाते हैं। हम किसी भी कठिनाई से अवगत नहीं हैं-और न ही हमें कोई परेशानी दिखाई गई है।

सी. एल. के निर्माण में। 33 कला के ओवर राइडिंग प्रावधानों के अधीन एक प्रावधान के रूप में। 226 संविधान का

और प्रश्न संख्या 4 का हमारा उत्तर इसमें होना चाहिए

नकारात्मक।

पूर्वगामी राय के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं

निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में:

प्रश्न संख्या 1: नहीं।

प्रश्न संख्या 2: ((i) हाँ, जहाँ तक एंग्लो-इंडियन का संबंध है।

अनुदान के हकदार शैक्षणिक संस्थान कला. 337 वे चिंतित हैं। ((ii) अन्य अल्पसंख्यकों के संबंध में जो संविधान के किसी भी स्पष्ट प्रावधान के तहत अधिकार के रूप में अनुदान के हकदार नहीं हैं, लेकिन सहायता प्राप्त कर रहे हैं या ऐसी सहायता चाहते हैं और एंग्लो इंडियन शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में भी जहां तक वे अनुच्छेद के तहत उन्हें देय सहायता से अधिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। 337 , खंड 8 (3) और 9 से 13 तक अनुच्छेद का अपमान नहीं करते हैं। 30 (1) लेकिन खंड 3 (5) जहाँ तक वह ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को खंड 14 और 15 के अधीन बनाता है।

कला का अपमान करें। 30 (1) . ((iii) खंड 7 (उपखंडों को छोड़कर। (1) * और (3) जो केवल सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होता है)। 10 में

कला को अपमानित करना। 30 (1) लेकिन सी. एल. 3 (5) जहाँ तक यह शुरू होने के बाद स्थापित नए स्कूलों को बनाता है सी. एल. के अधीन विधेयक। 20 कला का अपमान करता है। 30 (1) .

प्रश्न संख्या 3: नहीं।

प्रश्न संख्या 4: नहीं; खंड 33 अनुच्छेद के अधीन है। 226 संविधान से।

वेंकटरामा अय्यर जे.-मैं सहमत हूँ कि

प्रश्न संख्या 1,3 और 4 का उत्तर इस प्रकार होना चाहिए माई लॉर्ड, मुख्य न्यायाधीश के फैसले में कहा गया है। लेकिन जहां तक प्रश्न संख्या 2 का संबंध है, मैं उसमें व्यक्त किए गए विचार से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि क्ल. (20) विधेयक का, शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होने में है -

अल्पसंख्यक, धार्मिक या भाषाई, कला के प्रतिकूल। 30 (1) संविधान का, और परिणामस्वरूप, उस हद तक शून्य है।

खंड (20) में प्रावधान है कि:

" किसी भी सरकार या विश्वविद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं में किसी भी ट्यूशन के लिए किसी भी छात्र द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होगा।

निजी विद्यालय "। अब सवाल यह है कि क्या यह खंड उस अधिकार का उल्लंघन करता है जो अनुच्छेद है। 30 (1) सभी अल्पसंख्यकों को प्रदान करता है। धर्म या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना। प्रत्यक्षतः, सी. एल. (20) अल्पसंख्यकों द्वारा ऐसी संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन को प्रतिबंधित नहीं करता है;

केवल यह प्रावधान है कि निजी स्कूलों में कोई शुल्क नहीं होगा

प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों द्वारा देय। जिस पर

इसलिए, इस खंड की शर्तों को देखना मुश्किल है कि यह कला को कैसे आहत करता है। 30 (1) . लेकिन अल्पसंख्यकों की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अभ्यास कोई भी स्कूल तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि छात्रों से शुल्क एकत्र नहीं किया जाता है, इसलिए सी. एल. (20) यदि सक्रिय है, तो इसके परिणामस्वरूप शिक्षा समाप्त हो जाएगी

अल्पसंख्यकों की संस्थाएं, और वह एक प्रत्यक्ष आक्रमण था

उन्हें स्थापित करने और बनाए रखने का उनका अधिकार

संस्थाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून निर्णय लेने में

किसी अधिनियम की संवैधानिकता पर, न केवल इसकी भाषा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, बल्कि पक्षों के अधिकारों पर इसके प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, न केवल यह कि यह क्या कहता है, बल्कि यह कि यह क्या करता है। फिर भी, यह देखना मुश्किल है कि एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट कैसे आती है

सी. एल. (20) इसे कला का उल्लंघन कहा जा सकता है। 30 (1) . यह केवल सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होता है, और

आई.

निजी विद्यालय को सी. एल. में परिभाषित किया गया है। 2 (6) "जिसका अर्थ है सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय"। खंड (38) प्रदान करता है

कि -

इस अधिनियम में कुछ भी किसी भी स्कूल पर लागू नहीं होगा।

जो कोई सरकारी या निजी विद्यालय नहीं है।

परिणाम यह है कि जब तक वे राज्य से सहायता या मान्यता नहीं लेते हैं, तब तक अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई, अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और शुल्क लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

यह.

केवल तभी जब वे सहायता या मान्यता के लिए राज्य से मांग करते हैं कि विधेयक के प्रावधान

उन्हें लागू करें।

लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार

अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करेंगे

भ्रमपूर्ण प्रस्तुत किया जाता है, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्र

वे द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते हैं

राज्य या राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए पात्र हों,

संस्थाओं से। तदनुसार यह तर्क दिया जाता है कि कला के तहत अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए। 30 (1) ,

इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख करना आवश्यक है। उन संस्थानों को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान करना।

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे निर्धारित किया जाना है।

यदि अल्पसंख्यकों को अपना अधिकार नहीं है

राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, फिर प्रश्न

चाहे सी. एल. (20) क्या उस अधिकार का आक्रमण नहीं होगा निर्णय के लिए उठें। यह केवल तभी है जब हम मानते हैं कि

अधिकार को कला में निहित किया जाना है। 30 (1) कि आगे

यह उस अधिकार का उल्लंघन करता है। अब, चाहे अल्पसंख्यक हों, धार्मिक हों या भाषाई, उनके लिए मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है

कला के तहत संस्थान। 30 (1) इस पर निर्भर होना चाहिए

उस अनुच्छेद की व्याख्या की जाए। वहाँ है।

राज्य द्वारा मान्यता के बारे में इसमें कुछ भी नहीं

अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान, और

अगर हमें विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करना है

उनके लिए उपस्थित होना; हमें क़ानून में पढ़ना चाहिए

"और यह राज्य का कर्तव्य होगा" जैसे शब्द

ऐसे संस्थानों को मान्यता देना। यह एक नियम है निर्देश ने अच्छी तरह से स्थापित किया कि शब्दों को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट नहीं होना चाहिए

1076

[1959]

एक क़ानून में जोड़ा जाता है जब तक कि उन्हें देने की आवश्यकता न हो

उसमें अन्यथा प्रकट होने वाले अपने इरादे का प्रभाव, और

वह नियम यहाँ सभी अधिक से अधिक बल के साथ लागू होना चाहिए,

यह देखते हुए कि हम जिसकी व्याख्या कर रहे हैं वह एक संविधान है।

अब, के प्रासंगिक प्रावधानों का एक संदर्भ संविधान से पता चलता है कि ऐसा अधिकार निहित नहीं है

कला. 30 (1) . अनुच्छेद 28 (1) में प्रावधान है कि कोई भी धार्मिक

किसी भी शिक्षा में निर्देश प्रदान किया जाएगा। संस्थान का रखरखाव पूरी तरह से राज्य निधि से किया जाता है।

अनुच्छेद 28 (3) अधिनियमित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है।

राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान

या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

धार्मिक शिक्षा में भाग लेना। कला के तहत।

29 (2) , किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य द्वारा अनुरक्षित कोई भी शैक्षणिक संस्थान

कला. 30 (2) , वहाँ स्पष्ट प्रावधान है कि प्रदान करने में सहायता किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए

शैक्षणिक संस्थान इस आधार पर कि यह इसके अधीन है धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का प्रबंधन या

भाषा। उपरोक्त दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि संविधान एक स्पष्ट अंतर बताता है

राज्य-अनुरक्षित, राज्य-सहायता प्राप्त और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के बीच, और उनके संबंध में विभिन्न अधिकारों और दायित्वों का प्रावधान करता है। अगर

इसका उद्देश्य यह था कि कला में उल्लिखित अल्पसंख्यक। 30 (1) राज्य द्वारा उनके शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के मामले में मौलिक अधिकार होना चाहिए, ऐसा कहने से आसान कुछ नहीं होता। दूसरी ओर, यह अनुमान लगाने का अच्छा कारण है कि उसने जानबूझकर राज्य पर ऐसा दायित्व थोपने से परहेज किया है। कला द्वारा संरक्षित शैक्षणिक संस्थान। 30 (1) विशुद्ध रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि

मौलिक अवधारणा जिस पर संविधान है यह तय किया गया कि राज्य चरित्र में धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। यदि केवल धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को राज्य एस. सी. आर. द्वारा मान्यता के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है।

1077

कला के तहत। 30 (1) , अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान कैसे हो सकते हैं?

यह अधिकार किसके पास होना चाहिए? इसकी सामग्री

कला. 30 (1) सभी संस्थानों के संबंध में समान होना चाहिए इसके दायरे में आने वाली स्थितियाँ। इसलिए निर्माण करते हुए,

कला. 30 (1) इसकी भाषा पर, इसका समर्थन करना मुश्किल है

यह निष्कर्ष कि यह मिनो में किसी भी अधिकार का तात्पर्य है

अपने शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने का अधिकार

राज्य द्वारा।

मामला यहीं नहीं रुका है। इसमें है

संविधान एक ऐसा प्रावधान जो स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है

नकारात्मक अधिकार, जिसकी ओर से दावा किया जाता है अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि:

राज्य एक के भीतर प्रदान करने का प्रयास करेगा

इसकी शुरुआत से दस साल की अवधि

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए संविधान चौदह वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चे

बरसों "। यह ठीक यही दायित्व है जो राज्य पर निर्धारित किया गया है

संविधान जिसे सी. एल. में लागू करने की मांग की गई है। (20)

बिल से। अब, यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि अधिकार शिक्षा की स्थापना और रखरखाव के लिए अल्पसंख्यकों की

कला के तहत राष्ट्रीय संस्थान। 30 (1) इसे अपने साथ ले जाएँ

राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त करने का निहित अधिकार, तब नहीं

राज्य का कानून उन्हें छात्रों को प्रवेश देने के लिए मजबूर कर सकता है

भाग IV मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता है। संविधान और उस कला द्वारा गारंटीकृत। 45

लागू नहीं किया जा सकता है ताकि प्रदत्त अधिकारों को पराजित किया जा सके

कला के तहत अल्पसंख्यकों पर। 30 (1) . यह काफी हद तक सही है।

लेकिन यहाँ सवाल यह नहीं है कि क्या कोई निर्देश है।

सिद्धांत मौलिक अधिकार पर हावी हो सकता है, लेकिन क्या अल्पसंख्यकों में कोई मौलिक अधिकार है

उनके शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए

राज्य, और जब इसके बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं है

कला. 30 (1) और यह केवल निहितार्थ है कि इस तरह के एक अधिकार को उठाने की कोशिश की जाती है, यह पूछना उचित है, कर सकते हैं,

हम निहितार्थ से एक ऐसे अधिकार का अनुमान लगाते हैं जो असंगत है 1078

संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के साथ? इसलिए, कला की भाषा पर दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए। 30 (1) और कला में निर्धारित सिद्धांत पर। 45 , मैं खुद को इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ पाता हूं कि अल्पसंख्यकों का अधिकार केवल अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना नहीं है, बल्कि उन्हें राज्य द्वारा मान्यता दिलवाना है। इस प्रश्न को समाप्त करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए।

लेकिन फिर, यह तर्क दिया गया कि इसके पीछे की नीति

कला. 30 (1) यह अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के संस्थानों की स्थापना और रखरखाव में सक्षम बनाने के लिए था, और यह कि यदि राज्य को उन्हें मान्यता देने के दायित्व के तहत नहीं रखा जाता है तो उस नीति को हराया जाएगा।

आ

ओ हम।

मान लीजिए कि नीति के प्रश्न को अधिनियम की भाषा के अलावा भी लिया जा सकता है। लेकिन कला के पीछे की नीति क्या है। 30 (1) ? जैसा कि मैं इसकी कल्पना करता हूं, यह है कि किसी राज्य में अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई, के अधिकारों को नष्ट करने या बाधित करने की शक्ति बहुसंख्यक के पास नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसी नीति है जो सभी आधुनिक संविधानों में व्याप्त है, और इसका उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह सर्वविदित है कि मध्य युग के दौरान स्वीकृत धारणा यह थी कि संप्रभुओं को अपनी प्रजा पर अपना धर्म थोपने का अधिकार था, और जो लोग इसका पालन नहीं करते थे, उनसे गद्दारों के रूप में निपटा जा सकता था। यह धारणा ही थी जो 16 वीं और 17 वीं शताब्दियों के दौरान यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रों के बीच कई युद्धों और गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार थी, और बाद में ही यह माना गया कि धर्म की स्वतंत्रता अच्छे नागरिक जहाज और राज्य के प्रति निष्ठा के साथ असंगत नहीं है, और सभी प्रगतिशील समाजों को अपने अल्पसंख्यकों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। यह वह अवधारणा है जो कला में सन्निहित है। 25 , 26 , 29 और 30. अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से धर्म मानने, पालन करने और मूर्तिपूजक धर्म का समर्थन करने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों की स्थापना और रखरखाव के अधिकार को मान्यता देता है।

अनुच्छेद 29

(1)

धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान। नागरिकों के वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है

अनुच्छेद

30 (1)

अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति। यह कला के समान श्रेणी से संबंधित है।

और अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई, को बिना किसी हस्तक्षेप या बाधा के अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार प्रदान करता है। राज्य से। दूसरे शब्दों में, अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के संबंध में अपना सांस्कृतिक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए और राज्य द्वारा उन्हें जीने की अनुमति दी जानी चाहिए। यही कला के तहत लाए गए अधिकार का वास्तविक दायरा है। 30 (1) , और उसके संबंध में राज्य का दायित्व विशुद्ध रूप से नकारात्मक है। यह प्रो नहीं कर सकता है

इस तरह के संस्थानों की स्थापना को रोकें, और इसे अल्पसंख्यकों द्वारा ऐसे संस्थानों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह अधिकार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, सी. एल. द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। (20) . अल्पसंख्यक अब जिस अधिकार का दावा करते हैं, वह कुछ ऐसा है अधिक। वे न केवल अपने मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता चाहते हैं, बल्कि वे मांग करते हैं कि राज्य को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए और उनके शैक्षणिक संस्थानों को राज्य की मान्यता देनी चाहिए। यह, मेरी राय में, कला के भीतर नहीं है। 30 (1) . उस अनुच्छेद का वास्तविक उद्देश्य अल्पसंख्यकों को इसके साथ लैस करना है

एक ढाल जिसके द्वारा वे बहुसंख्यक, धार्मिक या भाषाई हमलों के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकते हैं, और नहीं

उन्हें एक तलवार से लैस करना जिससे वे बहुमत को रियायत देने के लिए मजबूर कर सकें। होना चाहिए।

इस संबंध में उल्लेख किया गया है कि संविधान ने

कला में शामिल बातों के अलावा अल्पसंख्यकों के संबंध में राज्य पर विभिन्न दायित्व निर्धारित किए गए हैं। 30 (1) .

इस प्रकार, कला। 30 (2) यह प्रावधान करता है कि कोई राज्य, जब वह शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने का विकल्प चुनता है, तो

के आधार पर अल्पसंख्यकों की संस्थाओं के खिलाफ अपराध करना

भाषा या धर्म। इसी तरह, यदि राज्य शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के लिए नियम बनाता है, तो उसे बिना किसी भेदभाव के उन सभी के साथ समान व्यवहार करना होगा।

भाषा या धर्म के आधार पर किसी भी संस्था के खिलाफ। संवैधानिक प्रावधान का परिणाम

इस प्रकार प्रश्न से संबंधित धारणाओं का सारांश दिया जा सकता है।

ऊपर:

(1) राज्य देने के लिए एक सकारात्मक दायित्व के तहत है

सहायता या मान्यता के मामले में सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ समान व्यवहार

अल्पसंख्यक, धार्मिक या भाषाई।

1080

(2) राज्य एक नकारात्मक दायित्व के तहत है

उन संस्थानों के संबंध में, उनकी स्थापना को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं

" प्रलोभन देना या उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करना।

विधेयक का खंड (20) इन दोनों में से किसी का भी उल्लंघन नहीं करता है। दायित्व। दूसरी ओर, यह विवाद है

अल्पसंख्यकों में से जो, यदि स्वीकार किए जाते हैं, तो परिणाम में होना चाहिए

राज्य द्वारा भेदभावः . जबकि। मान्यता प्राप्त संस्थान

बहुसंख्यक समुदायों के राष्ट्र विषय होंगे। को

सी. एल. (20) , कला के दायरे में आने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के समान संस्थान। 30 (1) यह इसके अधीन नहीं होगा। द.

पहला शुल्क एकत्र नहीं कर सकता है, जबकि दूसरा कर सकता है। यह निश्चित रूप से भेदभाव है। यह कहा जा सकता है कि सीखें

ई. डी. अल्पसंख्यकों के लिए परामर्श, जब इस सवाल के साथ दबाया जाता है कि उनके विवाद पर कला। 45 बनना चाहिए।

एक मृत। पत्र, जवाब दिया कि स्थिति हो सकती है

राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों को मुआवजे का भुगतान करना

शुल्क के नुकसान की भरपाई करने के लिए संस्थान। कि

यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि अल्पसंख्यक क्या लड़ते हैं

के लिए जो उन्हें इसके तहत नहीं दिया गया है

कला. 30 (2) संविधान का, '। , ' धर्म या भाषा के आधार पर उनकी सहायता करना। मेरी राय में, वहाँ

कला पहनने का कोई औचित्य नहीं है। 30 (1) एक निर्माण

जो अल्पसंख्यकों को अधिक अनुकूल बनाएगा

बहुसंख्यक समुदायों की तुलना में एड स्थिति।

} मैंने अब तक कला के दायरे पर चर्चा की है। 30 (1) इसके बारे में

भाषा और सिद्धांत पर। इसके अंतर्गत। आ रहा है।

अधिकारियों के बगल में, हमारे सामने उद्धृत, वेधशाला

विन्निपेग बनाम शहर में स्थितियाँ। बैरेट: विनी का शहर

पेग वी। लोगान (1) दिखाई देगा: केरल राज्य के गठन का समर्थन करने के लिए कि सी. एल. (20) कला का अपमान नहीं करता है। 30 (1) . यह एक निर्णय था। 22. में से

मैनिटोबा अधिनियम, 1870, जो इस प्रकार है: " प्रांत में और उसके लिए, उक्त विधायिका विशेष रूप से कर सकती है। शिक्षा, विषय के संबंध में कानून बनाएँ।

और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार:

(1) ऐसे किसी भी कानून में कुछ भी पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं होगा।

डेनोमी के संबंध में किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार को प्रभावित करता है

राष्ट्रीय विद्यालय जो किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के पास हैं

कानून द्वारा। या संघ में प्रांत में अभ्यास करें। ? .....

अब; तथ्य यह है कि मैनिटोबा डेनो में थे

द्वारा संचालित लघु विद्यालय। रोमन कैथोलिक जो

(1) [1892] ए. सी. 445. 457 एस. सी. आर. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

1081

छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस के साथ बनाए रखा गया और चर्च से दान। 1890 में, प्रांतीय l

विधानमंडल ने सार्वजनिक विद्यालय अधिनियम पारित किया, और यह

अधिनियमित किया कि सभी प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक स्कूल

जिले इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होने चाहिए, और यह कि सभी सार्वजनिक विद्यालय नि:शुल्क होने चाहिए।

शिक्षा के लिए विधायी अनुदान का एक हिस्सा था

सार्वजनिक विद्यालयों को आवंटित किया जाए, और यह प्रावधान किया गया था कि

कोई भी स्कूल जो सभी प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं किया जाता है

शिक्षा को सार्वजनिक नहीं माना जाना चाहिए। अधिनियम के अर्थ के भीतर स्कूल और नहीं था

. अनुदान में भाग लेने का अधिकार हो। वैधता

इन प्रावधानों को रोमन द्वारा चुनौती दी गई थी

कैथोलिक संस्थान इस आधार पर कि वे इसका विरोध करते हैं

वेनेड एस। 22 मैनिटोबा अधिनियम का, और के का उल्लंघन किया

उसमें गारंटीकृत अधिकार और विशेषाधिकार। सर्वोच्च

कनाडा के न्यायालय ने इस तर्क को बरकरार रखा; लेकिन यह निर्णय को प्रिवी काउंसिल द्वारा उलट दिया गया था, और यह

एस. 22 मैनिटोबा अधिनियम। लॉर्ड मैकनाघटेन वितरित करते हैं बोर्ड के निर्णय में कहा गया है:

*

*** पब्लिक स्कूल अधिनियम, 1890 के बावजूद,

रोमन कैथोलिक और हर दूसरे धर्म के सदस्य

मैनिटोबा में निकाय के माध्यम से स्कूल स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं

प्रांत के बाहर; वे अपने रखरखाव के लिए स्वतंत्र हैं

स्कूल फीस या स्वैच्छिक सदस्यता के आधार पर; वे

हैं। उनके अनुसार अपने स्कूलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र

स्वयं (छेड़छाड़ या अंतर के बिना धार्मिक सिद्धांत)

*

फेरेंस "।

परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम उल्लंघन नहीं करता है के तहत सांप्रदायिक संस्थानों के अधिकार

कला के तहत अल्पसंख्यक संस्थान। 30 (1) क्या ऐसा नहीं है के रोमन कैथोलिक स्कूलों के समान

एस के तहत मैनिटोबा। 22 1870 के अधिनियम और

सी. एल. द्वारा बनाई गई स्थिति। (20) ठीक यही है कि

1890 उस प्रांत में बनाया गया अधिनियम।

यह आगे बढ़े विवाद पर ध्यान देना बाकी है

श्री प्रिट ने कहा कि जिस आधार पर तर्क दिए गए हैं

अल्पसंख्यकों के वकील ने आगे कहा कि छात्र सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1959]

जो गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण होते हैं, वे सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने या राज्य की सेवाओं में प्रवेश पाने की पात्रता के मामले में नुकसान में होते हैं, वे स्वयं बिना किसी आधार के होते हैं, और यह कि भले ही गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच व्यवहार में कोई महत्वपूर्ण भेदभाव था, जो राज्य में लागू शिक्षा संहिताओं के प्रावधानों का परिणाम था, कि यह हो सकता है कि वे प्रावधान उल्लंघनकारी कला के रूप में खराब हैं। 30 (1) संविधान की, लेकिन इसने सी. एल. की वैधता को प्रभावित नहीं किया। (20) क्योंकि यह सी. एल. के आधार पर गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों पर लागू नहीं था। (38) , और कि, परिणामस्वरूप, विधेयक में कुछ भी नहीं था जो कला को अपमानित करने के लिए कहा जा सकता है। 30 (1) . शिक्षा संहिता के नियम वास्तव में हमारे सामने नहीं हैं, और वे वर्तमान संदर्भ का विषय नहीं हैं। मेरे विचार में, इस तर्क के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है कि यदि कला। 30 (1) इसका बिल्कुल भी उल्लंघन किया गया है, यह शिक्षा संहिता के नियमों द्वारा है न कि सी. एल. द्वारा। (20) . लेकिन इस पहलू को आगे बढ़ाना अनावश्यक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अन्यथा भी, सी. एल. के अधिकार हैं। (20) सवाल करने के लिए खुला नहीं है। मेरे विचार में, यह खंड कला का अपमान नहीं करता है। 30 (1) और इंट्रा वायर्स है।

मैं सहमत हूँ कि सी. एल. एस. (14) और (15) को बुरा माना जाना चाहिए, और मेरे निर्णय का आधार यह है: यह हो सकता है

यह लिया जाना चाहिए-और वास्तव में यह विवादित नहीं है-कि यदि राज्य किसी शैक्षणिक संस्थान को सहायता प्रदान करता है, तो उसे यह देखने की शक्ति होनी चाहिए कि संस्थान ठीक से और कुशलता से चलाया जा रहा है, कि वहां दी जाने वाली शिक्षा सही मानक की है, कि शिक्षकों के पास आवश्यक योग्यताएं हैं, कि धन को संस्थान और इसी तरह के उद्देश्यों के लिए विधिवत लागू किया जाता है। दूसरे शब्दों में, राज्य के पास राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर विनियमन और नियंत्रण की बड़ी शक्तियां होनी चाहिए। इन शक्तियों का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए, और वे क्या होनी चाहिए, इस बारे में विधानमंडल के निर्णय में हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि राज्य की जरूरतों, उसमें व्याप्त बुराइयों की प्रकृति और सीमा और उनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए। लेकिन विनियमन की शक्ति, सामान्य रूप से, एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को नहीं समझती है।

1083

निषेध करने की शक्ति और किसी संस्था के कार्यों को नियंत्रित करने के अधिकार का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि उसे बुझा दिया जाए। अब, सीएलएस। (14) और (15) शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव के लिए निजी एजेंसियों के अधिकार को समाप्त करने के लिए काम करते हैं और ऐसा नहीं किया जा सकता है।

राज्य की विनियमन या नियंत्रण करने की शक्ति के अंतर्गत रखा गया। यदि किसी विद्यालय का कुप्रबंधन किया जाता है तो राज्य निस्संदेह सहायता या मान्यता को रोकने के लिए स्वतंत्र है। यह, एक अंतरिम उपाय के रूप में भी, उस स्कूल को चलाने के लिए छात्रों के हित में व्यवस्था कर सकता है, जब तक कि अन्य शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं। यह उन संपत्तियों को भी फिर से शुरू कर सकता है जिन्हें संस्थानों द्वारा राज्य की सहायता से अधिग्रहित किया गया था।

अनुदान। लेकिन यह स्वयं अनिवार्य रूप से स्कूल को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता है और इसे अपने रूप में नहीं चला सकता है, या तो सी. एल. में निर्धारित शर्तों पर। (14) या सी. एल. (15) . यह ऐसी शक्ति नहीं है जो सीधे सहायता प्रदान करने से उत्पन्न होती है। मदद करने के लिए नहीं

नष्ट करने के लिए। वे खंड, मेरी राय में, संस्थानों को स्थापित करने और बनाए रखने के अधिकार का उल्लंघन करेंगे, चाहे ऐसा अधिकार कला पर आधारित हो। 19 (1) (छ) या कला। 30 (1) .

मुझे यह जोड़ना चाहिए कि प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न

सी. एल की वैधता। (20) या सीएलएस। (14) और (15) को स्पष्ट रूप से हमारी राय के लिए संदर्भित नहीं किया गया है। लेकिन कहा जाता है कि

सी. एल. का संदर्भ। 3 (5) विधेयक के सभी प्रावधानों को आकर्षित करता है, क्योंकि नए संस्थानों या विद्यालयों की स्थापना उस खंड के तहत विधेयक के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। मुझे गंभीर संदेह है कि क्या संदर्भ की शर्तों पर, हमें विधेयक के सभी प्रावधानों की वैधता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। संदर्भ आम तौर पर विधेयक के प्रावधानों के अधिकार पर नहीं होता है। यह निर्दिष्ट प्रावधानों, सी. एल. एस. की वैधता तक सीमित है। 3 (5) , 8 (3) और 9 से 13। इस सवाल का कोई संतोष कारखाना जवाब नहीं है कि अगर यह था तो क्यों इसका आशय यह था कि हमें विधेयक के सभी प्रावधानों की वैधता पर घोषणा करनी चाहिए। 8 (3) और (9) से (13) का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए था। इसके अलावा,

संदर्भ से पहले उनके मन में उठाए गए संदेहों के बारे में विस्तृत पाठ किया जाता है।

राष्ट्रपति ने कुछ प्रावधानों की वैधता के बारे में, और इसमें कोई संकेत नहीं है कि कोई संदेह था

1084 स्पष्ट रूप से उल्लिखित प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों के अधिकारों के संबंध में।

यदि अधिकतम "एक्सप्रेसम"

संघ द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ की व्याख्या करते समय उपकरणों के निर्माण में 'फेसिट सेसेरे टैसिटम' का उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है।

बहुत सावधानी और विचार-विमर्श के साथ सरकार। और कला के तहत सलाहकार न्यायशास्त्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। 143 , संदर्भ को व्यापक रूप से समझने के बजाय संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। लेकिन यह चर्चा अकादमिक है, क्योंकि सभी प्रावधानों की वैधता पर पूर्ण तर्क दिए गए हैं, और हम उस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।

परिणामस्वरूप, प्रश्न संख्या 2 का मेरा उत्तर यह है कि,

सीएलएस को छोड़कर। (14) और (15), विधेयक के अन्य प्रावधान अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करते हैं। 30 (1) संविधान से।

जहाँ तक एंग्लो-इंडियन कम्युनि के स्कूलों का संबंध है

संबंध, कला। 337 उन्हें दी जा रही सहायता का प्रावधान करता है

शर्तों और उसमें निर्दिष्ट सीमा तक।

यह कला से बाहर है। 30 (1) और उससे स्वतंत्र, और

मैं अपने प्रभु, मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूं कि प्रो

विधेयक के दृष्टिकोण इस हद तक हैं कि वे प्रभावित करते हैं या उस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकारों में हस्तक्षेप करना,

बुरा।

संदर्भ ने तदनुसार उत्तर दिया।